दैनिक

आज की जनधारा

सीधी और सच बात, साहस के साथ

डाक पंजीयन 29/2010-2012

वेब संस्करण
www.aajkijandhara.com
www.jandhara.in
Jandhara24x7
@AJandhara/Jandhara24/7
AajkiJandhara & Jandhara24x7
9981126516, 9425203900

तीन राज्यः नई दिल्ली ,मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ 5 संस्करणः नई दिल्ली ,भोपाल, रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर से एक साथ प्रकाशित

RNI.NO.MPHIN/ 25/A3544

वर्ष : 01, अंक : 252, भोपाल, मंगलवार 14 जुलाई 2026, पृष्ठः 12,मूल्यः 2/- aajkijandhara.news aajkijandhara NewsAkj अषाढ़ शुक्ल पक्ष-3, वि.सं. 2083

दतिया का उपचुनाव राजा और रंक के बीच की लड़ाई : मोहन यादव

आशुतोष तिवारी ने भरा नामांकन, भाजपा की शक्ति प्रदर्शन सभा में उमड़ा जनसैलाब

दतिया । दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने सोमवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रदेश प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह और वरिष्ठ नेता डॉ. नरोत्तम मिश्रा की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया। इसके बाद किला चौक पर आयोजित विशाल जनसभा में भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि दतिया का उपचुनाव अब राजा और रंक के बीच की लड़ाई बन गया है। कांग्रेस ने राजपरिवार से उम्मीदवार उतारा है, जबकि भाजपा ने एक सामान्य कार्यकर्ता को मैदान में उतारा है। उन्होंने कहा कि भाजपा विकास और सुशासन के आधार पर चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस जाति और धर्म की राजनीति करती है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि दतिया की जनता भाजपा के विकास मॉडल के साथ खड़ी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक सक्रिय होकर भाजपा को रिकॉर्ड मतों से विजय दिलाने का आह्वान किया। सभा को संबोधित करते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि 20 साल पहले दतिया में तांगे चलते थे, आज हवाई जहाज उतर रहे हैं। यह भाजपा सरकारों के विकास का परिणाम है। उन्होंने कहा कि वह दतिया के हर दरवाजे पर जाकर भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के लिए समर्थन मांगेंगे।

उद्बोधन के बाद भावुक हुए नरोत्तम

सभा के दौरान डॉ. नरोत्तम मिश्रा अपने संबोधन के अंत में भावुक नजर आए। दतिया और यहां के लोगों से अपने लंबे जुड़ाव का जिक्र करते हुए उनकी भावनाएं छलक पड़ीं। मंच पर मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका उत्साहवर्धन किया। भाजपा नेताओं ने इसे दतिया की जनता के प्रति उनके आत्मीय संबंध और समर्पण का प्रतीक बताया। भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने जनता से आशीर्वाद मांगते हुए कहा कि वे दतिया की सेवा के लिए जीवन समर्पित करेंगे और क्षेत्र के विकास को नई गति देंगे। नामांकन और जनसभा में बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

ब्रीफ न्यूज

आईईडी विस्फोटः एक जवान बलिदान, 4 घायल

कोहिमा। नगालैंड से एक दुखद खबर सामने आ रही है। जहां चुमौकेदिमा इलाके में आज एक संदिग्ध बम धमाका हुआ। इस हमले में असम राइफल्स के एक जवान देश के लिए बलिदानी हो गए, जबकि चार अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हैं। अधिकारियों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार यह एक संदिग्ध आईईडी ब्लास्ट था।

व्हाट्सएप-टेलीग्राम के लिए तय होंगे नए नियम

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप और टेलीग्राम द्वारा उनके उपयोगकर्ता नाम आधारित मैसेजिंग सुविधाओं पर जारी किए गए नोटिसों पर प्रस्तुत प्रतिक्रियाओं की जांच कर रहा है, अधिकारियों ने संकेत दिया है कि कोई भी नियामक ढांचा सभी प्लेटफॉर्मों पर समान रूप से लागू होगा। सोमवार को एक साइबर सुरक्षा रिपोर्ट के लॉन्च के मौके पर बोलते हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव एस कृष्णन ने कहा कि मंत्रालय को व्हाट्सएप की प्रतिक्रिया मिली थी और कार्रवाई के अगले पाठ्यक्रम पर निर्णय लेने से पहले ही इसकी समीक्षा की जा रही थी।

जून में लगातार छठे महीने महंगाई बढ़ी

नई दिल्ली। आलू-अदरक समेत खाने-पीने की चीजों के दाम फिर बढ़ने से रिटेल महंगाई लगातार छठे महीने बढ़ी है। महंगाई बढ़कर जून में 4.38फीसदी पर पहुंच गई है। जनवरी से लगातार रिटेल महंगाई दर बढ़ रही है। तब यह 2.74फीसदी थी। फूड इन्फ्लेशन जून में बढ़कर 5.32फीसदी पर पहुंच गई है। मई में यह आंकड़ा 4.38फीसदी पर था। जनवरी 2025 के बाद यह पहला मौका है जब महंगाई रिजर्व बैंकके 4फीसदी के मिडपॉइंट टारगेट के पार निकल गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने आज 13 जुलाई को ये आंकड़े जारी किए।

एमपी में 1160 करोड़ का चावल घोटाला

गरीबों के पोषण का अनाज एथेनॉल के नाम पर हुआ गायब

भोपाल। अजब-गजब मध्य प्रदेश में अब एक ऐसा कथित एथेनॉल घोटाला सामने आया है, जिसने पूरे सरकारी तंत्र को हिलाकर रख दिया है। हद यह है कि इस खेल में शामिल घोटालेबाज सरकार से ही भारी सब्सिडी पर चावल खरीदकर वापस उसे नए नाम से सरकार को ही बेच रहे थे। सबसे बड़ी परेशानी और चिंता की बात यह है कि यह कोई सामान्य अनाज नहीं, बल्कि बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पोषण के लिए तैयार किया गया फोर्टिफाइड चावल था। बालाघाट में एक ट्रक की धरपकड़ से शुरू हुआ यह मामला अब करीब 50 लाख क्विंटल सरकारी चावल की हेराफेरी और 1160 करोड़ रुपये के संभावित घोटाले की विस्तृत जांच तक पहुंच गया है।

एक ट्रक की संदिग्ध मौजूदगी ने खोली महाघोटाले की परतेंः इस पूरे कथित घोटाले की शुरुआत 3 जून 2026 को हुई। अधिकारियों को एक गोपनीय सूचना मिली थी कि सरकारी चावल से भरे तीन ट्रक बालाघाट जिले के भारतीय खाद्य निगम के नवेगांव गोदाम से छिंदवाड़ा के बोरगांव स्थित एवीजे एग्रीको प्राइवेट लिमिटेड के एथेनॉल संयंत्र के लिए रवाना हुए थे। इनमें से एक ट्रक, जिसका नंबर सीजी 04 जेडी 3147 था, उसमें 490 बोरी सरकारी चावल लदा था जिसका कुल वजन 242.55 क्विंटल था।

मौसम और भोजन का बहाना बना संदेहास्पदः जांच अधिकारियों ने जब ट्रक के चालक से पूछताछ की, तो उसने दावा किया कि वह सिर्फ भोजन करने अपने घर चला गया था। वहीं दूसरी तरफ राइस मिल के मालिकों ने कहानी गढ़ी कि अचानक बारिश शुरू होने के कारण ट्रक को मिल परिसर के भीतर सुरक्षित खड़ा किया गया था। हालांकि, जांच अधिकारियों को ये दोनों ही जवाब पूरी तरह संदेहास्पद और मनगढ़ंत लगे।

एक ही चावल के लिए सरकार ने कैसे कर दिया दो बार भुगतानः केंद्र सरकार की नीति के तहत पेट्रोल में मिश्रण के लिए एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके लिए सरकारी गोदामों में रखे अतिरिक्त चावल को रियायती दरों पर एथेनॉल निर्माताओं को दिया जाता है।

हम होर्मुज के रखवाले, निगरानी के लिए मिलना चाहिए पैसाः ट्रंप

नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और तेल आपूर्ति को लेकर बड़ा बयान दिया है। फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेगा और इसके बदले उसे पेमेंट दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका लंबे समय से इस अहम समुद्री मार्ग की सुरक्षा में भूमिका निभाता रहा है, इसलिए उसकी इस जिम्मेदारी की भरपाई भी होनी चाहिए। ट्रंप ने ईरान पर निशाना साधते हुए कहा कि वे बहुत बुरे लोग हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका और ईरान के बीच एक समझौता हुआ था, लेकिन ईरान ने उसे तोड़ दिया। ट्रंप ने कहा कि अगर अमेरिका इस महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की सुरक्षा करता है, तो इसके लिए उसे उचित भुगतान मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका इस रणनीतिक समुद्री मार्ग का गार्जियन (संरक्षक) बनेगा, ताकि अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार और तेल आपूर्ति में कोई बाधा न आए।

2020 दिल्ली दंगा मामले में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 दोषी

आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या का मामला, 6 आरोपी बरी

नई दिल्ली। वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान आईबी कर्मी अंकित शर्मा की हत्या के बहुचर्चित मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण कुमार सिंह ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन समेत पांच आरोपितों को दोषी करार दिया, जबकि छह आरोपितों को बरी कर दिया। **कौन हुए दोषी और कौन हुए निर्दोष?:** दोषी ठहराए गए आरोपितों में ताहिर हुसैन, नाजिम, कासिम, जावेद और अनस शामिल हैं। वहीं, हसीन उर्फ मुल्लाजी उर्फ सलमान, समीर खान, फिरोज, गुलफाम, शोएब आलम उर्फ बॉबी और मुंतजिम उर्फ मूसा को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया। दोषी ठहराए गए आरोपितों की सजा पर अदालत अलग से सुनवाई करेगी।

अब शिक्षा में क्रांति का समय : राहुल

सरकार और शिक्षा मंत्री पर लगाए आरोप

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि भारत की शिक्षा व्यवस्था अब बेईमान वसूली का तंत्र बन गई है। उन्होंने कहा कि अब शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने का समय आ गया है। राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज अभियान के तहत छात्रों से अपने दूसरे संवाद से पहले यह बात कही। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मोदी सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने चुप्पी साध ली है। उन्होंने कहा कि दोनों ने जवाबदेही से मुंह मोड़ लिया है। **सोशल मीडिया पोस्ट में राहुल गांधी ने क्या कहा?:** राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की। इसमें उन्होंने लिखा, भ्रष्ट, अन्यायी, पक्षपाती, बेईमानी- ये चार शब्द मेरे नहीं, ये देश के छात्र आज भारत की शिक्षा व्यवस्था के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं।

राममंदिर ट्रस्ट में होगी सीईओ की भर्ती, एसआईटी की रिपोर्ट मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी से रिपोर्ट मांगी; आठों आरोपी 14 दिन और जेल में रहेंगे

अयोध्या। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यूपी, केंद्र सरकार और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया। यूपी सरकार की तरफ से बनाई गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) से अब तक की जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी। कहा कि रिपोर्ट में जांच अधिकारियों के बारे में भी बताएं। कोर्ट ने मामले से जुड़े सीसीटीवी सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि स्टेटस रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश की जाएगी। इस पर कोर्ट ने साफ किया कि रिपोर्ट में स्ढ्ढञ्ज के गठन और उसकी संरचना की पूरी जानकारी होनी चाहिए। कोर्ट ने अगली सुनवाई 20 जुलाई को तय की। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच 4 अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाओं में जांच सीबीआई को सौंपने के अलावा मंदिर में दान के प्रबंधन से जुड़े अलग-अलग विषयों की समीक्षा के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाने की मांग की गई है।

900 साल का भ्रम टूटा, सरस्वती नहीं मां गायत्री की निकली प्रतिमा

धार की धरोहर का सच, वीणा नहीं थी तो खुला राज

अंशुमन खरे

भोपाल । मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खोज ने इतिहास और पुरातत्व जगत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। भोपाल स्थित स्टेट म्यूजियम में वर्षों से देवी सरस्वती की प्रतिमा के रूप में संरक्षित 12वीं सदी की एक दुर्लभ मूर्ति की पहचान अब बदल गई है। नवीन शोध, प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन और अत्याधुनिक 3D डिजिटल तकनीक के आधार पर विशेषज्ञों ने निष्कर्ष निकाला है कि यह प्रतिमा वास्तव में ज्ञान और वेदों की अधिष्ठात्री मां गायत्री की है। इस खोज ने करीब नौ शताब्दियों से चली आ रही एक ऐतिहासिक भ्रांति को समाप्त कर दिया है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित यह प्रतिमा धार जिले से प्राप्त हुई थी। परमार राजवंश की ऐतिहासिक राजधानी रहे धार का मध्यकालीन भारतीय कला और स्थापत्य में विशेष स्थान रहा है। इसी कारण इस प्रतिमा का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व पहले से ही काफी अधिक था। हालांकि लंबे समय तक शोधकर्ताओं और इतिहासकारों ने इसे देवी सरस्वती की प्रतिमा मानकर अध्ययन किया, लेकिन राज्य पुरातत्व निदेशालय द्वारा कराई गई हाई-रिजॉल्यूशन 3D मैपिंग और डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन ने इस धारणा को बदल दिया। विशेषज्ञों के अनुसार इस प्रतिमा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें वीणा नहीं है। भारतीय मूर्तिकला परंपरा में गुप्त काल के बाद निर्मित लगभग सभी सरस्वती प्रतिमाओं में वीणा को प्रमुख पहचान माना जाता है। भोपाल संग्रहालय की इस प्रतिमा में वीणा का पूरी तरह अभाव होने से पुरातत्वविदों को इसकी दोबारा जांच करने की आवश्यकता महसूस हुई। यही बिंदु इस पूरे शोध का आधार बना। राज्य पुरातत्व निदेशालय से जुड़े पुरातत्वविद रमेश यादव के अनुसार प्रतिमा ललितासन मुद्रा में विराजमान है और इसकी चार भुजाएं हैं। इनमें अक्षमाला, कमल तथा वेद स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। प्रतिमा के समीप एक सुंदर हंस भी उकेरा गया है, जिसे ज्ञान और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। यादव का कहना है कि प्रतिमा की संपूर्ण संरचना और इसके सभी प्रतीक शिल्पशास्त्र में वर्णित मां गायत्री के स्वरूप से पूरी तरह मेल खाते हैं। इतिहासकार एवं पुरातत्वविद बी.के. लोखंडे भी इस निष्कर्ष से सहमत हैं। उनका कहना है कि श्रीमद् देवी भागवत पुराण तथा शिल्पशास्त्र में वर्णित विवरणों का अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि यह प्रतिमा मां गायत्री की ही है। उनके अनुसार भारत में मां गायत्री की इतनी प्राचीन प्रतिमाएं अत्यंत दुर्लभ हैं। साथ ही इस कलाकृति में पश्चिमी चालुक्य शैली का प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है, जो परमार राजाओं के समय मध्य भारत की मूर्तिकला में व्यापक रूप से प्रचलित था। विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रतिमा 12वीं सदी की है और संभवतः राजा भोज के शासनकाल में निर्मित हुई थी। परमार शासक राजा भोज कला, साहित्य, शिक्षा और स्थापत्य के बड़े संरक्षक माने जाते हैं।

एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 में लगभग 40 हजार करोड़ के निवेश हुए प्राप्तः मुख्यमंत्री डॉ. यादव

प्राप्त निवेश से 34 हजार से अधिक रोजगार होंगे सृजित

28 हजार 200 करोड़ रुपर से अधिक की विदेशी योजनाएँ धरातल पर हुई साकार

उज्जैन। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 में 51 प्रमुख गतिविधियाँ संपन्न हुई इन गतिविधियों से लगभग 40 हजार करोड़ रुपए का निवेश और 34 हजार से अधिक रोजगार अवसरों का मार्ग प्रशस्त्र हुआ है। एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 की यात्रा में राज्य सरकार ने अपने सभी संकल्पों को पूरा किया है। पिछले 2 टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के माध्यम से प्रदेश को 46 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2025 के बाद से टेक्नोलॉजी क्षेत्र में 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश धरातल पर आया है। इस अवधि में 22 नई औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण और 4 नई परियोजनाओं का भूमि-पूजन किया गया है, जो राज्य सरकार की कार्य गति और आत्मविश्वास का परिचायक है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार को भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 जीसीसी, डेटा सेंटर एवं सेमीकंडक्टर के शुभारंभ अवसर पर संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत अपनी क्षमता, योग्यता और बुद्धिमत्ता के आधार पर विश्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत का गौरवशाली अतीत पूरी दुनिया के सामने है और पिछले 12 वर्षों में भारत ने विश्व के सबसे तेज गति से विकसित होने वाले देशों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में दुनिया को नई दिशा दे रहा है और इस विकास यात्रा में मध्यप्रदेश भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कृषि, खनिज और वनों की पारंपरिक पहचान से आगे बढ़ते हुए प्रदेश आज डिफेंस, ड्रोन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से लेकर फ्यूचर ग्रोइंग सेक्टर तक तेजी से प्रगति कर रहा है। एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 प्रदेश की इसी विकास यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार एआई, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर सहित सभी छोटे एवं बड़े उद्योगों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और सभी उद्योग समूहों को समान रूप से हरसंभव सहयोग प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश साइंस सिटी, एआई, डीप टेक पार्क और डेटा सेंटर सहित विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार एआई सहित सभी क्षेत्रों में नवाचार, अनुसंधान, कौशल विकास और अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल है।यहाँ व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य कर सकता है। मध्यप्रदेश की पहचान भारत रत्न से सम्मानित स्व॰ अटल बिहारी वाजपेयी से भी जुड़ी है, जिन्होंने देश के गौरवशाली अतीत से विश्व को परिचित कराया और संयुक्त राष्ट्र महासभा में राष्ट्रभाषा हिंदी में अपने विचार व्यक्त किए। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी भी उसी गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हिंदी में विश्व को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना के साथ आगे बढ़ते हुए मध्यप्रदेश में सभी क्षेत्रों में विकास की अपार संभावनाएं हैं। एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक और सबसे युवा देश है। देश में प्रगति की असीम संभावनाएं हैं और राज्य सरकार युवाओं की योग्यता एवं क्षमता का पूरा उपयोग सुनिश्चित करते हुए उन्हें पर्याप्त रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

28 हजार 200 करोड़ से अधिक की विदेशी निवेश परियोजनाएँ धरातल पर साकार- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि मध्यप्रदेश में विदेशी निवेश अब केवल एमओयू तक सीमित नहीं रहकर धरातल पर साकार हो रहा है। स्पेन, कनाडा, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जापान, दक्षिण कोरिया, आयरलैंड और इंडो-जर्मन सहयोग सहित 8 देशों की 10 प्रमुख कंपनियों की 28 हजार 200 करोड़ रुपये से अधिक की निवेश परियोजनाएँ प्रदेश में ग्राउंडब्रेकिंग चरण में हैं। इनमें स्पेन की सबमर इंडिया प्रा.लि. द्वारा भोपाल में लगभग 20 हजार करोड़ रुपये (यूएसडी 2 बिलियन डॉलर) के एआई-रेडी डेटा सेंटर की स्थापना, कनाडा की मैक्केन फूड की 3,800 करोड़ रुपये की फूड प्रोसेसिंग इकाई, यूनाइटेड किंगडम की हेलियन (जीएसके) की 3 हजार करोड़ रुपये की फार्मास्यूटिकल्स परियोजना, जापान की टोपान स्पेशियलिटी फिल्म्स की 1,100 करोड़ रुपये की स्पेशियलिटी फिल्म्स इकाई शामिल है। एक हजार करोड़ रुपए से ज्यादा लागत वाली इन परियोजनाओं के साथ अमेरिका टूयर स्पिलट वाटर्स की रिन्यूएबल्स एनर्जी की 500 करोड़ रुपये की नवकरणीय ऊर्जा परियोजना, दक्षिण कोरिया की बू यंग स्कीकॉर्प की 225 करोड़ रुपये की लेदर एवं फुटवियर इकाई और एफीबार की 207 करोड़ रुपये का मेडिकल डिवाइस पार्क, आयरलैंड की फेलिक्स जेनेरिक्स की 134 करोड़ रुपये की फार्मास्यूटिकल्स इकाई, यूनाइटेड किंगडम की क्लिनीसप्लाइज की 127 करोड़ रुपये की मेडिकल डिवाइस पार्क और इंडो-जर्मन सहयोग से टीडब्ल्यूई ओबीटी प्रा.लि. की 126 करोड़ रुपये की टेक्सटाइल इकाई के कार्य भी निरंतर प्रगति पर हैं।

कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग में सैय्यद उस्मान अली को बड़ी जिम्मेदारी, जबलपुर जिले का सह-प्रभारी नियुक्त

आज की जनधारा

भोपाल। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी की सहमति से मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग द्वारा संगठनात्मक विस्तार के तहत विभिन्न जिलों के प्रभारी एवं सह-प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। इसी क्रम में भोपाल अल्पसंख्यक कांग्रेस विभाग के पूर्व शहर जिला अध्यक्ष हाजी सैय्यद उस्मान अली को जबलपुर जिले का सह-प्रभारी नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति संगठन के प्रति उनकी वर्षों की निष्ठा, समर्पण, सक्रियता एवं संगठनात्मक कार्यशैली का सम्मान मानी जा रही है। मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग ने श्री उस्मान अली पर पूर्ण विश्वास व्यक्त करते हुए उम्मीद जताई है कि वे अपने अनुभव, कुशल नेतृत्व और कार्यकताओं के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर जबलपुर जिले में संगठन को और अधिक मजबूत एवं सक्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हाजी सैय्यद उस्मान अली लंबे समय से कांग्रेस संगठन में विभिन्न जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन करते रहे हैं। उनकी संगठनात्मक क्षमता, कार्यकताओं के बीच मजबूत पकड़ और सामाजिक सक्रियता को देखते हुए उन्हें यह महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया है। राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में उनकी नियुक्ति को संगठन की मजबूती की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। उनकी नियुक्ति पर भोपाल के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं, अल्पसंख्यक विभाग के पदाधिकारियों, कार्यकताओं एवं इष्ट मित्रों ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।

सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को अटेंड न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध नोटिस जारी

14 जुलाई से 31 अगस्त तक जिले में चलेगा दस्तक अभियान’

आज की जनधारा

उज्जैन। कलेक्टर श्री रौशन कुमार सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को प्रशासनिक संकुल भवन के सभाकक्ष में समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सिंहस्थ 2028 महापर्व के अंतर्गत चल रहे एवं अन्य नियमित निर्माण कार्यों, जनसुरक्षा व्यवस्थाओं, समयावधि पत्रों, सीएम हेल्पलाइन एवं विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में कलेक्टर श्री सिंह ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि समय-सीमा वाले प्रकरणों का निर्धारित समयावधि के भीतर निराकरण किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भी समयावधि पत्र को लंबित नहीं रखा जाए तथा उनकी नियमित समीक्षा सुनिश्चित की जाए। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों के लंबित समयावधि पत्रों की जानकारी दी तथा उनके निराकरण की कार्ययोजना प्रस्तुत की। कलेक्टर श्री सिंह ने लंबित मामलों पर विस्तृत चर्चा की तथा संबंधित अधिकारियों को त्वरित निराकरण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतकताओं को समय पर राहत उपलब्ध कराई जाए तथा प्रशासनिक कार्यों में तेजी और पारदर्शिता बरती जाए। सीएम हेल्पलाइन शिकायतों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री सिंह ने 50 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों का शत-प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इन शिकायतों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण किया जाए, ताकि शिकायतकर्ता को वास्तविक राहत मिल सके। कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को अटेंड न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध नोटिस जारी किया जाए। भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर श्री सिंह द्वारा किसान कल्याण वर्ष 2026 के सफल क्रियान्वयन के लिए चिन्हित जनकल्याणकारी योजनाओं की विभागवार समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान योजनाओं की प्रगति में तेजी लाने तथा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सभी विभाग प्रमुखों को स्पष्ट निर्देश दिए गए। समीक्षा बैठक में विशेष रूप से संबल योजना पर जोर देते हुए निर्देश दिए गए कि योजना के अंतर्गत सभी पात्र हितग्राहियों का पंजीयन शत-प्रतिशत पूर्ण किया जाए। बैठक में यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि कोई भी पात्र लाभार्थी योजना से वंचित न रहे। उर्वरक वितरण की समीक्षा कर किसानों को आवश्यकता अनुसार समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। बैठक में कलेक्टर श्री सिंह द्वारा कामधेनु योजना के अंतर्गत हितग्राहियों तक योजना का लाभ पहुँचाने में अपेक्षित लक्ष्य के विरुद्ध आशानुरूप प्रदर्शन नहीं पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की गई।

तराना में 15 से 17 जुलाई तक होगा भव्य ‘नानी बाई रो मायरो’ का आयोजन

आज की जनधारा

तराना/उज्जैन। नगर के श्री कृपा गार्डन (महालोक डिपो के पीछे) में 15, 16 एवं 17 जुलाई 2026 को भव्य धार्मिक आयोजन ह्यनानी बाई रो मायरोह्व कथा का आयोजन किया जाएगा। कथा का वाचन परम पूज्य गोवत्स श्री राधाकृष्णजी महाराज के श्रीमुख से होगा। आयोजन समिति के अनुसार, कथा प्रतिदिन 15 एवं 16 जुलाई को दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक तथा 17 जुलाई को दोपहर 12:00 बजे से 3:00 बजे तक आयोजित की जाएगी। कथा के माध्यम से भगवान श्रीकृष्ण भक्ति, भागवत महिमा एवं भक्त नरसी मेहता के जीवन प्रसंगों का भावपूर्ण वर्णन किया जाएगा। 17 जुलाई (शुक्रवार) को शाम 7:00 बजे से श्री कृपा गार्डन, तराना में विशाल भोजन प्रसादी का आयोजन भी रखा गया है, जिसमें नगरवासियों एवं श्रद्धालुओं से सपरिवार उपस्थित होकर धर्मलाभ लेने का आग्रह किया गया है। आयोजन का संचालन जगदीशचन्द्र राठी एवं समस्त राठी परिवार, तराना द्वारा किया जा रहा है।राठी परिवार द्वारा कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता हैं। नगर में होने वाले धार्मिक कार्यों में भी राठी परिवार द्वारा बढ़चढकर हिस्सा लिया जाता हैं आयोजन समिति ने सभी धर्मप्रेमी श्रद्धालुओं से अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर कथा श्रवण एवं प्रसादी का लाभ लेने की अपील की है।

थाना झारडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गौवंश तस्करी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

आज की जनधारा

उज्जैन। जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने एवं अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से विशेष वाहन चेकिंग एवं अपराधियों की धरपकड़ अभियान निरंतर संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) करण दीप सिंह (भा.पु.से.) एवं एसडीओपी महिदपुर जेडेन लिंगजेरपा (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी झारडा उनि सुरेन्द्र सिंह गरवाल के नेतृत्व में थाना झारडा पुलिस ने गौवंश तस्करी के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर 07 गौवंश सुरक्षित मुक्त कराए तथा घटना में प्रयुक्त दो पिकअप वाहन जब्त किए। 12.07.2026 को थाना झारडा पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम रणायरापीर की ओर से झारडा की तरफ पिकअप वाहनों में गौवंश भरकर अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल काचरिया फंटा, झारडा पर नाकाबंदी कर वाहनों की सघन चेकिंग प्रारंभ की गई। नाकाबंदी के दौरान एक पिकअप वाहन पायलटिंग करते हुए आया, जिसे पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। कुछ ही देर बाद एक अन्य पिकअप वाहन आने पर पुलिस ने उसे घेराबंदी कर रोका। वाहन की तलाशी लेने पर उसमें 07 गौवंश को परिवहन करते पाया गया। पुलिस ने मौके से संजय उर्फ संजू पिता चन्दर, उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम नवादा, थाना उन्हेल, जिला उज्जैन एवं एक विधि-विरुद्ध बालक को अभिरक्षा में लिया। आरोपियों के विरुद्ध पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11(घ) तथा मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4, 6 एवं 9 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी संजय को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर पुलिस रिमांड प्राप्त किया गया है। आपराधिक रिकॉर्ड- प्रारंभिक जांच में आरोपी संजय के विरुद्ध उज्जैन एवं अन्य जिलों में गौवंश तस्करी से संबंधित 05 से अधिक अपराध दर्ज होना पाया गया है। आरोपी के विरुद्ध थाना झारडा, महिदपुर, इंगोरिया, जावरा, ताल एवं उन्हेल में गौवंश तस्करी एवं पशु क्रूरता संबंधी प्रकरण पंजीबद्ध हैं। सराहनीय भूमिका- इस कार्रवाई में थाना प्रभारी उनि सुरेन्द्र सिंह गरवाल, सउनि व्ही.पी. सिंह परिहार, आरक्षक नारायण सिंह कुशवाह, शुभकरण सिंह भदौरिया, मोहर सिंह, अनार सिंह, कन्हैया अहिरवार, जितेन्द्र यादव, जयपाल विश्वकर्मा एवं सैनिक महेन्द्र सिंह की महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका रही।

वर्षा ऋतु में बढ़ते जोड़ों और कमर के दर्द से मिलेगी मुक्तिः अमलतास आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में दो महीने का 'बस्ती उपचार शिविर' शुरू

आज की जनधारा

देवास। आयुर्वेद के अनुसार बारीश के मौसम में मानवी शरीर में कुदरती तौर पर वात दोष में बढ़ोतरी हो जाती है यह बढा हुआ वात दोष शरीर में अनेक तरह की वात की बिमारियाँ उत्पन्न करता है जैसे की जोडों मे दर्द होना, गठियां की बिमारी, पीठ दर्द, कमर दर्द, बदन दर्द, लकवा, अंगों का सुन होना, बद्धकोष्ठता, जुलाब, डिसेंटरी इत्यादी इन सब बिमारीओं से बचने के लिए एक बहुत ही अच्छा चिकित्सा उपचार आयुर्वेद में बताया गया है उस चिकित्सा उपक्रम को ही बस्ती चिकित्सा कहते हैं जिसमे डॉक्टर पेशेंट की गुदा द्वारा औषधी तैल या काढा पेशंट की शरीर के अन्दर छोड़ते हैं यह ट्रीटमेंट दिखने में तो एनिमा जैसी है लेकिन बस्ती की उपयोगिता एनिमा से बहुत कुछ ज्यादा है बस्ती द्वारा शरीर में छोड़े गये औषधीओं की वजह से शरीर में बढे हुए वात दोष से हमें मुक्ती मिलती है और बिमारी ठीक होने में मदद मिलती हैं आयुर्वेद यह मानती है की, शरीर में जब दोष बढ़ता है उसी समय अगर उसका निराकरण होता है तो बिमारी जडसे खत्म होने में मदद मिलती है इसी को चलते, अमलतास आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, बांगर ग्राम, देवास में 10 जुलाई से 10 सितम्बर तक मतलब दो महीने के लिए बस्ती उपचार शिविर का आयोजन किया गया हैं जिन जिन मरीज को ऊपर निर्दिष्ट वात की बिमारिओं की समस्या है वे सब मरीज इस शिविर का लाभ उठाये ऐसा आवाहन हॉस्पिटल प्रबंधन की ओर से किया गया है शिविर में आनेवाले सभी पेशंट्स को थेरपी के चार्जेस पर 20% डिस्काउंट दिया जाएगा शिविर के शुभारंभ पर अमलतास ग्रुप के चेयरमैन मयंकराज सिंह भदौरिया ने अपना संदेश देते हुए कहा–हमारा उद्देश्य क्षेत्र के हर नागरिक को आयुर्वेद की प्राचीन और शुद्धतम चिकित्सा पद्धतियों का लाभ बेहद किफायती दरों पर उपलब्ध कराना है। वर्षा ऋतु में होने वाले वात कष्टों से मुक्ति दिलाने में यह बस्ती शिविर अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। जन-कल्याण के इसी संकल्प के साथ हमने थेरपी शुल्कों में विशेष छूट का प्रावधान भी किया है।

श्रावण-भादौ में महाकाल सवारी की तैयारियां तेज, पुलिस-प्रशासन ने किया संयुक्त सुरक्षा निरीक्षण

उज्जैन। पुलिस आगामी श्रावण-भादौ मास में भगवान श्री महाकालेश्वर की सवारी के दृष्टिगत उज्जैन पुलिस एवं जिला प्रशासन द्वारा सवारी मार्ग का संयुक्त निरीक्षण। आगामी श्रावण-भादौ मास में भगवान श्री महाकालेश्वर की निकलने वाली पारंपरिक सवारियों को सुरक्षित, व्यवस्थित एवं निर्विघ्न रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से आज उज्जैन पुलिस द्वारा जिला प्रशासन एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से सवारी मार्ग का व्यापक निरीक्षण एवं सुरक्षा सर्वेक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अपर कलेक्टर (ADM) यतेंद्र सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर पूर्व) आलोक शर्मा, नगर निगम से अतिरिक्त आयुक्त पवन सिंह, नगर पुलिस अधीक्षक (अनुभाग कोतवाली) दीपक सिंह, थाना प्रभारी महाकाल निरीक्षक गगन बादल, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी (MPEB), लोक निर्माण विभाग (PWD) सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। संयुक्त निरीक्षण के दौरान संपूर्ण सवारी मार्ग का पैदल भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था, कानून-व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण, आपातकालीन निकासी मार्ग, बैरिकेडिंग, प्रकाश व्यवस्था, सीसीटीवी कवरेज, फायर सेफ्टी, पार्किंग व्यवस्था तथा श्रद्धालुओं की सुविधाओं से संबंधित व्यवस्थाओं का बिंदुवार परीक्षण किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर पूर्व) आलोक शर्मा द्वारा निरीक्षण के दौरान सवारी मार्ग पर चल रहे निर्माण एवं मरम्मत कार्यों का अवलोकन करते हुए संबंधित विभागों को समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही मार्ग पर स्थित जर्जर भवनों, विद्युत पोल एवं लटकते विद्युत तारों, क्षतिग्रस्त सड़कों, मार्ग में संभावित अवरोधों तथा अन्य सुरक्षा संबंधी जोखिमों का सूक्ष्म निरीक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त सवारी मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए मार्ग में स्थित खुली नालियों को प्राथमिकता के आधार पर ढकने, श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर में लगे मधुमक्खियों के छत्तों को सुरक्षित रूप से हटाने, तथा मंदिर परिसर एवं आसपास के क्षेत्र में बंदरों की अधिक संख्या के कारण उत्पन्न होने वाली संभावित समस्याओं के निराकरण हेतु संबंधित विभागों को आवश्यक एवं प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

आज की जनधारा
City Dhara
मंगलवार 14 जुलाई 2026. www.aajkijandhara.com

मध्य प्रदेश में गायब हुए लोगों की होगी एफआईआर

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अलर्ट पर सभी पुलिस अधीक्षक

भोपाल। मध्य प्रदेश से गायब 1 लाख 26 हजार लोगों के परिवारों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एमपी पुलिस द्वारा दिए गए आदेश से थोड़ी राहत मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब मध्य प्रदेश पुलिस में नई व्यवस्था लागू की गई है। प्रदेश में अब किसी वयस्क युवक-युवती अचानक गायब होने पर पुलिस को अब उसकी एफआईआर दर्ज करना होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। अभी तक ऐसे मामलों में पुलिस सिर्फ शिकायती

आवेदन लेती थी, इक्का-दुक्का मामलों को छोड़ बाकी में कार्रवाई भी न के बराबर होती थी। मिसिंग पर्सन के मामले में मध्य प्रदेश देश में दूसरे नंबर पर है। प्रदेश में 1 लाख 26 हजार 163 लोग लापता हैं। इनमें 89352 महिलाएं जबकि 36811 पुरुष हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद बदला नियम वयस्कों की गुमशुदगी के मामले में एफआईआर का नियम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लागू हुआ है। दरअसल, जी गणेश बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। तमिलनाडु के जी गणेश की नाबालिग बेटी साल 2011 में लापता हो गई थी। कई जांच के बाद भी बच्ची का पता नहीं चला और पुलिस ने मामले को अनडिटेक्टेबल मानकर केस को बंद कर दिया था। इसके बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सभी गुमशुदा व्यक्तियों चाहे वह महिला हो या पुरुष पर भी लागू कर दी है।

अब क्या होगा

गुमशुदगी के मामले में अब तक अधिकांश मामलों में पुलिस सिर्फ शिकायती आवेदन लेती थी। एफआईआर और गंभीरता आमतौर पर महिलाओं के उन्हीं मामलों में दिखाई देती थी, जिसमें अपहरण या किसी दूसरे अपराध होने का संदेह होता था, लेकिन अब गुमशुदगी के हर मामले में पुलिस को एफआरआई करनी होगी। पीड़ित परिजन के शिकायत लेकर पहुंचने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 140 (3) के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी। हालांकि स्पेशल डीजी महिला अपराध अनिल कुमार के मुताबिक अब वयस्कों की गुमशुदगी के मामलों में अपहरण, मानव दुव्यापार और दूसरे अपराध के तथ्य मिलने पर इससे जुड़ी धाराओं को भी जोड़ा जाएगा। यानी गुमशुदगी के मामले में एफआईआर तो दर्ज होगी, लेकिन इसके बाद पुलिस जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। यदि जांच में ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अपहरण या कोई दूसरे गंभीर अपराध के तथ्य नहीं मिले तो धाराएं नहीं बढ़ेंगी। मध्य प्रदेश से गायब होने वालों के आंकड़े चौंकाने वाले मध्य प्रदेश से बच्चों के गायब होने के अलावा वयस्कों के गायब होने के आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। एनसीआरबी 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक मिसिंग पर्सन के मामले में मध्य प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। साल 2024 में मध्य प्रदेश में 65 हजार 338 लोग गुमशुदा हुए, इसमें युवतियों की संख्या सबसे ज्यादा है। गायब हुई महिलाओं की संख्या 46732 और पुरुषों की संख्या 18 हजार 606 है।

रेड डॉट अभियान को मिलेगा नगर निगम का सहयोग, महापौर से जैन महिला परिषद की चर्चा

भोपाल। अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन महिला परिषद, पद्मावती संभाग के प्रतिनिधिमंडल ने स्वच्छ सुंदर भोपाल अभियान के अंतर्गत रेड डॉट अभियान को प्रभावी बनाने के लिए महापौर श्रीमती मालती राय से सौजन्य भेंट कर विस्तृत चर्चा की। बैठक में परिषद की पदाधिकारियों ने सेनेटरी पैड और डायपर के सुरक्षित निस्तारण को लेकर नगर निगम के सहयोग का आग्रह किया। महापौर श्रीमती मालती राय ने अभियान की सराहना करते हुए नगर निगम की कचरा संग्रहण गाड़ियों में सेनेटरी पैड एवं डायपर के सुरक्षित निस्तारण के लिए पीले डिब्बे लगाने तथा सफाई कर्मचारियों के लिए जागरूकता सेमिनार आयोजित कराने का आश्वासन दिया। परिषद ने बताया कि पद्मावती संभाग की सभी शाखाओं के सामूहिक प्रयासों से जल्द ही भोपाल की महिलाओं और सफाई कर्मचारियों तक रेड डॉट अभियान की जानकारी पहुंचाई जाएगी, जिससे स्वच्छता, सुरक्षा, जागरूकता और सम्मान को बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर केंद्रीय चेयरपर्सन सुनीता जैन, प्रांतीय प्रभारी भारती जैन, केंद्रीय सह मंत्री अनुराधा जैन, समाजसेविका मीना पवैया सहित परिषद की अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहीं।

भोपाल में बनेगा 19 हजार करोड़ का डेटा सेंटर

स्पेन की कंपनी करेगी निवेश; डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा मजबूत

- **यह भूमि 99 साल की लीज पर दी जाएगी। भूमि आवंटन की स्वीकृति 12 जुलाई 2026 को एमपीआईडीसी की ओर से जारी की गई। यह परियोजना मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की जुलाई 2025 में स्पेन यात्रा के दौरान हुए समझौते का परिणाम मानी जा रही है।**

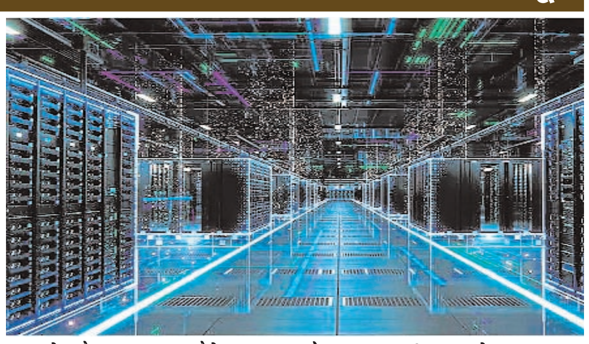

भोपाल। मध्य प्रदेश में विदेशी निवेश अब सिर्फ एमओयू तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि कई बड़े निवेश अब जमीन पर उतरने लगे हैं। इसी कड़ी में स्पेन की कंपनी सबमर टेक्नोलॉजीज भोपाल में करीब 2 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग 19 हजार करोड़) की लागत से अत्याधुनिक डेटा सेंटर स्थापित करेगी। कंपनी को भोपाल के हज्जामपुरा औद्योगिक क्षेत्र में डेटा सेंटर के लिए 60,619.30 वर्गमीटर जमीन आवंटित करने की मंजूरी मिल गई है। यह भूमि 99 साल की लीज पर दी जाएगी। भूमि आवंटन की स्वीकृति 12 जुलाई 2026 को एमपीआईडीसी की ओर से जारी की गई। यह परियोजना मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की जुलाई 2025 में स्पेन यात्रा के दौरान हुए समझौते का परिणाम मानी जा रही है। उस समय बार्सिलोना में सबमर टेक्नोलॉजीज के साथ एआई आधारित 1 गीगावाट क्षमता वाले डेटा सेंटर को लेकर एमओयू हुआ था। सरकार का कहना है कि इस निवेश से प्रदेश का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, नए उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। 28,200 करोड़ रुपये से अधिक के विदेशी निवेश धरातल पर राज्य सरकार के अनुसार, स्पेन, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया और अन्य देशों की 10 बड़ी कंपनियों के 28,200 करोड़ से अधिक के निवेश अब विभिन्न चरणों में जमीन पर उतर रहे हैं। **इन प्रमुख निवेशों में शामिल हैं**- सबमर इंडिया (स्पेन) - 19,000 करोड़, डेटा सेंटर, भोपाल मैककेन फूड्स (कनाडा)- 3,800 करोड़, फूड प्रोसेसिंग, आगर मालवा हेलियॉन/जीएसके (ब्रिटेन) - 3,000 करोड़, फार्मास्यूटिकल्स, पीथमपुर टोपान स्पेशलिटी फिल्म्स (जापान) -1,100 करोड़, पीथमपुर रूपर रिन्यूएबल्स (अमेरिका) -500 करोड़, नर्मदापुरम बू यंग स्कोर्प और एफीबार (दक्षिण कोरिया) सहित अन्य कंपनियों की परियोजनाएं भी क्रियान्वयन के चरण में हैं। सरकार का दावा है कि इन निवेशों से मध्य प्रदेश में वैश्विक कंपनियों का भरोसा बढ़ा है और प्रदेश देश के प्रमुख निवेश केंद्रों में तेजी से अपनी पहचान बना रहा है।

उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल एवं मंत्री नारायण सिंह पंवार ने सोमवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में कार्यकताओं से की मुलाकात

प्रदेश भर से आए कार्यकर्ताओं की जनसमस्याएं सुनकर त्वरित निराकरण के दिए निर्देश

भोपाल। मध्यप्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल एवं मंत्री नारायण सिंह पंवार ने सोमवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश भर से आए पार्टी कार्यकताओं से मुलाकात कर उनकी जनसमस्याओं को सुना। मध्यप्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल एवं मंत्री नारायण सिंह पंवार ने कार्यकताओं द्वारा रखी गई जनसमस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जिन मामलों का तत्काल समाधान संभव नहीं हो सका, उन्हें संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई एवं शीघ्र निराकरण के लिए प्रेषित किया गया। उन्होंने कार्यकताओं को आश्वस्त किया कि सभी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र समाधान सुनिश्चित कराया जाएगा।

नया वेदर सिस्टम मचाएगा हाहाकार

आने वाला है महामानसून...मौसम विभाग की भविष्यवाणी

भोपाल। मध्य प्रदेश में इस बार मानसून भले लेट आया है, लेकिन पूरा मध्य प्रदेश को भिगा डाला है। अब तक मध्य प्रदेश में बारिश का 25 प्रतिशत कोटा पूरा हो चुका है। कई जिलों में नदी नाले उफान पर पहुंच गए हैं। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, देवास को मानसून ने सबसे ज्यादा भिगोया है। यहां सामान्य से 125 प्रतिशत ज्यादा पानी गिर चुका है। हालांकि 2 दिन से बारिश में तेजी नहीं देखी गई। मौसम विभाग का कहना है कि एक वीक बाद नया वेदर सिस्टम एक्टिव होने पर फिर से मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की। भोपाल में सुबह से बादल छाए हुए हैं, बारिश का कोई नामोनिशान नजर नहीं आ रहा। धूप भी नदारद है। शनिवार-रविवार को भी भोपाल बिलकुल नहीं भीगा। नर्मदापुरम में जहां कुछ दिन

पहले काफी बारिश हुई थी, लेकिन दो दिन से यहां भी पानी की बूंद नहीं पड़ी। वहीं ग्वालियर में सुबह से धूप और उमस ने लोग जूझते नजर आ रहे हैं। भिंड में हल्के बादल छाए हुए हैं। यहां सुबह 11 बजे तक टेंपरेचर 34 डिग्री पर बना हुआ था। इंदौर और जबलपुर का भी कुछ ऐसा ही हाल है। जहां भी बारिश के छींटे नहीं पड़े, दोनों शहरों में हल्की धूप है। मध्य प्रदेश में 25 प्रतिशत पानी गिरा इस साल मानसून नौ दिन लेट आया था, लेकिन बारिश ने पूरे मध्य प्रदेश को कवर कर लिया। मौसम विभाग के मुताबिक, सूबे में अब तक औसतन 9.4 इंच बारिश हो चुकी है। सीजन के कोटे का 25 प्रतिशत पानी गिर चुका है। कुछ दिन से जो बारिश नहीं हो रही। जिससे तापमान में भी तेजी देखी गई है। लेकिन जो नया वेदर सिस्टम एक्टिव हो रहा है, वह ठप्प पड़े मानसून को रफ्तार देगा।

उमस और गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी

भोपाल। मध्य प्रदेश में मानसून की रफ्तार फिलहाल सुस्त पड़ गई है। जून में अच्छी बारिश के बाद जुलाई का आधा महीना बीतने के बावजूद प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में झमाझम बारिश नहीं हो सकी है। पिछले पांच दिनों से प्रदेश में बारिश की गतिविधियां काफी कमजोर बनी हुई हैं, जिससे उमस और गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मौसम विभाग के अनुसार, फिलहाल प्रदेश में कोई मजबूत मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं है। इसी वजह से अधिकांश जिलों में केवल हल्की बारिश या बूंदाबांदी की ही संभावना जताई गई है। मंगलवार को सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, मैहर, उमरिया सहित करीब 22 जिलों में कहीं-कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है, जबकि अन्य क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। 16 जुलाई से फिर बदलेगा मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 16 जुलाई के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक नया मौसम तंत्र सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से मध्य प्रदेश में मानसून दोबारा गति पकड़ सकता है और कई जिलों में अच्छी बारिश का दौर शुरू होने के आसार हैं।

अब अपील का इंतजार नहीं, 16वें दिन स्वत होगी कार्रवाई

लोक सेवा गारंटी में बड़ा बदलाव, लापरवाह अधिकारियों पर लगेगी पेनाल्टी

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब तय समय-सीमा में नागरिकों को सेवाएं उपलब्ध नहीं कराने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए आवेदक की अपील का इंतजार नहीं किया जाएगा। यदि निर्धारित समय में सेवा नहीं दी जाती है तो समय-सीमा समाप्त होने के 16वें दिन प्रथम और द्वितीय अपील प्राधिकारी स्वतः (सुओ मोटू) संज्ञान लेकर कार्रवाई करेंगे। राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की

गारंटी अधिनियम, 2010 में संशोधन कर इस व्यवस्था को लागू कर दिया है। संशोधित नियमों का 9 जुलाई से गजट नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही प्रभावी हो गया है। सरकार जल्द ही लोक सेवा गारंटी पोर्टल में भी इसके लिए तकनीकी प्रावधान करेगी, जिससे लंबित मामलों की स्वतः निगरानी और कार्रवाई संभव हो सके। अब नहीं टलेगी कार्रवाई अब तक यदि किसी अधिकारी ने समय-सीमा में सेवा नहीं दी, तो कार्रवाई के लिए नागरिक को स्वयं प्रथम और फिर द्वितीय अपील करनी पड़ती थी। कई मामलों में लोग अपील नहीं करते थे, जिससे लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हो पाती थी। नई व्यवस्था के तहत यदि सेवा तय समय में नहीं मिलती है तो 16वें दिन अपीलीय अधिकारी बिना किसी आवेदन के स्वतः रिकॉर्ड मंगाकर मामले की सुनवाई करेंगे और आवश्यक आदेश जारी करेंगे। इसके लिए नागरिक को अलग से दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। लापरवाही पर 500 से 5,000 रुपये तक जुमार्ना संशोधित नियमों के अनुसार यदि द्वितीय अपील प्राधिकारी यह पाता है कि संबंधित अधिकारी ने बिना उचित कारण के सेवा उपलब्ध नहीं कराई, तो उस पर 500 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का एकमुश्त जुमार्ना लगाया जा सकेगा।

न्यूज । ब्रीफ

राम मंदिर दान प्रकरण की न्यायिक जांच की मांग को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन

पचोर। जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह खींची के निर्देशानुसार सोमवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सारंगपुर के पड़ाना मंडलम में कांग्रेस कार्यकताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक के उपरांत मंडलम अध्यक्ष कमल गुर्जर के नेतृत्व में कार्यकताओं ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन ग्राम पंचायत पड़ाना के रोजगार सहायक श्याम पाटीदार को सौंपा। ज्ञापन में अयोध्या स्थित श्रीराम मंदिर में दान एवं चढ़ावे से जुड़े कथित गबन प्रकरण की स्वतंत्र न्यायिक जांच कराने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। साथ ही विभिन्न जनहित से जुड़े मुद्दों पर भी प्रभावी कार्रवाई करने की मांग की गई। मंडलम अध्यक्ष कमल गुर्जर ने कहा कि श्रीराम मंदिर दान प्रकरण में केवल एफआईआर दर्ज कर देना पर्याप्त नहीं है। पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच किसी स्वतंत्र न्यायिक संस्था से कराई जानी चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आए और यदि कोई दोषी हो तो उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनता के हितों और जवाबदेही से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाती रहेगी। ज्ञापन सौंपने के दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता हीरालाल मालवीय, शिल्पी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रामबाबू सेन, बाबू खां मंसूरी, साकिर अंसारी, बापूलाल वर्मा, दिनेश गोस्वामी, हामिद मंसूरी, कमलेश यादव, जगदीश खाती, अनोखी वर्मा, अजीत पठान, बाबूलाल मालवीय सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

नरसिंहगढ़ लूटकांड का खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार; 8.50 लाख रुपये के आभूषण, देशी कट्टा और बाइक बरामद..

दमोह। दमोह पुलिस ने नरसिंहगढ़ चौकी क्षेत्र में हुई लाखों रुपये की सनसनीखेज लूट की वारदात का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटे गए सोने-चांदी के आभूषण, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, एक देशी कट्टा, धारदार कटर सहित करीब 8.50 लाख रुपये की संपत्ति बरामद की है। मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार, 4 जुलाई 2026 की रात चौकी नरसिंहगढ़ अंतर्गत ग्राम सूखी पिपरिया निवासी विजय जैन ने डायल-112 पर सूचना दी थी कि देर रात करीब 1 से 1:30 बजे के बीच चार अज्ञात बदमाश हथियारों से लैस होकर उनके घर में घुस आए। आरोपियों ने परिवार के सदस्यों को बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट की और घर में रखे सोने-चांदी के आभूषण एवं नगदी सहित करीब 12.70 लाख रुपये की संपत्ति लूटकर फरार हो गए थे। घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना दमोह देहात पुलिस एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया। डॉग स्क्वॉड, फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ और साइबर टीम की सहायता से भौतिक एवं तकनीकी साक्ष्य जुटाए गए। जिले और सीमावर्ती क्षेत्रों में नाकाबंदी कराई गई। पुलिस अधीक्षक आनंद कलादगी ने आरोपियों की गिरफ्तारी पर 10 हजार रुपये के इनाम की घोषणा की थी। मामले के खुलासे के लिए करीब 30 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की छह विशेष टीमें गठित की गईं। पुलिस ने जिला एवं आसपास के क्षेत्रों में लगातार दबिश दी और जांच के दौरान करीब 200 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज का विश्लेषण किया। साथ ही कई संदिग्धों से पूछताछ भी की गई। पुलिस अधीक्षक आनंद कलादगी के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुजीत भदौरिया एवं नगर पुलिस अधीक्षक एच.आर. पाण्डेय के मार्गदर्शन में गठित टीम ने मुखबिर तंत्र, तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शंकर यादव एवं राहुल अहिरवार को हिरासत में लेकर पूछताछ की।

अजाक्स के नए कार्यालय के शुभारंभ पर गरिमामय समारोह, सेवानिवृत्त एवं स्थानांतरित अधिकारियों का हुआ सम्मान

आज की जनधारा

राजगढ़। सामाजिक सरोकारों, संगठनात्मक मजबूती और संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता का प्रेरक संदेश रविवार को उस समय देखने को मिला, जब मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति-जनजाति अधिकारी-कर्मचारी संघ अजाक्स जिला राजगढ़ द्वारा पुराने कलेक्टर कार्यालय परिसर में नवस्थापित जिला कार्यालय का विधिवत लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर आयोजित सम्मान, विदाई एवं अभिनंदन समारोह में जिलेभर से पहुंचे अधिकारी-कर्मचारियों और सामाजिक बंधुओं की उल्लेखनीय उपस्थिति ने संगठन की एकजुटता को नई पहचान दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्यप्रदेश शासन के पूर्व अपर मुख्य सचिव एवं सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी जे.एन. कांसोटिया रहे, जबकि अध्यक्षता वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा ने की। विशिष्ट अतिथियों के रूप में इंजीनियर एस.एल. सूर्यवंशी, जिला संरक्षक श्यामबाबू खरे, बसंत सूर्यवंशी, ज्ञानदीप भूवंकर, बनीप्रसाद दोतानिया सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी एवं समाज के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। अतिथियों ने फीता काटकर नवस्थापित कार्यालय का शुभारंभ किया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि यह कार्यालय केवल संगठन के संचालन का केंद्र नहीं होगा, बल्कि शिक्षा, सामाजिक जागरूकता, संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण और समाज के सर्वांगीण विकास के लिए प्रभावी मंच के रूप में कार्य करेगा। उन्होंने युवाओं को संगठन से जोड़कर सामाजिक चेतना को और मजबूत बनाने का भी संदेश दिया। मुख्य अतिथि जे.एन. कांसोटिया ने अपने संबोधन में कहा कि समाज की प्रगति शिक्षा, संगठन और संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूकता से ही संभव है। उन्होंने कहा कि अजाक्स को अधिकारी-कर्मचारियों के हितों के साथ-साथ समाज के वंचित वर्गों तक न्याय और अधिकारों की जानकारी पहुंचाने की दिशा में निरंतर कार्य करना चाहिए। अध्यक्षीय उद्बोधन में संतोष वर्मा ने संगठन की एकता को उसकी सबसे बड़ी पूंजी बताते हुए कहा कि सामाजिक परिवर्तन केवल सामूहिक प्रयासों से ही संभव है। उन्होंने शिक्षा, सामाजिक सहभागिता और सकारात्मक नेतृत्व को समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बताया। समारोह के दौरान सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी जे.एन. कांसोटिया को उनके उत्कृष्ट प्रशासनिक योगदान एवं संगठन के प्रति समर्पण के लिए शाल, श्रीफल और सम्मान-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। वहीं स्थानांतरण पर श्यामबाबू खरे का आत्मीय अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर उनके द्वारा प्रस्तुत ये मेरा राजगढ़ गीत ने समारोह को भावनात्मक बना दिया और उपस्थित लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया। अजाक्स जिलाध्यक्ष जगदीश वर्मा के नेतृत्व में आयोजित इस समारोह को सफल बनाने में कार्यवाहक जिलाध्यक्ष नरेंद्र जाधव, जिला महासचिव प्रशासन दिनेश जोनवाल, कोषाध्यक्ष गोकुल प्रसाद सिंहवाल सहित संगठन के सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने सक्रिय भूमिका निभाई।

18 वर्षों की गौरवशाली यात्रा का उत्सव एमबी कॉन्वेंट विद्यालय के स्थापना दिवस पर प्रतिभाओं का हुआ सम्मान

आज की जनधारा

पचोर। ग्रामीण अंचल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुशासन और संस्कारों की मजबूत नींव रखने वाले एमबी कॉन्वेंट विद्यालय ने अपने स्थापना के 18 वर्ष पूर्ण होने पर भव्य एवं गरिमामय समारोह आयोजित किया। पूरे विद्यालय परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया था, जहां विद्यार्थियों, अभिभावकों, अतिथियों एवं शिक्षकों की उपस्थिति ने कार्यक्रम को उत्सव का स्वरूप प्रदान किया। समारोह में विद्यालय की उपलब्धियों, विद्यार्थियों की प्रतिभा और शिक्षा के प्रति समर्पण की प्रेरक झलक देखने को मिली। कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर विद्यालय के संचालक महेश पटेल, मोहन नागर, जगदीश नागर, एल.एन. नागर, राजेश पटेल, मुख्य अतिथि महेश मालवीय तथा प्राचार्य ओम गौर सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। अतिथियों ने शिक्षा को समाज परिवर्तन का सबसे प्रभावी माध्यम बताते हुए विद्यार्थियों को ईमानदारी, परिश्रम और अनुशासन के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। समारोह के दौरान विद्यार्थियों ने स्थापना दिवस के महत्व पर प्रभावशाली भाषण प्रस्तुत किए। उनकी वाक्पटुता, आत्मविश्वास और मंच संचालन क्षमता ने उपस्थित जनसमुदाय की भरपूर सराहना अर्जित की। कार्यक्रम में विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों ने पूरे वातावरण को उत्साह और ऊर्जा से भर दिया।

15 दिन की पड़ताल के बाद वाहन चोर गिरोह बेनकाब, चोरी की पिकअप रंग-रोगन बदलकर छिपाई थी पहचान

आज की जनधारा

राजगढ़। राजगढ़ जिले में संपत्ति संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाने की दिशा में कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अंतरजिला स्तर पर सक्रिय वाहन चोर गिरोह का पदार्फाश करते हुए चार शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई एक पिकअप वाहन बरामद की गई है, जिसकी कीमत करीब दो लाख रुपये बताई जा रही है। मामले में एक आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। पुलिस के अनुसार ग्राम सालपुरा निवासी कन्हैयालाल तंवर ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 24-25 जून की रात उसके घर के सामने खड़ी पिकअप वाहन क्रमांक एमपी-39-जी-2160 अज्ञात बदमाश चोरी कर ले गए। शिकायत के आधार पर कोतवाली थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस अधीक्षक अमित तोलानी के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के.एल. बंजारे के मार्गदर्शन तथा एसडीओपी अरविंद सिंह राठौर के नेतृत्व में थाना प्रभारी निरीक्षक मंजू मखेनिया के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। टीम ने करीब 15 दिनों तक लगातार तकनीकी एवं भौतिक साक्ष्यों के आधार पर जांच की। इस दौरान 400 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई और साइबर सेल की मदद से आरोपियों की गतिविधियों का पता लगाया गया। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने वारदात से पहले घटनास्थल की रेकी कर पूरी योजना तैयार की थी। चोरी के बाद वाहन को कुरावर स्थित एक वेल्डिंग एवं डेंटिंग-पेंटिंग की दुकान पर ले जाकर उसका रंग और बाहरी स्वरूप पूरी तरह बदल दिया गया, ताकि उसकी पहचान छिपाई जा सके और पुलिस को भ्रमित किया जा सके। हालांकि पुलिस ने सटीक तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पूरे षड्यंत्र का खुलासा करते हुए वाहन बरामद कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में सीहोर जिले के इमलिया हसन निवासी मुजाहिद, विदिशा जिले के सिरोंज क्षेत्र निवासी अमित मालवीय तथा कंचनपुर निवासी सुल्तान गुर्जर और रामबाबू गुर्जर शामिल हैं।

सुल्तानिया पंचायत को मिला नया जनप्रतिनिधि, पंचों के बहुमत से राजकुमार वर्मा बने सरपंच

आज की जनधारा

पचोर। ग्राम पंचायत सुल्तानिया में रिक्त हुए सरपंच पद के लिए आयोजित निर्वाचन लोकतांत्रिक गरिमा, पारदर्शिता और अनुशासन का उत्कृष्ट उदाहरण बनकर सामने आया। जनपद पंचायत के निदेशानुसार संपन्न इस निर्वाचन में पंचायत के पंचों ने स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान करते हुए राजकुमार वर्मा को स्पष्ट बहुमत से ग्राम पंचायत का नया सरपंच चुना। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान पूरे परिसर में शांतिपूर्ण माहौल बना रहा तथा प्रशासनिक अधिकारियों की सतत निगरानी में सभी औपचारिकताएं नियमानुसार पूरी कराई गईं। जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के निर्देशन में नियुक्त निर्वाचन अधिकारी बलवीर जाटव ने पंचायत सचिव गजराज सिंह रुहेला, पटवारी लालसिंह भिलाला एवं सहायक सचिव बालचंद बैरागी के सहयोग से नामांकन, मतदान, मतगणना और परिणाम घोषणा की समस्त प्रक्रिया पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराई। सरपंच पद के लिए राजकुमार वर्मा तथा अवंतीबाई पति दिनेश बागरी ने अपना-अपना नामांकन प्रस्तुत किया था। मतदान में कुल 20 पंचों में से 19 पंचों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जबकि एक मत नहीं डाला गया। मतगणना के दौरान राजकुमार वर्मा को 12 मत प्राप्त हुए, जबकि उनकी प्रतिद्वंद्वी अवंतीबाई को 7 मत मिले। इस प्रकार राजकुमार वर्मा ने पांच मतों के अंतर से उल्लेखनीय जीत दर्ज करते हुए सरपंच पद पर अपना दावा मजबूत किया। निर्वाचन अधिकारी ने परिणाम घोषित करते हुए बताया कि नियमानुसार उन्हें जनपद पंचायत द्वारा निर्वाचन प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि पूर्व सरपंच जितेंद्र हाथिया के पद से पृथक होने के बाद यह पद रिक्त हो गया था। रिक्त पद पर नए जनप्रतिनिधि के चयन के लिए जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के निदेशानुसार निर्वाचन कराया गया। पूरी प्रक्रिया में लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करते हुए पंचों ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया और ग्राम पंचायत को नया नेतृत्व प्रदान किया।

निर्वाचन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पचोर थाना प्रभारी शकुंतला बामनिया के नेतृत्व में पुलिस बल की विशेष तैनाती की गई थी। उदनखेड़ी चौकी प्रभारी सहित पुलिस जवानों एवं चौकीदारों ने पूरे समय मुस्तैदी से मोर्चा संभाले रखा। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच मतदान एवं मतगणना शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई और कहीं भी किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। परिणाम घोषित होते ही पंचायत परिसर में उत्साह का वातावरण बन गया। नव निर्वाचित सरपंच राजकुमार वर्मा का समर्थकों, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने पुष्पमालाओं से स्वागत कर मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं देते हुए आशा व्यक्त की कि उनके नेतृत्व में ग्राम पंचायत सुल्तानिया में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी, मूलभूत सुविधाओं का विस्तार होगा तथा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पारदर्शिता और समानता के साथ पहुंचेगा। इस अवसर जनपद सदस्य प्रतिनिधि गिरवर नागर, भाजपा नेता अमृत नागर, कमल नागर, उपसरपंच देवनारायण नागर, जगदीश धाकड़, गिरिराज शर्मा, लक्ष्मीचंद नागर, लाला पटेल, श्रीलाल नागर, बालचंद राठौर, दिनेश खटक, महेश नागर सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

पड़ाना में 15 सीसीटीवी कैमरों से होगी चौबीसों घंटे निगरानी

आज की जनधारा

पचोर। नगर की सुरक्षा व्यवस्था को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में पड़ाना ग्राम पंचायत ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए विभिन्न प्रमुख स्थानों पर 15 सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए हैं। पुलिस द्वारा साइबर अपराधों की रोकथाम और जनसुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के बाद ग्राम पंचायत ने इस पहल को अमलीजामा पहनाया है। हाल ही में सारंगपुर थाना प्रभारी राहुल रघुवंशी एवं पड़ाना चौकी प्रभारी भंवर सिंह भूरिया ने गांव चौपाल के माध्यम से नागरिकों को साइबर अपराधों से बचाव, सतर्कता और सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए प्रेरित किया था। इसी के बाद ग्राम पंचायत ने नगर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का निर्णय लेते हुए प्रमुख चौराहों और मार्गों पर कैमरे स्थापित कर दिए। गांधी चौक, बस स्टैंड, आसारेटा-तलेन मार्ग, साधनखेड़ी रोड, पड़ाना-मऊ बायपास सहित पांच प्रमुख स्थानों पर लगाए गए कैमरे चौबीसों घंटे निगरानी करेंगे। सभी कैमरे रात्रि में भी स्पष्ट दृश्य रिकॉर्ड करने की क्षमता रखते हैं। इनका संचालन ग्राम पंचायत कार्यालय में बनाए गए नियंत्रण कक्ष से किया जाएगा तथा रिकॉर्डिंग लगभग एक माह तक सुरक्षित रखी जाएगी, जिससे किसी भी घटना की जांच में पुलिस को आवश्यक साक्ष्य उपलब्ध हो सकें। नगरवासियों ने ग्राम पंचायत और पुलिस प्रशासन की इस संयुक्त पहल का स्वागत करते हुए इसे समय की मांग बताया है। उनका कहना है कि सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था लागू होने से चोरी, असामाजिक गतिविधियों और अन्य अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगेगा। साथ ही किसी भी संदिग्ध व्यक्ति अथवा वाहन की पहचान करना पहले की तुलना में अधिक आसान होगा।

नन्हे हाथों ने थामा हरियाली का संकल्प, पौधारोपण कर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

आज की जनधारा

ब्यावरा। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सामाजिक संस्था खुशियों का ओटला के तत्वावधान में रविवार को संस्था परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। एक पौधा एक जिंदगी अभियान के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चों ने उत्साह के साथ विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपकर उनके संरक्षण का संकल्प लिया तथा प्रकृति को सुरक्षित रखने का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझते हुए कहा कि पौधों का महत्व केवल हरियाली तक सीमित नहीं है, बल्कि यही भविष्य में स्वच्छ हवा, छायादार वातावरण, फल-फूल और जैव विविधता का आधार बनते हैं। उन्होंने संकल्प व्यक्त किया कि जिस प्रकार परिवार के सदस्य अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, उसी समर्पण भाव से पौधों की नियमित सिंचाई और संरक्षण भी करेंगे ताकि वे बड़े होकर वृक्ष का स्वरूप धारण कर सकें। बच्चों ने पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का संकल्प लेते हुए निर्णय लिया कि विद्यालय आते-जाते समय पानी की बोतलों में बचा हुआ पानी पौधों में डालेंगे और उनकी निरंतर देखभाल करेंगे। इस पहल को सभी ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया। संस्था के संचालक डॉ. सुरजीत सिंह ने कहा कि वर्षा ऋतु पौधारोपण के लिए सबसे अनुकूल समय होती है।

बेटियों की सुरक्षा के दावे बेअसर! पूर्व मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में अनुसूचित जाति छात्रावास का रास्ता कई साल से बंद

आज की जनधारा

बुधनी। मध्य प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा, सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर लगातार बड़े-बड़े दावे करती है। करोड़ों रुपये की योजनाओं का प्रचार किया जाता है, लेकिन बुधनी की एक तस्वीर इन दावों की हकीकत बयां कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के लगभग 20 वर्षों तक विधानसभा क्षेत्र रहे बुधनी में अनुसूचित जाति की छात्राएं आज भी एक सुरक्षित रास्ते के लिए संघर्ष कर रही हैं। मामला शासकीय अनुसूचित जाति सीनियर उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, बुधनी का है, जहां कक्षा 9वीं से 12वीं तक की छात्राएं निवास करती हैं। छात्रावास तक पहुंचने के लिए हाईवे से एप्रोच रोड बनाया गया था, लेकिन पिछले लगभग दो वर्षों से यह मार्ग झाड़ियों, कांटेदार पौधों और बड़े-बड़े पेड़ों से पूरी तरह बंद पड़ा है। हालत यह है कि छात्राएं इस रास्ते का उपयोग नहीं कर पा रही हैं और मजबूरी में उन्हें प्रतिदिन दशहरा ग्राउंड के बीच से होकर छात्रावास तक पहुंचना पड़ता है। यही मैदान राजनीतिक सभाओं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, धार्मिक आयोजनों, मेलों और प्रशासनिक बैठकों का प्रमुख केंद्र है। ऐसे में कार्यक्रमों के दौरान छात्राओं को सैकड़ों लोगों की भीड़ के बीच से गुजरना पड़ता है, जिससे उनकी सुरक्षा, निजता और सम्मान पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि जिस दशहरा ग्राउंड पर समय-समय पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मंत्री, विधायक, सांसद, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी रहती है, उसी मैदान से कुछ दूरी पर स्थित छात्रावास का बंद पड़ा रास्ता किसी जिम्मेदार की नजर में नहीं आया। आखिर दो वर्षों से झाड़ियों से बंद पड़े इस मार्ग को साफ कराने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या अधिकारियों की समीक्षा बैठकों में ऐसी मूलभूत समस्याओं पर चर्चा नहीं होती? क्या जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी केवल लोकार्पण, भूमिपूजन, पौधारोपण और फोटो सेशन तक ही सीमित रह गई है? यदि नहीं, तो फिर अनुसूचित जाति की छात्राओं की इस समस्या को लगातार नजरअंदाज क्यों किया गया? छात्रावास की अधीक्षिका सीमा गढ़वाल ने बताया कि एप्रोच रोड की सफाई और रास्ता चालू कराने के लिए नगर परिषद को पूर्व में लिखित पत्र भेजा जा चुका है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे स्पष्ट है।

ई-अटेंडेंस की तकनीकी खामी से जूझे शिक्षक, समय पर स्कूल पहुंचने के बाद भी नहीं लग सकी डिजिटल उपस्थिति

आज की जनधारा

पचोर। मध्यप्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शासकीय विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति को अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के उद्देश्य से लागू की गई डिजिटल ई-अटेंडेंस व्यवस्था के पहले ही चरण में तकनीकी खामियां सामने आने लगी हैं। एक जुलाई से लागू नए प्रावधान के तहत शिक्षकों के लिए विद्यालय परिसर से ही मोबाइल ऐप के माध्यम से टाइम-इन और टाइम-आउट दर्ज करना अनिवार्य किया गया है, लेकिन सोमवार को सारंगपुर विकासखंड के कई विद्यालयों में शिक्षक घंटों तक उपस्थिति दर्ज कराने के लिए संघर्ष करते रहे। शासकीय सांदीपनि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मऊ में सोमवार सुबह सभी शिक्षक निर्धारित समय पर विद्यालय पहुंच गए, लेकिन अधिकांश की ई-अटेंडेंस दर्ज नहीं हो सकी। विद्यालय में कुल 32 शिक्षकों का स्टाफ है, जिनमें दो शिक्षक अवकाश पर थे। समय पर उपस्थित रहने के बावजूद केवल पांच शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज हो पाई, जबकि शेष शिक्षक करीब दो घंटे तक मोबाइल पर लगातार प्रयास करते रहे। शिक्षकों का कहना है कि ऐप में जियो-टैगिंग की तकनीकी गड़बड़ी के कारण विद्यालय परिसर में मौजूद होने के बावजूद मोबाइल स्क्रीन पर उनकी लोकेशन कई किलोमीटर दूर दिखाई जा रही थी। विभागीय नियमों के अनुसार उपस्थिति दर्ज करने के लिए शिक्षक का विद्यालय से 200 मीटर के दायरे में होना आवश्यक है, लेकिन तकनीकी त्रुटि के कारण यह शर्त पूरी नहीं हो सकी।

रोक हटने के बाद जिले में पदोन्नति की प्रक्रिया प्रारंभ

244 आरक्षक बने प्रधान आरक्षक, 64 अफसरों से छिना कार्यवाहक प्रभार

आज की जनधारा

विदिशा। पुलिस विभाग में पिछले 10 वर्षों से पदोन्नति पर रोक होने के कारण बड़ी संख्या में आरक्षक और प्रधान आरक्षकों की पदोन्नति नहीं हो पा रही थी। पुलिस विभाग द्वारा पदोन्नति प्रक्रिया से रोक हटाते हुए आरक्षक और प्रधान आरक्षकों के पदोन्नति की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। विदिशा पुलिस अधीक्षक द्वारा जिले में 244 आरक्षकों की पदोन्नति के आदेश जारी किए गए। इसके साथ ही वर्ष 2019 से लेकर अब तक जिन आरक्षकों और प्रधान आरक्षकों की पदोन्नति की गई थी, उनका डिमोशन किया गया है। जिले के करीब 64 कार्यवाहक प्रधान आरक्षकों और एएसआई की पदोन्नति को निरस्त कर दिया गया है।

पुलिस विभाग में पिछले 10 वर्षों से पदोन्नति पर रोक लगी हुई थी। जिसके कारण से पुलिस महकमें में पदोन्नति नहीं मिल पा रही थी। जिससे पुलिस विभाग का कार्य भी काफी प्रभावित हो रहा था। कार्य में गति लाने के उद्देश्य को लेकर वर्ष 2019 से अब तक आरक्षकों को पदोन्नति देकर विभाग का कार्य कराया जा रहा था। इस आदेश के जारी होते ही जिन आरक्षकों और प्रधान आरक्षकों की पदोन्नति की गई थी उसे समाप्त कर दिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 2019 से लेकर अब तक जिन आरक्षकों और प्रधान आरक्षकों की पदोन्नति की गई थी, उनके आदेश में स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि उन्हें कार्यवाहक प्रभार सौंपा जा रहा है। इस दौरान न तो उनके वेतन में बढ़ोत्तरी होगी और न ही न्यायालय या अन्य जगह अपील करने की कोई गुंजाइश रहेगी। इन्हें सिर्फ कार्यवाहक प्रभार सौंपा गया था।

11 जुलाई को पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी द्वारा जिले के बड़ी मात्रा में आरक्षकों की पदोन्नति की गई है। जिलेभर के 244 आरक्षकों को प्रधान आरक्षक बनाया गया है और इससे पहले जिन आरक्षकों और प्रधान आरक्षकों को पदोन्नति दी गई थी उनकी पदोन्नति को निरस्त कर दिया गया है और वह जो पहले मूल आरक्षक या प्रधान आरक्षक थे, इस पद पर रहकर कार्य करेंगे। पदोन्नति की सूची जारी होते ही ऐसे कई कर्मचारी सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जिनकी पदोन्नति समाप्त कर दी गई है। हालांकि अभी पुलिस विभाग द्वारा इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि जिन लोगों की वर्ष 2019 से लेकर अब तक पदोन्नति हुई थी उनका क्या होगा और वह किस पद पर रहकर कार्य करेंगे और न ही ऐसे लोगों की संख्या उजागर की गई है।

12 अंक जरूरी

पुलिस विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिन थानों में आरक्षक पदस्थ हैं और उनकी पदोन्नति होना थी। इस पदोन्नति को लेकर थाना प्रभारी द्वारा 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान उनका कार्य कितना सराहनीय रहा उस आधार पर उनके अंक आरक्षक को प्रदान किए गए। जिससे कि आरक्षक की पदोन्नति हो सके। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरक्षकों की पदोन्नति को लेकर पिछले 5 वर्षों का उनका रिकार्ड देखा गया और विभाग के प्रति लगन और कार्य निष्ठा को लेकर अंक दिए गए हैं, जिसके चलते जिले के 244 आरक्षकों को प्रधान आरक्षक बनाया गया है।

64 कार्यवाहक प्रधान आरक्षक और एएसआई के डिमोशन

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विदिशा जिले के 64 प्रधान आरक्षक और एएसआई की पदोन्नति को निरस्त किया गया है, क्योंकि उन्हें वर्ष 2019 से लेकर अब तक कार्यवाहक प्रभार सौंपते हुए पदोन्नति की गई थी, लेकिन पुलिस विभाग द्वारा पदोन्नति से रोक हटाने के बाद आरक्षकों की पदोन्नति की गई है। जिसमें पिछले 6 साल के दौरान जिन लोगों की पदोन्नति हुई थी उन्हें कार्यवाहक प्रभाव से हटाते हुए आरक्षक या जो मूल पद पर पहले कार्य कर रहे थे, इस पद पर रहने के आदेश जारी किए गए हैं। पदोन्नति का आदेश जारी होते ही सोमवार को कई कार्यवाहक प्रधान आरक्षक पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और उनके डिमोशन को लेकर अधिकारियों से मिलने की कोशिश की गई और अपने डिमोशंस को लेकर अधिकारियों के समक्ष अपनी बात रखी। अब आखिर जिन लोगों का डिमोशन हुआ है उन कर्मचारियों का क्या होगा। यह पुलिस अधीक्षक की जांच पड़ताल के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। हालांकि अभी जिले के कितने पुलिस कर्मचारियों का डिमोशन हुआ है यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। जो जानकारी सूत्रों से मिली है उसी के आधार पर डिमोशन हुए कर्मचारियों की संख्या दर्शाई जा रही है।

इनका कहना है

जिन लोगों को कार्य वाहक प्रभार दिया गया था वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। जिले में कितने ऐसे कर्मचारी हैं, इसकी अभी जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल कर्मचारियों की संख्या की जानकारी नहीं है। जांच पड़ताल होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। जिन लोगों को कार्यवाहक प्रभार दिया गया था वह अपने मूल पद पर रहकर कार्य करेंगे। अंकों के आधार पर पदोन्नति की गई है।
-प्रशांत चौबे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विदिशा।

विदिशा पुलिस ने विद्यालय में चलाया विशेष जागरूकता अभियान

आज की जनधारा

विदिशा। पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी के निर्देशन में जिलेभर में सड़क सुरक्षा एवं जनजागरूकता को लेकर लगातार प्रभावी अभियान संचालित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रशांत चौबे एवं एसडीओपी शिखा भलावी के मार्गदर्शन में यातायात प्रभारी गंजबासौदा निरीक्षक एन.एस. सिंह लोधी के नेतृत्व में 13 जुलाई को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्राम उहर तहसील बासौदा में विशेष सड़क सुरक्षा एवं जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में विद्यालय के 200 से अधिक छात्र-छात्राओं एवं स्कूल स्टाफ को सड़क दुर्घटनाओं के कारणों एवं उनसे बचाव के उपायों की विस्तार से जानकारी दी गई। विद्यार्थियों को दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने, चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट लगाने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग न करने, निर्धारित गति सीमा का पालन करने, जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करने, यातायात संकेतों का पालन करने तथा नशे की हालत में वाहन न चलाने जैसे महत्वपूर्ण यातायात नियमों के पालन के लिए प्रेरित किया गया।

अभियान के दौरान छात्र-छात्राओं एवं विद्यालय स्टाफ को राहवीर योजना, कैशलेस उपचार योजना तथा हिट एंड रन पीड़ित प्रतिकर योजना की विस्तृत जानकारी दी गई।

दुर्घटना की स्थिति में घायल व्यक्ति की तत्काल सहायता, उपलब्ध कानूनी प्रावधानों एवं शासन द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं से भी सभी को अवगत कराया गया।

कार्यक्रम में उपस्थित विद्यार्थियों को साइबर अपराधों से बचाव के उपाय बताते हुए ऑनलाइन ठगी से सतर्क रहने की सलाह दी गई। साथ ही नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी देकर नशामुक्त जीवन अपनाने के लिए प्रेरित किया गया।

अवैध रूप से यूरिया-डीएपी का भंडारण और विक्रय करने पर एफआईआर दर्ज

आज की जनधारा

विदिशा। सिरोंज विकासखंड के ग्राम नारायणपुर में उर्वरक के अवैध भंडारण एवं विक्रय के प्रकरण में किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की कार्रवाई के बाद पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम सहित विभिन्न प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज की है।

प्राप्त जानकारी अनुसार, कृषि विकास अधिकारी किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग सिरोंज से वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं उर्वरक निरीक्षक अनुज कुमार धाकड़ द्वारा थाना सिरोंज में लिखित शिकायत प्रस्तुत की गई। शिकायत में बताया गया कि ग्राम नारायणपुर में यूरिया एवं डीएपी उर्वरक का अवैध रूप से भंडारण और विक्रय किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना के आधार पर 12 जुलाई की रात्रि लगभग 9.40 बजे उर्वरक निरीक्षक अनुज कुमार धाकड़ एवं नायब तहसीलदार सिरोंज ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। जांच के दौरान जनक सिंह यादव पिता धीरज सिंह यादव, निवासी ग्राम नारायणपुर, विकासखंड सिरोंज के यहां उर्वरकों का बड़े पैमाने पर भंडारण पाया गया। निरीक्षण के दौरान जनक सिंह से उर्वरक के क्रय-विक्रय संबंधी आवश्यक दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वह वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। जांच में उनके घर के मुख्य द्वार पर खड़ी बोलेरो पिकअप (क्रमांक एमपी 40 जीए 0996) से एचयूआरएल कंपनी की 56 बोरी यूरिया बरामद हुई। इसके अलावा घर के एक कमरे से एनएफएल कंपनी की 291 बोरी यूरिया तथा इफको कंपनी की 17 बोरी डीएपी भी बरामद की गई।

कृषि विभाग के उप संचालक संजय जैन ने बताया कि बरामद सभी उर्वरकों को जब्त कर नियमानुसार मकान मालिक रामबाबू यादव पिता गजराज सिंह यादव के सुपुर्द किया गया। प्रकरण में प्रथम दृष्टया उर्वरक (गुण नियंत्रण) आदेश, 1985, फर्टिलाइजर (मूवमेंट) कंट्रोल आदेश, 1973 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर जनक सिंह यादव के विरुद्ध थाना सिरोंज में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 सहित संबंधित धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ कर दी गई है।

कुआंखेड़ी गांव के पास पुलिया से बाईक सहित गिरा युवक

आज की जनधारा

विदिशा। कुआंखेड़ी के पास गुलाबगंज रोड पर मौजूद पुलिया से एक बाइक सवार गिरकर घायल हो गया है। उसे बेहोशी की हालत में इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। एडिशनल एसपी प्राशांत चौबे ने बताया कि घटना सोमवार दोपहर की बताई गई है। जिसमें बाइक सवार बाइक सहित पुलिया से नीचे पानी और पत्थरों पर गिरकर घायल हुआ है। उसकी पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल उसे होश नहीं आया है। वहीं हादसा होने के कारणों को भी खोजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि युवक की उम्र 35 से 40 वर्ष के बीच की लग रही है। उसके सिर में गंभीर चोट लगी है। बाइक के नंबर एमपी 04 एमजी 2883 के आधार पर पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।

अपने लक्ष्य में समर्पित हो जाइए, दूसरों के दोष अपने आप दिखने बंद हो जाएंगे:मुनि श्री

आज की जनधारा

विदिशा। जीवन का महत्व केवल जीने में नहीं, बल्कि जीने के तरीके में है। एक व्यक्ति किसी प्रकार जीवन व्यतीत कर देता है, जबकि दूसरा प्रत्येक क्षण जीवन का रस लेकर उसे सार्थक बना लेता है। राष्ट्रसंत मुनि श्री 108 प्रमाण सागर महाराज ने सम्यग्दर्शन के उपगूहन अंग की विस्तृत व्याख्या करते हुए यह प्रेरणाप्रद उद्गार व्यक्त किए।

मुनि श्री ने कहा कि जीवन का वास्तविक आनंद आत्मजागरण, आत्मशुद्धि और सद्गुणों के विकास में निहित है। अज्ञानी अपने दोषों और दुर्बलताओं से घिरा रहने के कारण दुःख का पात्र बनता है, जबकि ज्ञानी अपने दोषों का क्षय कर सद्गुणों को आत्मसात करते हुए स्थायी सुख और शांति का अधिकारी बनता है। उन्होंने कहा कि सम्यक दृष्टि की पहचान निरंतर आत्मसुधार का प्रयास है। उपगूहन का वास्तविक अर्थ केवल दूसरों के दोषों को छिपाना नहीं, बल्कि अपनी शुद्ध आत्मा एवं सिद्ध परमात्मा की आराधना में इतना तल्लीन हो जाना है कि परद्रव्य और परदोष स्वतः ही गौण हो जाएँ। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पित होता है, उसकी दृष्टि दूसरों की कमियों पर नहीं जाती। मुनि श्री ने कहा कि हम दूसरों में परिवर्तन नहीं ला सकते, परिवर्तन केवल अपने भीतर ला सकते हैं। इसलिए अपने कार्य से कार्य रखिए, व्यर्थ की बातों और अनावश्यक चर्चाओं से बचिए। जब व्यक्ति निरर्थक चर्चाओं से बचता है, तब अनेक पापों से भी स्वतः बच जाता है।

प्रवचन में मुनि श्री ने चार महत्वपूर्ण सूत्र बताए दोष-दर्शन, दोषारोपण, दोष-स्वीकार और दोष-शोधन। उन्होंने कहा कि आज अधिकांश लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करने के बजाय दूसरों पर आरोप लगाने में लगे रहते हैं। यदि हम निरंतर दूसरों की कमियों पर दृष्टि रखेंगे तो अनजाने में वही दोष अपने भीतर भी भर लेंगे। इसलिए आत्मनिरीक्षण को जीवन का आधार बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज में अधिकांश विवाद इसलिए उत्पन्न होते हैं क्योंकि लोग अपनी भूल स्वीकार करने के बजाय दोष दूसरों पर मढ़ देते हैं। गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि भूल से भी बड़ी भूल अपनी गलती छिपाने के लिए किसी निर्दोष पर आरोप लगाना है। आत्म स्वीकार व्यक्ति को महान बनाता है, जबकि दोषारोपण उसके व्यक्तित्व को कमजोर कर देता है।

इस संदर्भ में मुनि श्री ने एक मार्मिक प्रसंग सुनाया। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति के हाथों मंदिर की एक प्रतिमा अनजाने में टूट गई। अपनी भूल स्वीकार करने के स्थान पर उसने तत्काल माली पर आरोप लगा दिया। जब सीसीटीवी फुटेज देखा गया तो सच्चाई सामने आ गई। तब लोगों ने उससे कहा कि प्रतिमा का टूटना उतनी बड़ी भूल नहीं थी, जितनी बड़ी भूल अपनी गलती छिपाने के लिए एक निर्दोष व्यक्ति पर आरोप लगाना था। इस प्रसंग के माध्यम से मुनि श्री ने संदेश दिया कि सत्य स्वीकार करने का साहस ही चरित्र की वास्तविक शक्ति है।

युवा संवाद में युवाओं ने लिए आत्म निर्भरता-समाज सुधार के संकल्प

आज की जनधारा

विदिशा। प्रज्ञा प्रवाह इकाई विदिशा के युवा आयाम द्वारा महाराणा प्रताप कॉलेज में आज का युवा, कल का भारत विषय पर एक प्रेरणादायक युवा संवाद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता डॉ. शुभम वर्मा ने युवाओं को भारत के गौरवशाली इतिहास, पिछले एक हजार वर्षों के राष्ट्रीय संघर्ष और विकसित भारत के निर्माण में उनकी अहम भूमिका से परिचित कराया। उनके विचारों से प्रभावित होकर उपस्थित युवाओं ने राष्ट्र निर्माण के लिए तीन बड़े संकल्प लिए।

स्टार्टअप सेल की स्थापना (रोजगार व स्वरोजगार)

युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए युवा आयाम प्रमुख राजेश विश्वकर्मा के नेतृत्व और डॉ. शुभम वर्मा के मार्गदर्शन में एक स्टार्टअप सेल का गठन किया जाएगा, जो युवाओं को बिजनेस और स्वरोजगार के लिए प्रेरित करेगा। ऐतिहासिक व सांस्कृतिक धरोहरों को सहेजने के लिए सृजन अध्ययन केंद्र के प्रमुख प्रो. संजय सारस्वत, शोध आयाम प्रमुख डॉ. रमेश ठाकुर और डॉ. शुभम वर्मा के सहयोग से बीजामंडल पर विशेष शोध कार्य करेंगे।

समाज को इस बुराई से बचाने के लिए महाराणा प्रताप अध्ययन केंद्र के प्रमुख यशवंत सिंह राठौर के नेतृत्व में युवाओं द्वारा एक बड़ा नशामुक्ति अभियान चलाया जाएगा। कार्यक्रम में राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अखिल भारतीय स्वर्णकार महासभा एवं लायंस पूर्व अध्यक्ष अरुण कुमार सोनी, प्रोफेसर ओजस्विनी जौहरी और भोपाल से पधारीं प्रज्ञा प्रवाह के महिला आयाम की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉ. पी. शशिकला ने भी युवाओं को संबोधित किया। इस अवसर पर लायन अरुण कुमार सोनी द्वारा युवाओं पर लिखी एक विशेष कविता का पाठ किया गया, जिसकी सभी ने मुक्तकंठ से प्रशंसा की। कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन डॉ. रमेश ठाकुर ने किया। संवाद में लगभग 30 युवाओं ने अपनी सक्रिय सहभागिता दर्ज कराई।

युवा संवाद के समापन के बाद भोपाल से आए केंद्रीय टोली के सदस्यों डॉ. पी. शशिकला, डॉ. अंबुज तिवारी एवं डॉ. उदित कुमार सेंगर ने प्रज्ञा प्रवाह विदिशा द्वारा संचालित 21 अध्ययन केंद्रों एवं 2 शिक्षण केंद्रों के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। अधिकारियों ने विदिशा इकाई के कार्यों पर संतोष व्यक्त करते हुए महिला आयाम प्रमुख डॉ. निशा तिवारी, प्रचार-प्रसार आयाम सह-प्रमुख चंद्रभूषण किरार, शोध आयाम प्रमुख डॉ. रमेश ठाकुर और युवा आयाम प्रमुख राजेश विश्वकर्मा को भविष्य की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया।

लापरवाही पर शोकॉज नोटिस के निर्देश

आज की जनधारा

विदिशा। कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने सोमवार को लंबित आवेदनों एवं सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में उन्होंने विभागवार लंबित मामलों की स्थिति का अवलोकन किया तथा स्पष्ट कहा कि आमजन की शिकायतों के निराकरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा। बैठक के दौरान यह सामने आया कि सीएम हेल्पलाइन के अंतर्गत दर्ज कुछ शिकायतों में निर्धारित समय-सीमा के भीतर संबंधित अधिकारियों द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस पर कलेक्टर श्री गुप्ता ने नाराजगी व्यक्त करते हुए अपर कलेक्टर अनिल कुमार डामोर को ऐसे सभी अधिकारियों के विरुद्ध कारण बताओ (शोकॉज) नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन शासन की प्राथमिकता वाली व्यवस्था है, जिसके माध्यम से नागरिक अपनी समस्याओं के समाधान की अपेक्षा करते हैं। इसलिए सभी अधिकारी शिकायतों का समय-सीमा में तथ्यात्मक, संतोषजनक एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक विभाग नियमित रूप से लंबित प्रकरणों की समीक्षा करे और किसी भी आवेदन को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि समय-सीमा का पालन नहीं करने तथा शिकायतों के निराकरण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही निर्देश दिए कि सभी विभाग लंबित आवेदनों का शीघ्र निराकरण कर शासन की मंशा के अनुरूप पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रशासन सुनिश्चित करें।

ई-20 पेट्रोल नीति तत्काल बंद करने की मांग को लेकर राष्ट्रपति को लिखा पत्र:अवस्थी

आज की जनधारा

विदिशा। जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अरुण अवस्थी ने भारत की राष्ट्रपति को पत्र लिखकर देशभर में लागू ई-20 पेट्रोल नीति को तत्काल प्रभाव से बंद करने की मांग की है। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि यह नीति आम जनता के लिए राहत नहीं, बल्कि आर्थिक बोझ बनती जा रही है और लाखों वाहन मालिक इसकी वजह से परेशान हैं। उन्होंने कहा कि देश का आम नागरिक वर्षों की मेहनत और बचत के बाद एक मोटरसाइकिल या कार खरीदता है। वह अपने परिवार की जरूरतों, बच्चों की पढ़ाई और रोजगार के लिए उसी वाहन पर निर्भर रहता है। यदि किसी सरकारी नीति के कारण वाहन का माइलेज घटे, इंजन पर अतिरिक्त दबाव पड़े और मेंटेनेंस का खर्च बढ़ जाए, तो इसका सीधा असर गरीब और मध्यम वर्ग की जेब पर पड़ता है।

राष्ट्रपति से आग्रह किया कि ई-20 पेट्रोल नीति के प्रभावों की निष्पक्ष और वैज्ञानिक जांच कराई जाए तथा जब तक यह पूरी तरह आम जनता के हित में सिद्ध नहीं हो जाती, तब तक इसे तत्काल प्रभाव से स्थगित या बंद किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार को जनता की आवाज सुननी चाहिए। देश की जनता किसी भी ऐसी नीति को स्वीकार नहीं कर सकती जिससे उसकी गाढ़ी कमाई पर अतिरिक्त बोझ पड़े। लोकतंत्र में जनता का हित सर्वोपरि होना चाहिए और सरकार का पहला दायित्व भी यही है कि वह आम नागरिकों की समस्याओं को समझे और उनका समाधान करे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि राष्ट्रपति इस जनहित के मुद्दे पर गंभीरता से विचार करेंगी और केंद्र सरकार को आम जनता के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु उचित सलाह देंगी।

समीक्षा | विभागों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश

लंबित आवेदनों और विकास कार्यों की व्यापक समीक्षा

आज की जनधारा

विदिशा। कलेक्टर अंशुल गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित साप्ताहिक लंबित आवेदनों की समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों, जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति तथा विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में अधिकारियों को लंबित मामलों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने तथा शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं में निर्धारित समयसीमा के भीतर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में टीएल बैठक के लिए प्रस्तुत की जाने वाली पॉवर प्वाइंट प्रेजेंटेशन (पीपीटी) की तैयारी, मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग, माननीय केंद्रीय मंत्री एवं प्रभारी मंत्री से प्राप्त पत्रों के निराकरण और उनके जवाब की स्थिति की समीक्षा की गई। इसके साथ ही स्कूलों, छात्रावासों एवं आईटीआई में प्रवेश की प्रगति का परीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को शत-प्रतिशत पात्र विद्यार्थियों का प्रवेश सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने बंद पड़ी नल-जल योजनाओं को शीघ्र चालू कराने, पूर्ण हो चुकी योजनाओं के हैंडओवर, विभिन्न विभागों में आवंटन की स्थिति, उचित मूल्य दुकानों पर की गई कार्रवाई तथा राशन कार्ड हितग्राहियों की री-केवाईसी की प्रगति की भी समीक्षा की। छात्रावासवार प्रवेश, घुमक्कड़ सर्वे, राहत राशि वितरण तथा विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय से जुड़े विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में अन्य महत्वपूर्ण विषयों के अंतर्गत जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत किए गए कार्यों की समीक्षा करते हुए वर्षा जल संरक्षण एवं जल स्रोतों के संवर्धन के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। बारिश के दौरान जलभराव की समस्या रोकने के लिए नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व तैयारी सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया।

कलेक्टर ने जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा एक या दो आंगनबाड़ी केंद्रों तथा एक विद्यालय के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की रिपोर्ट की भी समीक्षा की। कृषि वर्ष के अंतर्गत ग्रामवार सर्वे में प्राप्त आवेदनों पर की गई कार्रवाई, नरवाई जलाने की रोकथाम की ग्रामवार योजना तथा खरीफ मौसम में मूंग के स्थान पर उड़द की खेती को प्रोत्साहित करने के प्रयासों की जानकारी ली गई। बैठक में एपीसी बैठक के बिंदुवार पालन प्रतिवेदन, शासकीय भूमि एवं भवनों पर विभागवार अतिक्रमण की स्थिति, अविवादित नामांतरण (180 दिवस), बंटवारा (45 दिवस) एवं सीमांकन (90 दिवस) के लंबित प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को समयसीमा में निराकरण के निर्देश दिए गए। इसके अलावा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत बैंकवार लंबित ऋण प्रकरणों, तहसीलवार लंबित आरआरसी प्रकरणों, जिला स्तरीय समितियों के सदस्यों के प्रभारी मंत्री द्वारा नामांकन की स्थिति तथा जिले में संचालित पौधारोपण अभियान एवं उसके रखरखाव की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने सभी विभागीय अधिकारियों से कहा कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं एवं जनहित से जुड़े मामलों में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। प्रत्येक विभाग लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करे तथा प्रगति की नियमित समीक्षा करते हुए गुणवत्तापूर्ण कार्य संपादित करे।

यातायात व्यवस्था सुधारने सड़क का निरीक्षण, 6 वाहनों पर चालानी कार्रवाई

आज की जनधारा

विदिशा। कलेक्टर अंशुल गुप्ता के निर्देशानुसार सोमवार को डिप्टी कलेक्टर अजय पाठक के नेतृत्व में यातायात पुलिस के संयुक्त समन्वय से विदिशा नगर में स्वामी विवेकानंद चौराहा से शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय तक मुख्य सड़क मार्ग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सड़क पर अनावश्यक रूप से खड़े वाहनों, यातायात बाधाओं तथा आवागमन की स्थिति का जायजा लिया गया। आम नागरिकों और वाहन चालकों की सुविधा तथा यातायात सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सड़क पर अवैध रूप से खड़े वाहनों की जांच की गई। कार्रवाई के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले 6 वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई।

अधिकारियों ने कहा है कि शहर में सुगम एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस प्रकार के निरीक्षण और अभियान नियमित रूप से जारी रहेंगे। साथ ही नागरिकों से अपील की गई कि वे यातायात नियमों का पालन कर प्रशासन के प्रयासों में सहयोगप्रद करें।

बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर छत्तीसगढ़

संपादकीय

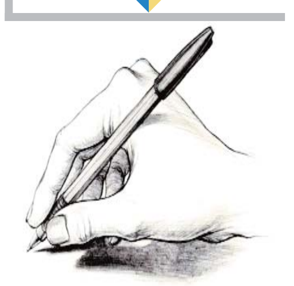

छत्तीसगढ़ राज्य जब वर्ष 2000 में अस्तित्व में आया था, तब यह केवल प्रशासनिक पुनर्गठन नहीं था, बल्कि एक नए विकास मॉडल की शुरुआत थी। छोटे राज्यों के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा तर्क यही था कि छोटे राज्य अपनी स्थानीय आवश्यकताओं को बेहतर समझते हैं और विकास की गति तेज होती है। आज छत्तीसगढ़ उस तर्क की एक महत्वपूर्ण मिसाल बनकर सामने खड़ा है।

राज्य निर्माण के समय स्वास्थ्य सुविधाओं की तस्वीर बहुत सीमित थी। पूरे प्रदेश का भार मुख्यतः रायपुर के एकमात्र बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेज पर था। बस्तर, सरगुजा, कोरिया, जशपुर, दंतेवाड़ा या कबीरधाम जैसे दूरस्थ जिलों के मरीजों को गंभीर बीमारी की स्थिति में सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था। यह केवल इलाज की समस्या नहीं थी, बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच की दूरी भी थी। पिछले पच्चीस वर्षों में इस तस्वीर में बड़ा बदलाव आया है। रायपुर में एम्स की स्थापना हुई, बिलासपुर में सुपर स्पेशलिटी संस्थानों का विकास हुआ।

सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों का विस्तार हुआ। नर्सिंग और डेंटल कॉलेजों की संख्या बढ़ी तथा जिला अस्पतालों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने का प्रयास किया गया। आज प्रदेश में सरकारी और निजी मिलाकर लगभग 15 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं, जिनमें लगभग 2,300 से अधिक एमबीबीएस सीटें उपलब्ध हैं।

अब राज्य सरकार ने दंतेवाड़ा, मनेन्द्रगढ़, जशपुर (कुनकुरी), जांजगीर-चांपा और कबीरधाम में पांच नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इन कॉलेजों को लेकर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) से आवश्यक स्वीकृतियों और मानकों की चुनौतियां भी सामने आई हैं, जिन्हें समयबद्ध ढंग से पूरा करना आवश्यक है।

केवल मेडिकल कॉलेज खोल देना स्वास्थ्य क्रांति नहीं कहलाता। असली चुनौती उन कॉलेजों में योग्य प्रोफेसरों, विशेषज्ञ चिकित्सकों और आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। प्रदेश के अनेक जिला अस्पतालों में हृदय रोग विशेषज्ञ, न्यूरो सर्जन, एनेस्थेटिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट और अन्य विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी बनी हुई है। कई डॉक्टर दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में लंबे समय तक सेवा देने से बचते हैं। सरकार लगातार संविदा नियुक्तियां निकालती है, लेकिन पद अपेक्षित संख्या में नहीं भर पाते। यही कारण है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सबसे बड़ी आवश्यकता केवल भवन निर्माण नहीं, बल्कि मानव संसाधन निर्माण है। डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, लैब टेक्नीशियन और विशेषज्ञ चिकित्सकों की एक मजबूत श्रृंखला तैयार किए बिना स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती।

छत्तीसगढ़ की भौगोलिक परिस्थितियां भी इस चुनौती को और कठिन बनाती हैं। प्रदेश का लगभग 44 प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है और बड़ी आबादी दूरस्थ एवं आदिवासी अंचलों में निवास करती है। ऐसे क्षेत्रों में सड़क, संचार और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किसी भी सरकार के लिए कठिन कार्य रहा है। इसके बावजूद पिछले वर्षों में सड़क संपर्क, एंबुलेंस नेटवर्क, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों तथा टेलीमेडिसिन जैसी व्यवस्थाओं का विस्तार हुआ है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का प्रयास तेज हुआ है।

दरअसल, स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च केवल खर्च नहीं बल्कि सबसे बड़ा निवेश होता है। स्वस्थ नागरिक ही बेहतर शिक्षा प्राप्त करता है, बेहतर रोजगार पैदा करता है और राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देता है। यदि किसी परिवार की आधी आय इलाज में चली जाए तो विकास के सारे दावे खोखले हो जाते हैं।

छत्तीसगढ़ ने उद्योग, कृषि, सड़क, बिजली और सिंचाई के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। अब समय है कि स्वास्थ्य को भी विकास की केंद्रीय धुरी बनाया जाए। नए मेडिकल कॉलेजों के साथ सुपर स्पेशलिटी सेवाएं, मेडिकल रिसर्च, नर्सिंग शिक्षा, डिजिटल हेल्थ और ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था को समान प्राथमिकता दी जानी चाहिए। छोटे राज्य बनने का उद्देश्य केवल नया सचिवालय बनाना नहीं था, बल्कि आम आदमी तक बेहतर शासन पहुंचाना था। यदि दंतेवाड़ा का मरीज इलाज के लिए रायपुर न आए, बल्कि उसे अपने जिले में ही विशेषज्ञ उपचार मिल जाए; यदि जशपुर की बेटी डॉक्टर बनकर अपने जिले में सेवा दे। यदि बस्तर का आदिवासी आधुनिक चिकित्सा और संवेदनशील स्वास्थ्य सेवा दोनों प्राप्त कर सके, तभी राज्य निर्माण का सपना पूर्ण माना जाएगा।

छत्तीसगढ़ ने विकास की लंबी यात्रा तय की है। अब अगला पड़ाव स्पष्ट होना चाहिए, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर छत्तीसगढ़, क्योंकि किसी भी विकसित राज्य की पहचान केवल ऊंची इमारतों से नहीं, बल्कि स्वस्थ नागरिकों से होती है।

मानसून सत्र : सवालों की बारिश, जवाबों की परीक्षा

सुभाष मिश्र

छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र ऐसे समय शुरू हुआ है, जब राज्य की राजनीति कई महत्वपूर्ण मुद्दों के मोड़ पर खड़ी है। एक ओर सरकार अपनी विकास योजनाओं, सुशासन और उपलब्धियों का लेखा-जोखा जनता के सामने रखने को तैयार है, तो दूसरी ओर विपक्ष सरकार के फैसलों, प्रशासनिक कार्यशैली और विभिन्न विवादों को लेकर उसे कठघरे में खड़ा करने की रणनीति बना चुका है। ऐसे में यह सत्र केवल विधायी औपचारिकता नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक जवाबदेही की एक बड़ी परीक्षा है। सत्र की शुरुआत ही राजनीतिक गर्मी के साथ हुई। राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी का मुद्दा पहले ही दिन सदन में गूंजा। यह मामला केवल किसी मंदिर तक सीमित नहीं है, बल्कि आस्था, प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही से भी जुड़ा है। विपक्ष ने इसे सरकार की विफलता के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि सरकार ने तथ्यों के आधार पर अपना पक्ष रखा। लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है कि हर गंभीर प्रश्न का उत्तर सदन में दिया जाए। लेकिन बहस का उद्देश्य केवल राजनीतिक शोर नहीं, बल्कि समाधान होना चाहिए। सत्र से पहले भारतीय जनता पार्टी द्वारा मंत्रियों और विधायकों की बैठक कर विभागवार तैयारी कराने का निर्णय स्वागतयोग्य है। विधानसभा में दिया गया हर उत्तर सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा बनता है। इसलिए तथ्यों के साथ जवाब देना केवल राजनीतिक मजबूरी नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक दायित्व भी है। यदि मंत्री पूरी तैयारी के साथ सदन में उपस्थित होते हैं, तो इससे सरकार की विश्वसनीयता बढ़ती है।

उधर कांग्रेस ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वह इस सत्र में सरकार को कई मुद्दों पर घेरेगी। नकटी क्षेत्र में विधायक आवास निर्माण के लिए हटाए गए अतिक्रमण, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन, शिक्षा व्यवस्था, किसानों, युवाओं, स्वास्थ्य और प्रशासनिक निर्णयों को लेकर विपक्ष आक्रामक रहेगा। विपक्ष की भूमिका केवल विरोध करना नहीं, बल्कि जनहित के प्रश्नों को मजबूती से उठाना है। यदि उसके सवाल तथ्यपरक होंगे, तो सरकार को भी गंभीरता से जवाब देना होगा।

सरकार इस सत्र में बस्तर को अपनी उपलब्धियों के प्रमुख उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर सकती है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा, सड़क, शिक्षा और विकास कार्यों में तेजी तथा मुख्यमंत्री के 'संवाद से समाधान' अभियान के परिणाम निश्चित रूप से चर्चा का विषय बनेंगे। यदि इन पहलों से वास्तव में आम लोगों का जीवन बदला है, तो यह सरकार की उपलब्धि है। लेकिन इन दावों की वास्तविकता की पड़ताल करना विपक्ष का भी दायित्व है।

लोकतंत्र में प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। सैकड़ों प्रश्नों के माध्यम से विधायक अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याएं सदन तक पहुंचाते हैं। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सिंचाई, रोजगार और अधूरी परियोजनाओं जैसे विषय केवल आंकड़े नहीं, बल्कि लाखों लोगों के जीवन से जुड़े प्रश्न हैं। सरकार यदि ईमानदारी से उत्तर देती है और विपक्ष तथ्यपरक ढंग से सवाल उठाता है, तो लोकतंत्र मजबूत होता है।

चिंता की बात तब होती है, जब सदन का बहुमूल्य समय हंगामे और नारेबाजी में नष्ट हो जाता है। लोकतंत्र में विरोध आवश्यक है, लेकिन विरोध का उद्देश्य चर्चा को रोकना नहीं, बल्कि चर्चा को मजबूर करना होना चाहिए। इसी प्रकार सरकार का दायित्व केवल बहुमत के आधार पर निर्णय लेना नहीं, बल्कि विपक्ष के तर्कों को सुनना और उचित सुझावों को स्वीकार करना भी है।

आज जनता पहले से कहीं अधिक जागरूक है। विधानसभा की कार्यवाही अब केवल सदन की चारदीवारी तक सीमित नहीं रहती। डिजिटल माध्यमों और सोशल मीडिया के कारण हर प्रश्न, हर उत्तर और हर व्यवहार जनता के सामने होता है। लोग अब यह भी देखते हैं कि किस विधायक ने अपने क्षेत्र की आवाज उठाई, किस मंत्री ने तथ्यात्मक उत्तर दिया और किसने केवल राजनीतिक प्रदर्शन किया।

यह मानसून सत्र सरकार के लिए अपनी नीतियों और उपलब्धियों की परीक्षा है, तो विपक्ष के लिए अपनी विश्वसनीयता साबित करने का अवसर भी। यदि सरकार पारदर्शिता के साथ जवाब देती है और विपक्ष जिम्मेदारी के साथ सवाल पूछता है, तो लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन यदि पूरा सत्र केवल आरोप-प्रत्यारोप और हंगामे में बीत गया, तो सबसे बड़ा नुकसान जनता का होगा।

विधानसभा किसी सरकार या विपक्ष की नहीं, बल्कि प्रदेश की जनता की संस्था है। वहां उठने वाला हर प्रश्न जनता की उम्मीद का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए इस मानसून सत्र से यही अपेक्षा है कि राजनीतिक तापमान चाहे जितना ऊंचा रहे, लेकिन लोकतांत्रिक मर्यादा, तथ्यपरक बहस और जनहित सर्वोच्च प्राथमिकता बने रहें। आखिर लोकतंत्र की असली ताकत शोर में नहीं, जवाबदेही में होती है।

व्यंग्य

जेबी कफन

सुदर्शन सोनी

'जेबी कफन' है। बीच में 'सी' सीकर इसे 'जेसीबी कफन' कृपया न समझें? कि कस्बे-कस्बे गाँव गाँव इस मशीन के कारण हताश परेशान मजदूरों ने इसे जलाकर सुर्पदे खाक कर दिया। मार्क्स के समय यदि इस मशीन का अविष्कार हो गया होता तो इसका हर जगह यही हश्र होता! नहीं मैं तो एक कहानी सुना रहा हूँ, कफन बेचकर रातोंरात अरबपति बनने वाले एक गंगू नाम के व्यापारी की। यह एक छोटा व्यापारी था, छोटे-मोटे काम करके अपना पेट पालता था और मन ही मन सालता रहता था कि उसके अच्छे दिन आखिर कब आएँगे? वह क्यों नहीं, कार व इक बंगला न्यारा का मालिक हो, हवाई जहाज में विदेश की सैर करे! लेकिन उसके दिन नहीं फिरते थे। अच्छे दिनों के आने की उम्मीद तो वह कई सालों से बाँधे हुए था।

यह गंगू नाम का व्यापारी अपनी दुकान में खाली समय में किताबें, अखबार पढ़ता रहता था। आजकल अखबारों में पाजीटिव समाचार भी आने लगे है! और इनमें ज्यादातर ऐसे रहते कि कैसे किसी गरीब अभावग्रस्त व्यक्ति ने नाम मात्र की पूँजी से शुरू अपने धंधे से करोड़ों अरबो की संपत्ति बना ली या कोई-कोई एप बना कर अरबपति बन गया था, आदि। खाकपति से अरबपति बनने की कहानियाँ पढ़-पढ़कर उसके मन में भी ऐसे ही किसी एक आइडिया के बलबूते अपनी किस्मत चमकाने की इच्छा बलवती होने लगी। लेकिन कुछ खास क्रेक हो नहीं पा रहा था। सोते-जागते, वह यही सोचता कि किसी दिन उसके भी दिन बदलेंगे? और शायद वह अभी तक अड़ी-घड़ी जल्दी ही आने वाली थी!

अवसर तो किसी को यदि कफन ओढ़ाया जा रहा हो तो भी मौजूद रहता है नहीं तो 'जलती चिता में रोटी सेंकने' की कहावत कहाँ से प्रचलन में आई होती। उसके पड़ोस में रहने वाले लालाराम सेठ के प्राण पखेरू दिल के दौरे से पचास की पकी उम्र में ही उड़ गए। बेशुमार दौलत थी उसके पास, कहते हैं कि रोज रात नोट गिनते ही उसे सुबह के चार बज जाते थे! गंगू ने लालाराम से कई बार उधार लिया था। वैसे अब वह खुश था कि लालाराम गयाराम हो गया है तो उससे तकाजा करने कोई नहीं आएगा, लेकिन दूसरे ही पल सोचता कि नहीं किसी का पैसा खाना हराम है! यह सोचते-सोचते वह इस सेठ के द्वारे आ पहुँचा, आखिर वह इस सूदखोर का देनदार तो था ही। सेठ को कफन ओढ़ाया जा रहा था। सेठानी पछाड़ें ले लेकर रो रही थी। और गंगू को इसी समय एक आइडिया क्लिक कर गया कि इतनी बेशुमार दौलत का मालिक साथ में कुछ भी नहीं लेकर जा रहा है! वैसे किसी की शव यात्रा में शामिल होने पर सबसे पहले तो गीता की पंक्तियाँ याद आती है कि तू क्या लाया था, जो लिया यहीं से लिया, क्या ले जा रहा है कुछ नहीं आदि। कारण पीछे केवल एक ही है कि कोई भी कफन जेबयुक्त नहीं होता! नहीं तो कहो वह सब साथ में इस आस में ले जाता कि परलोक में भी ऐशो-आराम में कोई कमी न होने पाए? और शायद इसी कारण मिस्र में राजा महाराजाओं की ममी के साथ उनके दास-दासियाँ, धन-दौलत, भी दफना दिए जाते थे। गंगू लालाराम की शव यात्रा के बाद घर आकर अपने इस धाँसू आइडिया को अमलीजामा पहनाने में लग गया। उसने चार दिन बाद ही अपनी किराने की दुकान बंद कर नए मिले आइडिया से उत्साहित होकर एक कफन बेचने की दुकान शुरू कर दी। कफन की दुकान चल निकली इतनी कि अब उसके पास किताब व अखबार पढ़ने का भी समय नहीं था। उसके कफन में क्या खास बात थी? कफन तो बस एक सफेद कपड़े के टुकड़े के अलावा क्या है? उसने 'जेबी कफन' के नाम से अपने उत्पाद का पेटेंट करा लिया था। उसके पास ऐसे-ऐसे डिजाइन के कफन थे, कि मरने वाला या मरने जा रहा शख्स खुश हो जाए जेब देखकर!, दो जेब वाला, चार जेब वाला, खुफिया जेब वाला, आगे जेब वाला, पीछे जेब वाला। जिप के जेब वाला, बटन के जेब वाला, लंबी जेब वाला, छोटे जेब वाला साथ में बटुआ लटका हुआ वाला। उसकी दुकान में दिन भर तिल रखने को भी जगह नहीं रहती! एक कफन तो ऐसा था कि उसमें हर स्थान पर जेब ही जेब थे। अब वह लाखों कमा रहा था। उसके जेबी कफन पास के देशों में एक्सपोर्ट भी होना शुरू हो गए थे! वह कुछ ही दिनों में शहर का सबसे बड़ा 'कफन एक्सपोर्टर' बन गया था। आखिर जेबी कफन चलते क्यों नहीं देश में करोड़पतियों की संख्या बढ़ रही थी। लोगों में काले धन के कारण संचय की प्रवृत्ति नई ऊँचाई पर थी।

उसने अब जेबी के साथ ही 'डिजायनर कफन' का भी स्टार्ट अप शुरू कर दिया था। चूँकि लोग अब मौत की रस्मों को भी डिजायनर तरीके से पूरी करना चाहते थे! वह पाँच सालों में ही शहर का एक करोड़पति व्यापारी हो गया था। उसके 'जेबी कफन' की चहुँ ओर माँग थीं। लेकिन कभी-कभी उसके मन में एक विचार आता था कि उसे अपने अंतिम समय के लिए जेबी कफन रखना चाहिए कि नहीं। वह उहापोह में था, निर्णय नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब भी वह ऐसा सोचता, तो उसे गीता की वो पंक्तियाँ याद आ जातीं फिर वह सोचता कि भले ही वह सबके लिए जेबी कफन बनाता हो लेकिन खुद बिना जेब वाला ही ओढ़ेगा।

कविता संसार

भूख की मुस्कान

चन्द्रकांत खुंटे 'क्रांति'

फटे बोरे के बिछौने पर जब पसर जाता है
दिनभर का थका-हारा बचपन
तब शुरू होती है एक मूक कहानी
दिनभर की गर्द,कूड़े के ढेरों की बदबू
और नंगे पैरों के छाले सब ओझल हो जाते हैं
नींद की गहरी आगोश में।
अंधेरी, ठंडी झुग्गी में कोई तारा नहीं चमकता
पर अचानक...उस सोए हुए मासूम के होंठ
हलके से फड़कते हैं
एक अलौकिक शांत मुस्कान
चेहरे पर तैर जाती है।
वहाँ कोई परियों का देश नहीं होता
न ही चमचमाती गाड़ियाँ होती हैं
न महँगे खिलौने, न नए कपड़े
वहाँ होती है सिर्फ एक गरम
गोल रोटी जो तवे से अभी-अभी उतरी हो
जिसकी सोंधी महक
उसकी आत्मा को तृप्त कर देती है
तरसते पेट को जब नींद की चादर छुपाती है
तभी बेबस लबों पर
एक अधूरी आस मुस्कुराती है
यकीं मानिए उस मासूम हंसी का
सबब कुछ और नहीं
ख्वाबों के तवे पर बस एक रोटी सिक जाती है।

क्या न्यायपालिका पर घट रहा है जनविश्वास?

महेन्द्र तिवारी

आज के समय में न्यायपालिका केवल संविधान की व्याख्या करने वाली संस्था नहीं है, बल्कि लोकतंत्र में नागरिकों के अंतिम विश्वास का केंद्र भी है। जब कार्यपालिका और विधायिका से किसी व्यक्ति को राहत नहीं मिलती, तब उसकी अंतिम उम्मीद न्यायालय से जुड़ती है। ऐसे में यदि सर्वोच्च न्यायालय के भीतर ही ऐसी घटना घटे जिसमें एक याचिकाकर्ता न्यायाधीशों को ÷ज्यूडिशियल सर्वेंट÷ कहकर संबोधित करे, स्वयं को ÷सॉवरेन÷ घोषित करे, न्यायालय को आदेश देने की भाषा बोले, कागज हवा में उछाल दे और मुख्य न्यायाधीश के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करे, तो यह केवल एक व्यक्ति का अनुचित व्यवहार नहीं रह जाता। यह घटना न्यायपालिका, समाज और लोकतंत्र के संबंधों पर गंभीर प्रश्न भी खड़े करती है। हाल में सर्वोच्च न्यायालय में स्वयं पैरवी कर रहे प्रबल प्रताप द्वारा ऐसा व्यवहार किए जाने के बाद अदालत की कार्यवाही बाधित हुई और सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें बाहर ले जाकर स्थिति को सामान्य किया। यह घटना देशभर में चर्चा का विषय बन गई।

इस घटना को देखने के दो अलग-अलग दृष्टिकोण सामने आते हैं। पहला यह कि यह पूरी तरह से न्यायालय की अवमानना और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन है। दूसरा यह कि यह उस गहरे असंतोष की अभिव्यक्ति है जो वर्षों से लंबित मामलों और न्याय मिलने में होने वाली देरी के कारण समाज के एक वर्ग में पनप रहा है। दोनों दृष्टिकोणों को समझे बिना इस घटना का निष्पक्ष मूल्यांकन संभव नहीं है।

भारतीय न्याय व्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी न्यायिक व्यवस्थाओं में से एक है। देश की अदालतों में करोड़ों मुकदमे लंबित हैं। अनेक मामलों में न्याय पाने में वर्षों नहीं बल्कि दशकों का समय लग जाता है। कई बार मुकदमे की शुरुआत करने वाला व्यक्ति अंतिम निर्णय देखने के लिए जीवित भी नहीं रहता। ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जहां अगली पीढ़ी मुकदमा लड़ती रहती है। यह स्थिति स्वाभाविक रूप से लोगों में निराशा पैदा करती है। प्रसिद्ध कहावत है कि विलंबित न्याय, न्याय से वंचित करने के समान होता है। जब नागरिकों को लगता है कि उनकी समस्याओं का समाधान समय पर नहीं हो रहा, तब व्यवस्था के प्रति उनका विश्वास कमजोर होने लगता है। यही कमजोर होता विश्वास कभी-कभी आक्रोश का रूप भी ले लेता है।

लेकिन क्या यह आक्रोश अदालत के भीतर अनुशासन तोड़ने का अधिकार दे देता है? इसका उत्तर स्पष्ट रूप से नहीं है। लोकतंत्र में असहमति व्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता है। न्यायिक निर्णयों की आलोचना भी की जा सकती है। पुनर्विचार याचिका दायर की जा सकती है।

सिर्फ क्रिकेट नहीं, अब मैदान बड़ा चाहिए!

-प्रभात झा बिलासपुर

138वें नंबर से विश्व कप तक भारतीय फुटबाल का लंबा रास्ता

शाम ढलते ही मणिपुर के एक छोटे से गांव का धूल भरा मैदान अचानक जी उठता है। स्कूल की छुट्टी खत्म होते ही दर्जन भर बच्चे नंगे पांव गेंद के पीछे दौड़ पड़ते हैं। मैदान के किनारे खड़े एक बुजुर्ग के मोबाइल पर अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में चल रहे फीफा विश्व कप 2026 का कोई मैच लाइव चल रहा है। बच्चे बीच-बीच में खेल रोककर स्क्रीन पर झांकते हैं, फिर वापस मैदान में कूद पड़ते हैं—मानो हर पास, हर शॉट में वही सपना बुन रहे हों जो स्क्रीन पर दिख रहा है।

यह दृश्य भारत के फुटबॉल-भविष्य की सबसे सच्ची तस्वीर है। देश में करोड़ों बच्चे यही सपना रोज़ देखते हैं, पर हकीकत कुछ और कहती है। फीफा की ताज़ा रैंकिंग में भारत 138वें स्थान पर खड़ा है—211 सदस्य देशों वाले इस खेल में एक ऐसी जगह, जो हमारी आबादी और जुनून, दोनों के हिसाब से बेमेल लगती है।

पर इस साल एक बदलाव उम्मीद जगाता है। विश्व कप 2026 में टीमों की संख्या 32 से बढ़ाकर 48 कर दी गई है, जिससे एशियाई फुटबॉल परिसंघ का कोटा 4.5 सीधी जगहों से बढ़कर 8.5 हो गया है। मतलब अब एशिया की शीर्ष नौ टीमें सीधे विश्व कप तक पहुंच सकती हैं। यह दरवाज़ा पहले से बड़ा तो हुआ है, पर उसमें दाखिल होने के लिए भारत को अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है।

अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने इसी चुनौती को स्वीकार करते हुए ÷विज़न 2047÷ नाम की योजना शुरू की है—लक्ष्य है, आज़ादी के सौवें वर्ष तक भारत को एशिया की शीर्ष चार फुटबॉल शक्तियों में शामिल करना। यह योजना कागज़ पर जितनी आकर्षक है, ज़मीन पर उतारना उतना ही कठिन भी।

दिलचस्प बात यह है कि भारत के पास एक ऐसा इलाका पहले से मौजूद है, जिसे फुटबॉल की नर्सरी कहा जाता है—पूर्वोत्तर भारत। इंडियन सुपर लीग और राष्ट्रीय टीम में खेलने वाले 40 प्रतिशत से अधिक खिलाड़ी इसी छोटे भौगोलिक क्षेत्र से आते हैं। मणिपुर, मिज़ोरम और असम के गांव-गांव में फुटबॉल केवल खेल नहीं, पारिवारिक स्वीकृति का हिस्सा है—यहां किसी बच्चे का फुटबॉलर बनना उतना ही सामान्य माना जाता है जितना डॉक्टर या इंजीनियर बनना। यही वह सबक है जो बाकी भारत को अभी सीखना बाकी है। सफलता केवल प्रतिभा से नहीं आती; उसके लिए बचपन से व्यवस्थित प्रशिक्षण, प्रशिक्षित कोच, खेल विज्ञान और मज़बूत घरेलू लीग ढांचे की ज़रूरत होती है। इंडियन सुपर लीग ने बीते एक दशक में फुटबॉल को नया मंच दिया है, कई राज्यों ने अकादमियां भी खोली हैं—पर ये कोशिशें भारत की विशालता के सामने अब भी एक बूंद जैसी हैं।

भारतीय फुटबॉल का संघर्ष केवल मैदान तक सीमित नहीं रहा। एआईएफएफ में नेतृत्व-विवाद, कानूनी अड़चनें और नीतिगत अस्थिरता ने कई अच्छी योजनाओं को अधूरा छोड़ा है। जिन देशों ने फुटबॉल में मुकाम हासिल किया—जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे उदाहरण देखें—वहां प्रशासनिक स्थिरता और दीर्घकालिक सोच पहली शर्त रही है। ऑस्ट्रेलिया तो क्रिकेट में भी उतना ही मज़बूत है, फिर भी उसने फुटबॉल को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। असली सवाल संसाधनों का नहीं, प्राथमिकता के बंटवारे का है। क्रिकेट ने भारत को जो पहचान और गर्व दिया है, वह अमूल्य है। पर किसी एक खेल की चमक बाकी खेलों के अंधेरे का कारण नहीं बननी चाहिए। असली खेल संस्कृति वहां बनती है जहां क्रिकेट के साथ फुटबॉल, हॉकी, कुश्ती और एथलेटिक्स को भी बराबर की जगह और सम्मान मिले।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने खेल को पढ़ाई से अलग खाने में रखने के बजाय शिक्षा का ही हिस्सा माना है। अगर स्कूलों में फुटबॉल को साल में एक बार होने वाली प्रतियोगिता तक सीमित न रखकर नियमित प्रशिक्षण, फिटनेस मूल्यांकन और स्थानीय लीग से जोड़ा जाए, तो मणिपुर के उस धूल भरे मैदान जैसे हज़ारों मैदान पूरे देश में खिलाड़ियों की खान बन सकते हैं।

उस शाम, मैदान के किनारे बैठे बुजुर्ग के मोबाइल की स्क्रीन आखिरकार बंद हो गई, पर मैदान में गेंद तब भी घूम रही थी। शायद यही भारतीय फुटबॉल की सबसे बड़ी ताकत है—सपना कभी नहीं थकता, भले ही रास्ता लंबा हो। ज़रूरत बस इतनी है कि यह जुनून किसी योजना, किसी कोच, किसी मैदान तक पहुंच पाए। जिस दिन देश के हर गांव का धूल भरा मैदान किसी अकादमी से जुड़ जाएगा, भारत विश्व कप का दर्शक नहीं, दावेदार बनकर मैदान में उतरेगा।

भारत को खेल-महाशक्ति बनने के लिए किसी एक चैंपियन की नहीं, हज़ारों मणिपुरी गांवों जैसे मैदानों की ज़रूरत है, जहां सपना पहले से मौजूद है—बस रास्ता चाहिए। यही आने वाले दशक की सबसे बड़ी जीत होगी।

नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ के बिल्डर ने एक ही फ्लैट की कई लोगों को कर दी रजिस्ट्री, सीएम योगी ने शुरू कराई जांच

लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ के जनता दर्शन में सोमवार को एक ऐसा मामला सामने आया, जिसने रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए. नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ से जुड़े एक बिल्डर के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंचे लोगों ने आरोप लगाया कि बिल्डर ने एक ही फ्लैट की कई-कई लोगों के नाम रजिस्ट्री कर दी. शिकायत सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए और कहा कि यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो बिल्डर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए तथा पीड़ितों को न्याय दिलाया जाए.

सोमवार को लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए लोगों की समस्याएं सुनीं. इस दौरान भूमि विवाद, अवैध कब्जे, धमकी, अपराध और बिल्डरों से जुड़े कई मामले उनके सामने आए. जनता दर्शन में पहुंचे लोगों ने मुख्यमंत्री को बताया कि नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ में परियोजनाएं विकसित करने वाले एक बिल्डर ने कथित तौर पर एक ही फ्लैट की रजिस्ट्री कई अलग-अलग लोगों के नाम कर दी. शिकायतकर्ताओं का कहना था कि इससे बड़ी संख्या में खरीदार आर्थिक और कानूनी परेशानी का सामना कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि यदि जांच में बिल्डर दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और प्रभावित लोगों को न्याय दिलाया जाए.

जनता दर्शन में सुनीं प्रदेशभर से आई शिकायतें

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के दौरान प्रदेश के अलग-अलग जिलों से आए फरियादियों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की. उन्होंने हर शिकायत को ध्यान से सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जनता की समस्याओं का

समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए और किसी भी शिकायत को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए. जनता दर्शन में कई लोगों ने जमीन पर अवैध कब्जे और दबंगों द्वारा धमकी दिए जाने की शिकायत भी मुख्यमंत्री के सामने रखी. मुख्यमंत्री ने ऐसे मामलों को गंभीर बताते हुए अधिकारियों से कहा कि शिकायत मिलते ही तत्काल जांच कराई जाए. यदि कोई व्यक्ति अवैध कब्जे या धमकी देने का दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा है कि किसी भी नागरिक की जमीन पर अवैध कब्जा न हो और पीड़ितों को समय पर न्याय मिले.

अपराधियों के लिए यूपी में कोई जगह नहीं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है. उन्होंने कहा कि जो लोग अवैध कब्जा करते हैं, लोगों को धमकाते हैं या कानून व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ बिना किसी ढिलाई के कार्रवाई की जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून का राज बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा.

विवेचना में तेजी लाने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने अपराध और भूमि विवाद से जुड़े मामलों की जांच में तेजी लाने पर भी जोर दिया. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ऐसे मामलों की विवेचना समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए ताकि पीड़ितों को जल्द न्याय मिल सके और दोषियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हो. उन्होंने यह भी कहा कि जांच में किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी.

बिल्डरों से जुड़े मामलों पर सरकार की नजर

हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश के कई शहरों, खासकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ में बिल्डरों से जुड़े विवाद सामने आते रहे हैं. फ्लैट की देरी से डिलीवरी, रजिस्ट्री में अनियमितता, अतिरिक्त वसूली और परियोजनाओं में पारदर्शिता की कमी जैसी शिकायतें समय-समय पर उठती रही हैं. ऐसे में जनता दर्शन के दौरान एक ही फ्लैट की कथित तौर पर कई लोगों के नाम रजिस्ट्री किए जाने की शिकायत सामने आने के बाद मुख्यमंत्री का तत्काल जांच का निर्देश देना महत्वपूर्ण माना जा रहा है. मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में प्राप्त सभी शिकायतों को संबंधित विभागों और शासन के अधिकारियों को भेजते हुए कहा कि हर मामले की निष्पक्ष जांच की जाए. उन्होंने निर्देश दिए कि शिकायतों के निस्तारण में पारदर्शिता बरती जाए और पीड़ितों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें.

पीड़ितों को न्याय दिलाने पर जोर

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि सरकार की प्राथमिकता आम नागरिकों को न्याय दिलाना है. उन्होंने कहा कि यदि बिल्डर या कोई अन्य व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है और लोगों के साथ धोखाधड़ी करता है, तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई होगी. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो. जनता दर्शन में सामने आए इस मामले के बाद अब निगाहें जांच पर टिकी हैं. यदि आरोप सही साबित होते हैं तो संबंधित बिल्डर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है, वहीं फ्लैट खरीदारों को राहत मिलने की उम्मीद भी बढ़ गई है।

छात्रवृत्ति योजना में घोटाला, परतें खुलीं, 19 शिक्षण संस्थानों के खिलाफ केस दर्ज

हरिद्वार। केंद्र सरकार की अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना में वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है। विभागीय जांच में गड़बड़ी के संकेत मिलने के बाद जिले के 19 स्कूल, कॉलेज और निजी शिक्षण संस्थानों के खिलाफ सिडकुल थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

मामला करोड़ों रुपये की छात्रवृत्ति से जुड़ा होने की आशंका है। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने पूरे प्रकरण की जांच के लिए एसआईटी गठित किए जाने की बात कही है।पुलिस के अनुसार, वर्ष 2021-22 और 2022-23 में अल्पसंख्यक छात्रों के लिए संचालित केंद्र पोषित छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर कुछ शिक्षण संस्थान संदिग्ध पाए गए थे। इसके बाद भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के निर्देश पर उत्तराखंड शासन ने जांच के आदेश दिए।

वित्तीय अनियमितता और शासकीय धन के गबन की आशंका

तत्कालीन जिलाधिकारी हरिद्वार ने उप जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जांच समितियों का गठन किया। भगवानपुर, लक्सर, हरिद्वार और रुड़की के उप जिलाधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्रों के संस्थानों की जांच कर रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी। जांच रिपोर्ट में कई संस्थानों में वित्तीय अनियमितता और शासकीय धन के गबन की आशंका जताई गई।

19 संस्थानों पर दर्ज हुई प्राथमिकी

गौड ब्लैस पब्लिक स्कूल (सहदेवपुर), एमजी पब्लिक स्कूल (अहमदपुर ग्रांट), एएसएन इंटर कॉलेज (धीरवाली, ज्वालापुर), सैनी प्राइवेट आईटीआई (बहादराबाद), जय भारती प्राइवेट आईटीआई (पर्दाथा उर्फ धनपुरा), एसबीएन प्राइवेट आईटीआई (टिक्कमपुर), आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर (मुस्तफाबाद), विश्व भारती पब्लिक स्कूल (गाडोवाली), मदरसा नूर-ए-हसन (हरिद्वार), जय भारत पीएस (बिंदुखड़क), हन्नू आईटीआई (भगवानपुर), रेडियंस एकेडमी (नेहंदपुर सुठारी, लक्सर), रामतीर्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (रहमतपुर, रुड़की), रुड़की इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (पुहाना), महर्षि दयानंद प्राइवेट आईटीआई (धनौरी), संस्कृति पब्लिक स्कूल (भौरी, रुड़की), फोनिक्स स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड बिजनेस (कांजेल इमलीखेड़ा), एसडीपीसी गर्ल्स इंटर कॉलेज (रुड़की) और ओम इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन (बढ़ेड़ी राजपूताना, रुड़की)।

प्रदेश में 181 पीसीएस अधिकारियों के तबादले

12 घंटे में 363 अफसर इधर से उधर; कई जिलों के एसडीएम बदले

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत 181 पीसीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। महज 12 घंटे के भीतर राज्य में कुल 363 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। शासन के आदेश के तहत कई तहसीलों के एसडीएम बदले गए हैं, जबकि कुछ अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।

जारी तबादला सूची में बड़ी संख्या में उप जिलाधिकारियों (एसडीएम) को एक जिले से दूसरे जिले में भेजा गया है, जबकि कई अधिकारियों को विकास प्राधिकरणों, नगर निगमों और अन्य संस्थानों से हटाकर नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

तबादलों के तहत अयोध्या के एसडीएम राम प्रसाद त्रिपाठी को मथुरा भेजा गया है, जबकि मिर्जापुर के एसडीएम संजीव कुमार यादव को अयोध्या की जिम्मेदारी दी गई है। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण में विशेष कार्याधिकारी लालकृष्ण को अयोध्या का एसडीएम बनाया गया है।

कुशीनगर के एसडीएम विनोद कुमार गुप्ता का भी तबादला अयोध्या किया गया है। वहीं, बाराबंकी, सीतापुर, गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ, हरदोई, बुलंदशहर और अन्य जिलों में भी कई अधिकारियों की नई तैनाती की गई है।

धार्मिक स्थलों पर नकली नोट खपाने की साजिश, नेटवर्क का भंडाफोड़

14 दिन में 12 तस्कर गिरफ्तार

हरिद्वार। देश से रोजाना लाखों श्रद्धालुओं की आमद और बाजारों में नकदी के बड़े कारोबार का फायदा उठाकर धर्मनगरी में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रहे नकली नोटों के एक बड़े नेटवर्क का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। पिछले 14 दिनों के भीतर पुलिस ने लगातार तीन बड़ी कार्रवाइयां करते हुए इस गिरोह को तगड़ा झटका दिया है।

पुलिस ने अलग-अलग मामलों में 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2.92 लाख रुपये की जाली करेंसी, नोट छापने में इस्तेमाल होने वाले प्रिंटर, लैपटॉप और मोबाइल समेत अन्य उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि यह शातिर गिरोह मुख्य रूप से छोटे दुकानदारों और भीड़भाड़ वाले धार्मिक स्थलों पर इन नकली नोटों को खपाने की

फिराक में था। 28 जून को श्यामपुर थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया।

छापेमारी कर दो और आरोपियों किए गिरफ्तार

तलाशी में उनके पास से 52,500 रुपये की नकली करेंसी बरामद हुई। 30 जून को गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने गिरोह के तीन अन्य सदस्यों को भी दबोच लिया। इनके कब्जे से 50 हजार रुपये के छपे हुए नकली नोट, प्रिंटर, लैपटॉप, मोबाइल और अन्य अहम उपकरण बरामद हुए।

6 जुलाई को नगर कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार और आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 84,500 रुपये की जाली करेंसी मिली।11 जुलाई को पुलिस कस्टडी रिमांड में आरोपियों ने कई अहम राज उगले। इसके आधार पर पुलिस की एक विशेष टीम पंजाब पहुंची और छापेमारी कर दो और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 1.05 लाख रुपये के नकली नोट, एक प्रिंटर और तस्करी में इस्तेमाल की जा रही एक कार बरामद की।

इसलिए निशाने पर थी धर्मनगरी

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, हरिद्वार जैसे प्रमुख धार्मिक शहरों में प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। यहां भीड़भाड़, अस्थायी दुकानों की बहुलता और नकद भुगतान का चलन अधिक है। जाली नोट खपाने की कोशिश करने वाले गिरोह ऐसे स्थानों को अपना सबसे आसान निशाना मानते हैं, क्योंकि जल्दबाजी में छोटे दुकानदार अक्सर नोटों की ठीक से पहचान नहीं कर पाते हैं।

मायके जाने की जिद को लेकर पत्नी ने बच्ची के साथ नदी में लगा दी छलांग

हरिद्वार/बहादराबाद। गंगनहर में मासूम बच्ची के साथ छलांग लगाने की घटना के पीछे पति-पत्नी के बीच रास्ते में हुआ विवाद वजह बनकर सामने आ रहा है। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि पति अपनी बीमार मां से मिलने देहरादून जाना चाहता था, जबकि पत्नी मायके छोड़ने की जिद कर रही थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हुई, जो कुछ ही देर में बड़े हादसे में बदल गई।

पुलिस के अनुसार अर्जुन (35) निवासी कोटा मुरादनगर थाना कलियर अपनी पत्नी सविता (30), एक वर्षीय बेटी नोनी और चार वर्षीय पुत्र नक्श के साथ बाइक से ससुराल गांव रायपुर दरेड़ा जा रहा था। जब परिवार दौलतपुर के पास पहुंचा तो रास्ते में पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया। कहासुनी बढ़ने पर सविता ने अर्जुन से मोटरसाइकिल रोकने के लिए कहा। जैसे ही मोटरसाइकिल रुकी, सविता ने बेटी नोनी को गोद में उठाया और देखते ही देखते गंगनहर में छलांग लगा दी।

घटना देख पति व बेटा चिल्लाने लगे। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना

दी। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने महिला और बच्ची की तलाश के लिए सर्च अभियान शुरू किया। क्षेत्राधिकारी संजय चौहान ने बताया कि एसडीआरएफ की टीम लगातार गंगनहर में तलाश में जुटी है। परिजनों से भी पूछताछ कर घटना के कारणों की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस के मुताबिक, कोटा मुरादानगर निवासी अर्जुन पेशे से एल्यूमीनियम स्ट्रक्चर बनाने का कारीगर है। अर्जुन और सविता का विवाह 2021 में हुआ था। अर्जुन ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि उसकी मां देहरादून के एक अस्पताल में भर्ती हैं और वह उनसे मिलने जाने की तैयारी में था। इसी बीच पत्नी ने उसे पहले मायके छोड़ने की बात कही। पति के अनुसार, वह पत्नी को बाइक से मायके छोड़ने के लिए निकला, लेकिन रास्ते में दोनों के बीच फिर विवाद होने लगा।

लखवाड़ बांध परियोजना निर्माण स्थल पर अचानक गिरा भारी मलबा

डंपर और जेसीबी क्षतिग्रस्त

कालसी विकासनगर। लखवाड़ बांध परियोजना के निर्माण स्थल पर अचानक मलबा और पत्थर गिरने से एक जेसीबी और डंपर क्षतिग्रस्त हो गए। गनीमत रही कि हादसे के समय चालक और श्रमिक मौजूद नहीं थे। घटना शनिवार की रात 10 के करीब हुई।

लखवाड़ बांध परियोजना के निर्माण स्थल पर रात दस बजे अचानक से भारी-भरकम पत्थर गिरने लगे। इस दौरान पहाड़ी के नीचे सटाकर पार्क किए गए जेसीबी और एक डंपर क्षतिग्रस्त हो गए। उधर, घटना की जानकारी मिलते ही निर्माण एजेंसी से संबंधित अधिकारी-कर्मचारी मौके पर पहुंचे।

उन्होंने क्षतिग्रस्त डंपर व जेसीबी पर गिरे मलबे को हटाना शुरू किया। पत्थर व मलबा गिरने की घटना रात

में घटने के कारण बड़ा हादसा टल गया। अन्यथा निर्माण स्थल पर कार्य करने वाले श्रमिक, अधिकारी-कर्मचारी व वाहन चालक भी चपेट में आ सकते थे।

लखवाड़ बांध परियोजना का निर्माण करा रही एलएनटी के महाप्रबंधक एपी सिंह ने बताया कि भारी वर्षा की चेतावनी के चलते कार्य बंद था। इस कारण कोई भी श्रमिक व अधिकारी-कर्मचारी निर्माण स्थल पर मौजूद नहीं था। उन्होंने बताया कि क्षतिग्रस्त वाहनों को मलबे से निकाल लिया गया है।

तीन दिन पहले मलबे से बाल-बाल बचा था चालक

लखवाड़ बांध परियोजना के निर्माण स्थल पर बृहस्पतिवार को भी अचानक से भारी मलबा गिरा था। इस दौरान एक जेसीबी मौके पर मौजूद थी जिसके चालक ने जेसीबी से कूदकर और दूसरी दिशा की ओर भागते हुए बमुश्किल जान बचाई थी। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वॉयरल हुआ था। ह्यूमन राइट एंड आरटीआई एसोसिएशन ने निर्माण कंपनी पर कार्य के दौरान लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है जिस प्रकार से लखवाड़ बांध निर्माण स्थल पर किसी भी समय मलबा व पत्थर गिर रहे हैं, उससे बड़ी दुर्घटना हो सकती है। दूसरी ओर कंपनी प्रबंधन ने निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा नियमों का पूर्णरूप से पालन किए जाने की बात कही है।

नवजात बेटी का मुंह देखने से पहले पिता और मामा की दर्दनाक मौत

अस्पताल में मां करती रही इंतजार!

हमीरपुर। हमीरपुर जिले के मौदहा थाना इलाके के रोहारी गांव निवासी कुलदीप कुमार और उनके साले पवन की रात करीब एक बजे एनएच-34 पर एक अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई. कुलदीप अपनी गर्भवती पत्नी रेखा को देखने के लिए साले और एक अन्य रिश्तेदार के साथ ई-रिक्शा से जिला अस्पताल जा रहे थे. बाइक की लाइट खराब होने के कारण उन्होंने ई-रिक्शा लिया था. अस्पताल से 23 किलोमीटर पहले हुए इस हादसे के ठीक दो घंटे बाद रात करीब तीन बजे पत्नी ने एक नवजात बच्ची को जन्म दिया, जिससे परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं.

लाइट खराब होने पर लिया ई-रिक्शा, रास्ते में काल ने घेरा

मौदहा के रोहारी गांव के रहने वाले कुलदीप की पत्नी रेखा को प्रसव पीड़ा होने के बाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था. अपनी गर्भवती पत्नी को देखने के लिए कुलदीप अपने

साले पवन और एक अन्य रिश्तेदार के साथ साढ़ू के घर से निकले थे। बाइक की हेडलाइट खराब होने की वजह से उन्होंने सुरक्षा के लिहाज से ई-रिक्शा से जाने का फैसला किया. लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, रास्ते में ही वे हादसे का शिकार हो गए.

मासूम के जन्म से ठीक दो घंटे पहले उजड़ा सिंदूर

रात करीब एक बजे कुण्डरा गांव के पास नेशनल हाईवे-34 पर एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने उनके ई-रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी. इस दर्दनाक हादसे में कुलदीप और उनके साले पवन की मौके पर ही मौत हो गई।

ललिता हत्याकांड

चंद्रशेखर मेरठ में करते रहे आंदोलन, अखिलेश ने दिल्ली से ही कर दिया खेला!

मेरठ। उत्तर प्रदेश की सियासत में 'दलित वोट बैंक' को अपने पाले में करने को लेकर शह-मात का खेल चल रहा है. दलित राजनीति की सियासी बिसात पर मेरठ में हुए ललिता गौतम हत्याकांड एक बड़ा केंद्र बनकर उभरा. इस पूरे घटनाक्रम में जमीन पर संघर्ष की एक अलग कहानी दिखी, तो दूसरी तरफ बंद कमरों में लिखी गई रणनीतिक पटकथा ने सबको चौंका दिया.

ललिता गौतम की हत्याकांड को लेकर आजाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद मेरठ की सड़कों पर पुलिस प्रशासन से सीधी जंग लड़ रहे थे. चंद्रशेखर आजाद सूबे में दलित समुदाय के बीच अपनी सियासी पैठ जमाने का कोई भी मौका नहीं गंवा रहे हैं.

वहीं, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने दिल्ली में बैठकर एक ऐसा सियासी 'खेल' किया. चंद्रशेखर मेरठ की सड़क पर आंदोलन ही करते रहे और अखिलेश यादव ने लखनऊ में ललिता गौतम के परिवार वालों से मुलाकात किया और उन्हें आर्थिक मदद देने के साथ न्याय दिलाने की गारंटी दी. इस तरह अखिलेश ने दलित समाज को साधे रखने के लिए बड़ा दांव चला.

चंद्रशेखर का संघर्ष बनाम अखिलेश का 'स्मार्ट मूव'

मेरठ की 20 वर्षीय बीए की छात्रा ललिता गौतम की हत्या के बाद इंसाफ के लिए जब सड़क पर उतरे तो उन्हें पुलिसिया कार्रवाई और लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा. पुलिस एक्शन के बाद चंद्रशेखर आज़ाद तुरंत सड़क पर उतर गए. वे पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ अल्टीमेटम देने के लिए मेरठ की ओर कूच कर गए.

पुलिस ने उन्हें टोल प्लाजा पर रोकने की कोशिश की, तीखी बहस हुई और चंद्रशेखर ने आक्रामक तेवर दिखाते हुए पुलिस महकमे को हिला कर रख दिया. ज़मीन पर पूरा माहौल ऐसा था कि चंद्रशेखर इस मुद्दे के सबसे बड़े मसीहा बनकर उभर रहे हैं. इतना ही नहीं उन्होंने मायावती के खामोशी पर भी सवाल उठाया और कहा कि दलित समुदाय के लिए संघर्ष करते रहेंगे.

दिलचस्प बात यह है कि जब चंद्रशेखर मेरठ के रास्तों पर पुलिस से उलझ रहे थे, ठीक उसी वक्त सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बिना कोई शोर-शराबा किए एक बड़ा दांव खेल दिया. अखिलेश यादव ने पहले फ्रंटफुट पर उतरकर पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल खड़े किए और फिर अपनी तेजतर्रार युवा सांसद इकरा हसन को इस मोर्चे पर लगाया.

इकरा हसन के जरिए अखिलेश ने किया 'खेला'

अखिलेश यादव ने मेरठ की सड़कों पर उतरकर सीधे टकराव में पड़ने के बजाय 'लॉजिस्टिक और इमोशनल' रणनीति चुनी. कैराना से सपा की सांसद इकरा हसन ने शनिवार सुबह चुपचाप मेरठ पहुंचती हैं और ललिता गौतम के पीड़ित परिवार को अपने साथ लेकर सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो जाती हैं.

जब तक मेरठ का प्रशासन और खुफिया तंत्र चंद्रशेखर आज़ाद के आंदोलन को संभालने और उन्हें रोकने में व्यस्त रहा, तब तक पीड़ित परिवार अखिलेश यादव के सामने बैठ चुका था. अखिलेश यादव ने न सिर्फ दिल्ली में पीड़ित परिवार से मुलाकात की, बल्कि उन्हें ढांढस बंधाया, कानूनी और हर संभव न्याय दिलाने की गारंटी दी और साथ ही दो लाख रुपये की आर्थिक मदद का बंद लिफाफा सौंप दिया.

अखिलेश का दांव क्या 2027 में हिट होगा?

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस घटनाक्रम से समाजवादी पार्टी ने एक तीर से कई निशाने साधने की कवायद की है. बसपा प्रमुख मायावती सिर्फ सोशल मीडिया पर बयान जारी किया और चंद्रशेखर आज़ाद रास्ते के गतिरोधों से जूझते रहे, तब तक अखिलेश यादव पीड़ित परिवार के साथ अपनी तस्वीर सार्वजनिक कर चुके थे. राजनीति में 'जो पहले पहुंचा, वो बाजी ले गया' वाला नियम यहां पूरी तरह फिट बैठा.

2024 के लोकसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद अखिलेश यादव लगातार खुद को दलितों के हितैषी के रूप में स्थापित करने में जुटे हैं. ललिता गौतम के परिवार को संरक्षण देकर उन्होंने यह संदेश दिया कि सपा सिर्फ पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की नहीं, बल्कि दलितों के उत्पीड़न पर भी सबसे पहले खड़ी होती है. अखिलेश ने सिर्फ जुबानी बात तक सीमित नहीं रहे बल्किराजनीतिक भाषण देने के बजाय मौके पर आर्थिक सहायता पहुंचाना पीड़ित परिवार और दलित समाज के बीच अपनी पैठ जमाने की कोशिस की है.

बदायूं में पत्नी की हत्या कर सोकपिट में छिपाया

तीसरे दिन जलाया, पति समेत तीन आरोपी गिरफ्तार

बदायूं। बदायूं के बिसौली थाना क्षेत्र में लापता महिला सत्यवती की तलाश के दौरान पुलिस को 42वें दिन सफलता हाथ लगी। पुलिस के मुताबिक महिला की हत्या कर उसके शव का जला दिया गया। पुलिस ने सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए महिला के पति और दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, पति ने प्रेम संबंध के चलते पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के बाद शव को घर के आंगन में बने लैट्रिन के टैंक (सोकपिट) में छिपा दिया। तीन दिन बाद शव निकालकर श्मशान के पास जला दिया। इस मामले में छह लोगों की संलिप्तता सामने आई है।

बिसौली क्षेत्र के गांव सर्वा निवासी जय सिंह यादव ने प्रेम संबंध के चलते पत्नी सत्यवती (40 वर्ष) की अपने भाई चंद्रपाल, भांजे विजय यादव उर्फ छोटू के साथ मिलकर एक-दो जून की रात कमरे के भीतर गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद मृतका के शव को आंगन में बने सोकपिट में छिपा दिया।

मध्य प्रदेश शिक्षक संघ दमोह द्वारा सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं शिक्षा अधिकारियों का भव्य सम्मान समारोह संपन्न

आज की जनधारा

दमोह। जिले में शिक्षा के क्षेत्र में अपना संपूर्ण जीवन एवं उत्कृष्ट योगदान समर्पित करने वाले सेवानिवृत्त शिक्षकों और शिक्षा अधिकारियों के सम्मान में एक भव्य एवं गरिमामयी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह समारोह मध्य प्रदेश शिक्षक संघ, दमोह के तत्वावधान में पुरानी कलेक्ट्रेट स्थित नेहरू पार्क के सामने संघ के कार्यालय में अपार हर्षोल्लास एवं आत्मीयता के साथ संपन्न हुआ। इस विशेष अवसर पर पूर्व एवं नवागत जिला शिक्षा अधिकारियों का भी हार्दिक स्वागत व अभिनंदन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में नवागत शिक्षा अधिकारी श्री सत्यम चौरसिया उपस्थित रहे, जिन्होंने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। वहीं, विशिष्ट अतिथि के आसंदी पर श्री एस. के. नेमा, कमलचंद सिंघई और कोषालय अधिकारी श्री अभिषेक हजारी ने उपस्थित रहकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम के आरंभ में संघ के पदाधिकारियों द्वारा सभी मंचासीन अतिथियों का पुष्पगुच्छ और माल्यार्पण से भव्य स्वागत किया गया। इस गरिमामयी आयोजन का मुख्य आकर्षण उन गुरुजनों और अधिकारियों का सम्मान रहा, जिन्होंने अपना पूरा जीवन नौनिहालों के भविष्य निर्माण और शिक्षा विभाग की प्रगति में लगा दिया। कार्यक्रम के दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारी नेता श्री राकेश हजारी, सेवानिवृत शिक्षक श्री भागचंद जैन और श्री डी. के. जैन को उनके सुदीर्घ, निष्ठावान एवं निष्कलंक सेवाकाल के लिए सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही, पूर्व विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्री वाय. के. कोरी को भी उनके उत्कृष्ट प्रशासनिक नेतृत्व व कुशल कार्यशैली के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ द्वारा इन सभी विभूतियों को मंच पर ससम्मान आमंत्रित कर शॉल और श्रीफल भेंट किया गया तथा उनके स्वस्थ, सुखी और दीर्घायु जीवन की मंगल कामना की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नवागत शिक्षा अधिकारी श्री सत्यम चौरसिया ने अपने उद्बोधन से उपस्थित सभी शिक्षकों और अधिकारियों का हृदय जीत लिया। अपने स्वागत से अभिभूत होकर श्री चौरसिया ने एक अत्यंत प्रेरक और भावुक संदेश दिया। उन्होंने अपने संबोधन में दृढ़ संकल्प व्यक्त करते हुए कहा, *₹मैं दमोह जिले में अपने कार्यकाल के दौरान ऐसे काम करना चाहूंगा कि जिस प्रकार आज मेरे आगमन पर इतना भव्य और आत्मीय स्वागत हुआ है, ठीक वैसा ही स्नेह और सम्मान मुझे मेरे यहाँ से जाने (विदाई) पर भी प्राप्त हो। उनके इस सकारात्मक एवं ऊर्जावान वक्तव्य का समूचे सभागार ने करतल ध्वनि के साथ जोरदार स्वागत किया। विशिष्ट अतिथि श्री एस. के. नेमा और श्री अभिषेक हजारी ने भी अपने विचार साझा करते हुए शिक्षकों के योगदान को समाज के लिए सर्वोपरि बताया और सेवानिवृत्त शिक्षकों के अनुभवों से युवा पीढ़ी को सीख लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित अतिथियों एवं शिक्षकों ने जिले में शिक्षा की गुणवत्ता को और अधिक सुदृढ़ करने तथा शिक्षकों के हितों के लिए एकजुट होकर कार्य करने का संकल्प लिया। इस सफल आयोजन में मध्य प्रदेश शिक्षक संघ दमोह के सभी सक्रिय सदस्यों, पदाधिकारियों और भारी संख्या में जिले के शिक्षकों की उत्साहवर्धक उपस्थिति रही। कार्यक्रम का सफल संचालन एमके खरे एवं आभार प्रदर्शन संघ के संभागीय अध्यक्ष प्रमेंद्र जैन द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में संगठन मंत्री पारस जैन,प्रदीप अग्रवाल, महेंद्र जैन,मनीष भारद्वाज शिशिर तिवारी, संजय दुबे, विजय दुबे,आदित्य चौरसिया, महेश गुप्ता, अरविंद चौराहा निलेश जैन, नितेश पाठक ,देवी पटेल ,नितिन श्रीवास्तव ,संजय पाठक निरपत ठाकुर ,नीरज साहू ,धीरज पाराशर उमाशंकर चौबे, महेश सोनी, सोनू मुंडा, मुन्ना पटेल ,कैलाश ठाकुर, संदीप श्रीवास्तव ,दीपमाला जैन निशा चौकसे आदि उपस्थित रहे।

दस्तक अभियान का शुभारंभ आज से घर-घर जाकर बच्चों के स्वास्थ्य को जांचेगा स्वास्थ्य दल

आज की जनधारा

उज्जैन। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी बाल्यकालीन बीमारियों की पहचान एवं त्वरित उपचार व रेफर सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश भर में दस्तक अभियान के प्रथम चरण का आयोजन 14 जुलाई से 31 अगस्त तक किया जायेगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अशोक कुमार पटेल ने बताया कि डायरिया बीमारी से बढ़ती शिशु मृत्यु दर को संज्ञान में लेते हुए ₹स्टॉप डायरिया कैम्पेन₹ सह दस्तक अभियान डायरिया की रोकथाम, सफाई और ओआरएस से रखें अपना ध्यान की थीम पर आधारित है। जिसमें जन्म से पांच वर्ष तक के बच्चों में गंभीर कुपोषण, एनीमिया, निमोनिया, निर्जलीकरण, संक्रमण की पहचान, त्वरित उपचार एवं आवश्यकता अनुसार रेफरल के साथ-साथ विटामिन ए की खुराक दी जायेगी एवं ओ.आर.एस. पैकेट व जिंक टैबलेट का वितरण किया जायेगा। स्वास्थ्य विभाग एवं महिला एवं बाल विकास के संयुक्त दल, जिसमें ए.एन.एम., आशा कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों को घर-घर जाकर दस्तक देकर बच्चों में पाई जाने वाली बीमारियों की सक्रिय पहचान एवं उचित प्रबंधन सुनिश्चित करेंगे। दस्तक अभियान में जन्म से पांच वर्ष तक के गंभीर कुपोषित बच्चों की सक्रिय रूप से पहचान एवं प्रबंधन करना, छह माह से पांच वर्ष तक के बच्चों में गंभीर एनीमिया की सक्रिय स्क्रीनिंग कर प्रोटोकॉल अनुसार उपचार करना, 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को आयरन सिरप पिलाई जायेगी। नौ माह से पांच वर्ष तक के समस्त बच्चों को विटामिन ए अनुपूरक की खुराक पिलाना, पांच वर्ष तक के बच्चों में बाल्यकालीन निमोनिया की त्वरित पहचान एवं रेफरल करना, पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में बाल्यकालीन दस्त रोग के नियंत्रण हेतु ओ.आर.एस. के उपयोग संबंधी सामुदायिक जागरूकता में बढ़ावा एवं प्रत्येक घर में गृहभेंट के दौरान ओ.आर.एस. पहुँचाना, गृहभेंट के दौरान शिशु एवं बाल आहार-पूर्ति संबंधी समझाइश समुदाय को देना एवं स्तनपान संबंधी भ्रांतियों को दूर करने के लिए सामुदायिक जागरूकता लाना, कम वजन के नवजात शिशुओं की उचित देखभाल के लिए समुदाय में कंगारू मदर केयर पद्धति संबंधी जागरूकता की गतिविधियां की जायेंगी। शिशु एवं बाल आहार-पूर्ति संबंधी समझाइश समुदाय में स्तनपान संबंधी भ्रांतियों को दूर करने के लिए सामुदायिक जागरूकता करना अभियान का मुख्य उद्देश्य है।

दमोह में बड़ा खुलासाः बिना एक्सप्लोसिव लाइसेंस चल रहे थे 33 पेट्रोल पंप, 4 सील

आज की जनधारा

दमोह। जिले में पेट्रोल पंपों के संचालन को लेकर हुई प्रशासनिक जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। शिकायत मिलने के बाद कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के निर्देश पर अधिकारियों की संयुक्त टीम ने जिले के पेट्रोल पंपों का आकस्मिक निरीक्षण किया। जांच के दौरान सामने आया कि 33 पेट्रोल पंप बिना वैध एक्सप्लोसिव लाइसेंस के संचालित हो रहे थे। इनमें से 4 पेट्रोल पंपों पर लाइसेंस नहीं मिलने के कारण उन्हें तत्काल सील कर दिया गया। कलेक्टर ने बताया कि कई पेट्रोल पंपों के एक्सप्लोसिव लाइसेंस वर्ष 2023 में ही समाप्त हो चुके थे, लेकिन संचालकों ने न तो उनका नवीनीकरण कराया और न ही नया आवेदन किया। इसके बावजूद पेट्रोलियम पदार्थों का भंडारण और विक्रय जारी रखा गया, जो आमजन की सुरक्षा और जान-माल के लिए गंभीर खतरा है। जांच के दौरान दो पेट्रोल पंपों पर मात्रा संबंधी अनियमितताएं भी सामने आईं। इनमें से एक पेट्रोल पंप पर 4100 लीटर अतिरिक्त डीजल पाया गया, जिसे जब्त कर राजसात करने की कार्रवाई की जा रही है। संबंधित ऑयल कंपनी को भी इस संबंध में पत्र भेजा गया है। कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने कहा कि बिना वैध लाइसेंस पेट्रोल पंपों का संचालन केवल नियमों का उल्लंघन नहीं, बल्कि आम जनता की सुरक्षा के साथ गंभीर खिलवाड़ है। इस मामले में संबंधित पेट्रोल पंप संचालकों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। साथ ही ऑयल कंपनियों के क्षेत्रीय प्रबंधकों को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा जा रहा है, क्योंकि बिना वैध लाइसेंस के भी पेट्रोल पंपों को ईंधन की आपूर्ति की जा रही थी। उन्होंने यह भी कहा कि जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी समय-समय पर निरीक्षण करने और निगरानी रखने की थी, उनकी भूमिका की भी जांच की जाएगी।

दमोह पुलिस के सूबेदार प्रमोट होकर बने रक्षित निरीक्षक, पुलिस विभाग में खुशी की लहर

आज की जनधारा

दमोह। दमोह पुलिस के लिए रविवार का दिन गौरव का रहा। पुलिस मुख्यालय से जारी सूची में जिले के 2 सूबेदारों को प्रमोशन देकर रक्षित निरीक्षक बनाया गया है।प्रमोट होने वालों में सूबेदार अभिनव साहू और सूबेदार श्रीमती आकांक्षा जोशी शामिल हैं, जो वर्तमान में दमोह में पदस्थ हैं। वहीं सूबेदार लाखन सिंह बघेल, जो पूर्व में दमोह में पदस्थ रहे और वर्तमान में नरसिंहपुर में पदस्थ हैं, उन्हें भी रक्षित निरीक्षक के पद पर प्रमोशन मिला है।तीनों अधिकारियों को प्रमोशन मिलने पर जिले भर में बधाई और शुभकामनाओं का दौर जारी है।वहीं यातायात थाना प्रभारी दलबीर सिंह मार्को को कार्यवाहक जिम्मेदारी से मुक्ति मिलने और रक्षित/निरीक्षक बनने पर भी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने उन्हें बधाई दी।पुलिस विभाग के अधिकारियों ने कहा कि इन प्रमोशन से जवानों का मनोबल बढ़ेगा और जिले में कानून व्यवस्था और बेहतर होगी।

अतिक्रमण के विस्थापितों की टूट, रही आसए आश्वासन और घोषणा के बाद भी हाथ खाली

आज की जनधारा

ओबेदुल्लागंज। अतिक्रमण हटाना कानूनन प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है, लेकिन प्रभावितों का पुनर्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण है आपको बता दें कि सवा साल पूर्व स्थानीय प्रशासन ने विकास के नाम पर सैकड़ों लोगों की दुकानें धराशाही की थीं। उनको प्रशासन ने आश्वासन भी दिया था कि जल्द कम लागत की दुकानों का निर्माण कराकर नई दुकानें दुकानदारों को दी जाएंगी, लेकिन पूरा साल बीत जाने के बाद प्रभावित आर्थिक तंगी से जूझ रहे बेरोजगारों को स्थानीय प्रशासन दुकानें उपलब्ध नही करवा सका है। प्रभावित लोगो ने संगठित होकर स्थानीय प्रशासन एसडीएम, तहसीलदार स्थानीय नपा अध्यक्ष को ज्ञापन भी सौंपा। लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई, अब प्रभावित लोगों के सामने आजीविका का संकट गहराता जा रहा है, प्रभावित लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि उन्हें किसी निश्चित स्थान पर अस्थाई या स्थाई रूप से व्यापार करने की अनुमति दी जाए जब तक कोई स्थाई समाधान नहीं मिलता, तब तक प्रभावित परिवारों को राशन, स्वास्थ्य सुविधाएं और बच्चों की पढ़ाई के लिए जन प्रतिनिधियों, विधायक, पार्षद के माध्यम से आपातकालीन सहायता दिलाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

जयघोषों के बीच निकली भगवान जगदीश स्वामी की रथयात्रा, श्रद्धा के रंग में रंगा जनसैलाब

आज की जनधारा

पचोर। सनातन संस्कृति, सामाजिक एकता और धार्मिक आस्था का अनुपम संगम सोमवार को भगवान जगदीश स्वामी (जगन्नाथ) की भव्य रथयात्रा के दौरान देखने को मिला। अखिल भारतीय चंद्रवंशी खाती समाज के तत्वावधान में आयोजित इस धार्मिक आयोजन में नगर सहित आसपास के अनेक गांवों से हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। पूरे मार्ग में भगवान जगदीश स्वामी के जयघोष, भक्ति गीतों और ढोल-नगाड़ों की गूंज से वातावरण भक्तिमय बना रहा। रथयात्रा का शुभारंभ सायंकाल साधनखेड़ी रोड स्थित उज्जैन वाली अंबे माता मंदिर से विधि-विधान के साथ किया गया। आकर्षक ढंग से सजाए गए बैलगाड़ी के रथ पर भगवान जगदीश स्वामी की मनोहारी प्रतिमा विराजित थी। भगवा ध्वजों से सजे रथ को समाजसेवी मुंशीलाल वर्मा एवं धर्मेंद्र खाती ने श्रद्धापूर्वक खींचते हुए यात्रा का नेतृत्व किया। रथ के आगे चल रहे श्रद्धालु धार्मिक भजनों की स्वर लहरियों पर झूमते हुए भगवान के जयकारे लगाते रहे, जिससे पूरा मार्ग भक्ति के रंग में रंग गया।

रथयात्रा पड़ना नगर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होकर निकली। तलेन रोड, नाना गोया, आसारेटा चौराहा, सदर बाजार, गांधी चौक, बस स्टैंड और पिपली चौराहा सहित अनेक स्थानों पर श्रद्धालुओं ने भगवान की आरती उतारकर पुष्पवर्षा की। कई स्थानों पर श्रद्धालुओं ने शीतल पेय और प्रसाद की व्यवस्था भी की। महिलाओं ने मंगलगीत गाकर भगवान का स्वागत किया, वहीं युवाओं ने पूरे उत्साह के साथ यात्रा में सहभागिता निभाई। इस धार्मिक आयोजन में तुकोगंज, गुलावता, लीमा चौहान, शेरपुरा, मगराना, रामपुरिया, कांकरिया, मीणा, साधनखेड़ी, मऊ, आसारेटा, पंवार, करौंदी सहित आसपास के अनेक गांवों से समाजजन बड़ी संख्या में पहुंचे। बुजुर्गों, युवाओं और महिलाओं की उल्लेखनीय भागीदारी ने रथयात्रा को और अधिक भव्य स्वरूप प्रदान किया। नगर भ्रमण के बाद रथयात्रा झिरी स्थित श्री नरसिंह मंदिर पहुंची, जहां भगवान जगदीश स्वामी की सामूहिक पूजा-अर्चना एवं महाआरती संपन्न हुई। महाआरती के पश्चात मेडतवाल धर्मशाला में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण कर धर्मलाभ प्राप्त किया। पूरे आयोजन के दौरान पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्क रहा। एसआई राहुल सेंधव, एएसआई आनंदीलाल भिलाला, आरक्षक राकेश सिसोदिया सहित पुलिस बल ने यात्रा मार्ग पर तैनात रहकर व्यवस्था संभाली, जिससे रथयात्रा शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हुई।

मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना के अंतर्गत मिली चिकित्सा सुविधा

जन्म से हृदय रोग से ग्रसित बालिका सभ्यता अब सामान्य जीवन जीने की राह पर है।

आज की जनधारा

उज्जैन। जन्म से हृदय रोग से ग्रसित बालिका सभ्यता अब सामान्य जीवन जीने की राह पर है। जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अशोक कुमार पटेल के मार्गदर्शन में जिला स्वास्थ्य टीम के प्रयासों से सभ्यता का सफल हृदय ऑपरेशन कराया गया। सभ्यता का जन्म हृदय रोग की सभ्यता के साथ हुआ था। बचपन में ही उसे बार-बार थकान, सांस लेने में तकलीफ, शारीरिक विकास में कमी और सामान्य क्रियाओं में दिक्कतें होती थीं। 9 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर स्थिति गंभीर हो गई। जिला स्वास्थ्य टीम द्वारा जांच कराई गई तो पता चला कि समता को गंभीर हृदय रोग है। तत्काल उसे मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना के अंतर्गत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। जिला चिकित्सालय उज्जैन से सभ्यता को आरबीएसके (राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम) टीम के माध्यम से भोपाल के अयुष्मान भारत निरामय हृदय योजना के अंतर्गत संबद्ध अस्पताल में रेफर किया गया। वहां विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम द्वारा सफल ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद समता की हालत पूरी तरह स्थिर है और वह अब सामान्य जीवन जीने की ओर अग्रसर है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अशोक कुमार पटेल ने बताया कि मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना के तहत जिले के ऐसे कई बच्चों को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। समता का यह सफल ऑपरेशन योजना की उपयोगिता का जीवंत उदाहरण है। माता-पिता अब समता की निरंतर देखभाल कर रहे हैं और शासन द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं का पूरा लाभ ले रहे हैं।

बिना खाद्य लायसेंस के दुकान संचालित करने के आरोप में दोष सिद्ध होने पर

02 अनावेदक पर 50 हजार रुपए की अर्थदण्ड शास्ति अधिरोपित

आज की जनधारा

दमोह। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत बिना खाद्य लायसेंस के दुकान संचालित करने पर दोष सिद्ध होने के आरोप में अपर कलेक्टर एवं न्याय निर्णयन अधिकारी ने जिले के 02 अनावेदकों पर 50 हजार रुपए के अर्थदण्ड की शास्ति अधिरोपित की है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी माधवी रावत (बुधौलिया) द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर जिले की तहसील दमयंती नगर बरंडा नया बाजार नं.-1 निवासी अनावेदक सोनू जैन पिता अजीत जैन तथा तहसील जबेरा के नोहटा स्टार नगर निवासी प्रकाश नेमा पिता स्व. चंद्रभान नेमा द्वारा बिना खाद्य लायसेंस के दुकान संचालित करने का दोष सिद्ध होने के आरोप में 25-25 हजार रुपए के मान से अर्थदण्ड की शास्ति अधिरोपित की है। उन्होंने संबंधितों को निर्देशित किया है कि अधिरोपित शास्ति की राशि एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से ऑनलाईन चालान द्वारा शीर्ष 0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य 04 लोक स्वास्थ्य 104 शुल्क एवं दण्ड आदि 0754 खाद्य एवं औषधि नियंत्रण में जमा कराकर चालान की एक प्रति न्यायालय अपर कलेक्टर एवं न्याय निर्णयन अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत की जाय । अधिरोपित शास्ति की राशि 15 दिवस में जमा की जाये। नियत समयावधि में राशि जमा नहीं किये जाने पर अधिनियम की धारा 96 के तहत भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूल की जायेगी।

डेंगू मलेरिया के बचाव हेतु रखें सावधानी

आज की जनधारा

उज्जैन। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आमजनों को मच्छर द्वारा जनित बीमारियों से बचाव के लिए सलाह जारी की गई हैं। इसके अंतर्गत डेंगू मलेरिया के बचाव हेतु मच्छरों से सावधान रहें। डेंगू एडीज मच्छर के काटने से होता है, यह मच्छर दिन में काटता है। डेंगू के अधिकांश मामले पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं और उनका प्रबंधन घर पर भी किया जा सकता है। डेंगू मलेरिया के बचाव व नियंत्रण हेतु अपने घर, परिसर और आसपास पानी इकट्ठा न होने दें। अपने घर के सिंक, गमले, हौज आदि में साफ-सफाई रखें। इसके साथ ही घरों की छतों पर अटाला या गंदगी न होने दें।

डेंगू मलेरिया फैलाने वाले मच्छर कहाँ पैदा होते हैं- छत पर रखी पानी की खुली टंकियों में, टूटे बर्तन, मटके, कुल्हड़, गमलों में एकत्र जल में, बेकार फेंके हुए टायरों में एकत्र जल में, बिना ढंके बर्तनों में एकत्र जल में, कूलर में एकत्र जल में, किचन गार्डन में रुका हुआ पानी, गमले, फूलदान, सजावट के लिए बने फव्वारे में एकत्र जल में।

ऐसे करें डेंगू से बचाव- डेंगू फैलाने वाले मच्छर रुके हुए पानी में पनपते हैं। इससे बचने के लिए टायर, प्लास्टिक कवर, फूलों के बर्तन, पालतू जानवरों के पानी के कटोरे आदि चीजों को ढकें। इन मच्छरों के प्रजनन के लिए उपलब्ध आवास को कम करने (स्थिर पानी को खाली करने से) डेंगू बुखार की रोकथाम में सहायता मिल सकती है। विशेष रूप से घनी आबादी और भीड़ वाले स्थानों में मच्छर निरोधकों का उपयोग करने से मच्छरों को आपसे दूर रखने में मदद मिल सकती है। कुछ क्षेत्रों की यात्रा करते समय और यहां तक कि जब आप घर पर हों, तो भी अपनी त्वचा पर मच्छर प्रतिरोधी क्रीम लगाएं। मच्छरों के काटने से बचने के लिए लंबी बाजू के कपड़े, मोटे पैंट, मोजे और सुरक्षित जूते पहनें। डेंगू बुखार की रोकथाम के लिए मच्छरदानी के नीचे सोने से मच्छरों के काटने से सुरक्षा मिल सकती है। रुके हुए पानी में मच्छर पनपते हैं। फूलों के बर्तनों को खाली करें, अपने पालतू जानवरों के पानी के कटोरे को साफ करें और बदलें, अपने घर के अंदर किसी भी पानी वाले पौधे को रखने से बचें तथा सुनिश्चित करें कि पानी से भरा हुआ हर बर्तन ढका हुआ हो।

डेंगू के सामान्य लक्षण- तेज बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों या जोड़ों में दर्द, जी मिचलाना, उल्टी आना, आंखों में दर्द होना, विभिन्न अंगों में सूजन।

डेंगू के गंभीर लक्षण- गंभीर पेट दर्द, लगातार उल्टी होना, मसूड़ों या नाक से खून आना, मल या उल्टी में खून आना, तेजी से सांस लेना, थकान, बेचैनी, त्वचा के नीचे ब्लीडिंग। इनमें से 2 या अधिक लक्षण दिखाई देने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। कई बार प्लेटलेट्स कम होने पर यह बुखार खतरनाक हो जाता है। मरीज की जान भी जा सकती है। गंभीर मामलों में गंभीर रक्तस्राव और शॉक सिंड्रोम हो सकता है, जिससे जान को खतरा हो सकता है।

यदि बुखार हो तो क्या करें- बुखार आने पर तुरंत रक्त की जांच कराएं। मलेरिया की पुष्टि होने पर पूरा उपचार लें। खाली पेट दवा कदापि न लें। मलेरिया हेतु खून की जांच व उपचार सुविधा समस्त शासकीय अस्पतालों पर निःशुल्क उपलब्ध है।

बिलौजी मेले की सुरक्षा व्यवस्था कटघरे में, झूले में 10 मिनट तक फंसे रहे बच्चे और महिलाएं

समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन की चेतावनी

आज की जनधारा

सिंगरौली । सिंगरौली जिला मुख्यालय से कुछ दूरी पर स्थित बिलौजी मेले को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मेले की संचालन अनुमति (परमिशन) समाप्त होने के बावजूद इसका संचालन लगातार जारी है। हालांकि इस मामले को लेकर जब एसडीएम सुरेश जाधव से जानकारी लिया गया तो उन्होंने बताया कि मेरे पास इनका आवेदन आया है और में पटवारी को भेज कर जांच कर बात हूँ अगर नियमो के विपरीत पाए जाते हैं तो उन पर ठोस कार्रवाई की जाएगी , ऐसे में लोगों ने प्रशासन से पूरे मामले की जांच कर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि मेले में प्रतिदिन बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और युवा पहुंच रहे हैं, लेकिन सुरक्षा मानकों और प्रशासनिक नियमों के पालन को लेकर गंभीर लापरवाही दिखाई दे रही है। उनका आरोप है कि यदि समय रहते व्यवस्थाओं की समीक्षा नहीं की गई तो भविष्य में कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है।

झूले में फंसे रहे लोग, मची अफरा-तफरी – प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हाल ही में मेले में संचालित एक झूले के दौरान अचानक बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। बिजली जाने से झूला हवा में ही रुक गया और उसमें बैठे बच्चे, महिलाएं एवं अन्य लोग करीब दस मिनट तक फंसे रहे। इस दौरान मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और परिजन अपने बच्चों को सुरक्षित नीचे उतारने की मांग करते रहे। बाद में बिजली आपूर्ति बहाल होने पर झूले को दोबारा संचालित कर लोगों को सुरक्षित उतारा गया। घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन इसने सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं।

'मौत का कुआं' भी चर्चा में

मेले में संचालित 'मौत का कुआं' भी इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। स्थानीय सूत्रों का दावा है कि प्रदर्शन में उपयोग किए जा रहे कुछ वाहनों के फिटनेस, प्रदूषण प्रमाणपत्र (पीयूसी) तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजों को लेकर सवाल हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। लोगों का कहना है कि संबंधित विभागों को वाहनों एवं सुरक्षा मानकों की जांच कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

सुरक्षा और अनुमति पर उठे प्रश्न

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि मेले का संचालन वैध अनुमति के साथ किया जा रहा है तो संबंधित अनुमति, विद्युत सुरक्षा प्रमाणपत्र, अग्निशमन व्यवस्था, झूलों की तकनीकी जांच और अन्य आवश्यक दस्तावेज सार्वजनिक किए जाने चाहिए। वहीं यदि अनुमति की अवधि समाप्त हो चुकी है तो यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि मेला किस आधार पर संचालित हो रहा है।

संयुक्त जांच की मांग

स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन, पुलिस, नगर निगम, विद्युत विभाग, परिवहन विभाग और अग्निशमन विभाग से मेले का संयुक्त निरीक्षण कर सभी सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि मेले में आने वाले लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और किसी भी प्रकार की लापरवाही पर नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।

भाजपा मंडल जयंत के शक्ति केंद्र-20 की संगठनात्मक बैठक संपन्न, बूथ सशक्तिकरण पर मंथन

आज की जनधारा

सिंगरौली । सिंगरौली भारतीय जनता पार्टी मंडल जयंत के शक्ति केंद्र क्रमांक-20 की संगठनात्मक बैठक सोमवार को आयोजित की गई। बैठक में रीवा संभाग के संगठन प्रभारी विजय दुबे की विशेष उपस्थिति रही। इस दौरान संगठन को बूथ स्तर तक और अधिक मजबूत बनाने, आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों की तैयारियों तथा कार्यकताओं की सक्रिय भागीदारी को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत उसका मजबूत संगठन और समर्पित कार्यकर्ता हैं। इसलिए प्रत्येक बूथ और शक्ति केंद्र को और अधिक सक्रिय एवं सशक्त बनाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है। साथ ही आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए कार्यकताओं से पूरी सक्रियता के साथ कार्य करने का आह्वान किया गया। बैठक के दौरान संगठन के विस्तार, जनसंपर्क अभियान, बूथ प्रबंधन तथा पार्टी की नीतियों एवं विचारों को जन-जन तक पहुंचाने की रणनीति पर भी विस्तार से चर्चा की गई। कार्यकताओं ने संगठन की मजबूती और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए पूर्ण समर्पण एवं सक्रियता के साथ कार्य करने का संकल्प भी लिया। बैठक में सिंगरौली जिलाध्यक्ष सुंदर लाल शाह, जिला संगठन प्रभारी विनोद यादव, सिंगरौली विधायक रामनिवास शाह, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य प्रेमवती खैरवार, जिला उपाध्यक्ष एवं मंडल प्रभारी पूनम गुप्ता, मंडल अध्यक्ष कमलेश वर्मा, नगर निगम अध्यक्ष देवेश पांडेय, सीधी जिला संगठन प्रभारी नरेंद्र त्रिपाठी सहित मंडल पदाधिकारी, शक्ति केंद्र के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

'सेफ्टी फर्स्ट' का संदेश, जेपी पावर में सुरक्षा सप्ताह के समापन पर 33 कर्मचारी सम्मानित

आज की जनधारा

सिंगरौली। सिंगरौली जिले में जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड (जेपीवीएल) निगरी प्लांट में 6 से 11 जुलाई 2026 तक आयोजित सिंगरौली सुरक्षा सप्ताह का समापन शनिवार को पुरस्कार वितरण समारोह के साथ हुआ। समापन समारोह के मुख्य अतिथि एम.वी.आर. रेड्डी (सीओपी) ने विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता 33 प्रतिभागियों को सम्मानित किया तथा कार्यस्थल पर सुरक्षा मानकों का पालन करने का संदेश दिया। अपने संबोधन में एम.वी.आर. रेड्डी ने कहा कि प्रत्येक कर्मचारी को किसी भी कार्य की शुरूआत से पहले संभावित जोखिमों की पहचान कर उनके निवारण की योजना के अनुसार कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारियों को निर्धारित स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन करते हुए 'सेफ्टी फर्स्ट' की भावना के साथ कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुरक्षा केवल एक विभाग की नहीं, बल्कि लाइन वर्कर, सुपरवाइजर, इंजीनियर, मैनेजर सहित प्रत्येक कर्मचारी की सामूहिक जिम्मेदारी है। सहायक महाप्रबंधक (सुरक्षा) अरुण कुमार उपाध्याय ने सुरक्षा सप्ताह के दौरान आयोजित गतिविधियों की जानकारी देते हुए बताया कि कर्मचारियों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से फायर ड्रिल प्रतियोगिता, सेफ्टी पोस्टर प्रतियोगिता, सेफ्टी स्लोगन प्रतियोगिता, 'नो योर पीपीई' प्रतियोगिता, अंतर विभागीय हाउसकीपिंग प्रतियोगिता तथा ऑन-द-स्पॉट आईएमएस एवं सेफ्टी क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गईं। उन्होंने बताया कि सुरक्षा सप्ताह के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में 429 कर्मचारियों ने भाग लेकर सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की। वहीं 8 जुलाई को आयोजित ऑन-द-स्पॉट आईएमएस एवं सेफ्टी क्विज प्रतियोगिता में 75 प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। समापन समारोह में विभिन्न प्रतियोगिताओं के 33 विजेताओं को मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए। कार्यक्रम में डॉ. एस.एन. दुबे (एवीपी), ए.के. श्रीवास्तव (एडवाइजर-मानव संसाधन), डी.के. सिंह (वरिष्ठ उपाध्यक्ष-ओ एंड एम), नवीन तिंगुरिया (उपाध्यक्ष-ई एंड आई), बी.के. झा (उपाध्यक्ष-एस एंड पी), ए.के. सिंह (वरिष्ठ महाप्रबंधक-बॉयलर मेंटेनेंस), विक्रम सिंह गहरवार (वरिष्ठ महाप्रबंधक-जेएनसीजीयू), एम. मुरलीकृष्णा (प्लांट हेड-पावरमेक), निखिल तिवारी (प्रबंधक-सुरक्षा) सहित प्लांट के वरिष्ठ अधिकारी, संविदाकारों के प्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे।

सरकारी निर्माण में गुणवत्ता से समझौता? सड़क, पुलिया और तालाब निर्माण पर ग्रामीणों ने उठाए सवाल

आज की जनधारा

सिंगरौली । सिंगरौली जिले में जनपद पंचायत वैढ़न अंतर्गत ग्राम पंचायत ढेंकी में चल रहे विकास कार्यों की गुणवत्ता को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ग्रामीणों और पूर्व जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया है कि पंचायत में निमार्णाधीन सड़क, पुलिया तथा हाल ही में निर्मित जोगिया तालाब की सीढ़ियों में मानकों के विपरीत सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। शिकायत के बाद पंचायत इंजीनियर ने संबंधित पुलिया निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से रुकवा दिया है और तकनीकी जांच कराने की बात कही है। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत क्षेत्र में बन रही सड़क और पुलिया के निर्माण में भस्सी (फ्लाई ऐश अवशेष), अमानक गिट्टी और रेत का उपयोग किया जा रहा है। उनका कहना है कि यदि निर्माण कार्यों में निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया गया तो ये संरचनाएं लंबे समय तक टिकाऊ नहीं रहेंगी और सरकारी धन का भी दुरुपयोग होगा।

ग्रामीणों ने प्रशासन से की निष्पक्ष जांच की मांग – मामले को लेकर ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और जनपद पंचायत से सड़क, पुलिया और जोगिया तालाब की सीढ़ियों की स्वतंत्र तकनीकी जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि निर्माण कार्यों में उपयोग की गई सामग्री के नमूनों की प्रयोगशाला में जांच कराई जाए और यदि अनियमितता सिद्ध होती है तो दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए।

पुलिया में 8 एमएम सरिया लगाने का आरोप

ग्राम पंचायत के पूर्व पंच राजलाल शाह ने आरोप लगाया कि लगभग 5 लाख रुपये की लागत से निर्मित की जा रही पुलिया में निर्धारित मानकों के अनुरूप सरिया का उपयोग नहीं किया जा रहा है। उनका दावा है कि पुलिया निर्माण में 8 एमएम की सरिया लगाई जा रही थी, जिससे निर्माण की मजबूती पर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि निर्माण में भस्सी का उपयोग किया जा रहा है। राजलाल शाह ने मांग की है कि पुलिया के निर्माण में उपयोग की गई सामग्री और तकनीकी मानकों की स्वतंत्र जांच कराई जाए, ताकि वास्तविक स्थिति सामने आ सके।

तालाब की सीढ़ियों पर भी उठे सवाल

पूर्व पंच ने जोगिया तालाब में हाल ही में लगभग 5 लाख रुपये की लागत से निर्मित सीढ़ियों की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि इस निर्माण कार्य में भी भस्सी का उपयोग किया गया है। उनका कहना है कि सड़क, पुलिया और तालाब की सीढ़ियों सहित पंचायत में हाल ही में हुए सभी निर्माण कार्यों की तकनीकी जांच कराई जानी चाहिए।

शिकायत के बाद इंजीनियर ने रुकवाया निर्माण

मामले में जब पंचायत इंजीनियर सोनल श्रीवास्तव से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि गुणवत्ताविहीन निर्माण की शिकायत मिलने के बाद संबंधित पुलिया निर्माण कार्य को तत्काल रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि निर्माण सामग्री और तकनीकी मानकों की जांच कराई जाएगी। यदि जांच में शिकायतें सही पाई जाती हैं तो संबंधित ठेकेदार या जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी तथा निर्माण कार्य मानकों के अनुरूप कराया जाएगा।

पुलिस तबादलों के बाद भी तीन अहम इकाइयों में नहीं हुई नियमित प्रभारियों की तैनाती

आज की जनधारा

सिंगरौली । सिंगरौली जिले में हाल ही में पुलिस विभाग में हुए तबादलों और नई पदस्थापनाओं के बावजूद जियावन थाना, यातायात थाना और जयंत पुलिस चौकी में अब तक नियमित प्रभारी की नियुक्ति नहीं हो सकी है। लंबे समय से इन महत्वपूर्ण इकाइयों का संचालन प्रभारी व्यवस्था के तहत किया जा रहा है, जिससे पुलिसिंग और प्रशासनिक कार्यों की प्रभावशीलता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले जिले के कई थानों और चौकियों में निरीक्षकों एवं चौकी प्रभारियों की पदस्थापना की गई थी, लेकिन जियावन थाना और यातायात थाना में निरीक्षक स्तर के अधिकारी की नियुक्ति अब तक नहीं हुई है। वहीं जयंत पुलिस चौकी भी नियमित प्रभारी से वंचित है। वर्तमान में इन स्थानों का संचालन उप निरीक्षक (एसआई) स्तर के अधिकारियों के माध्यम से किया जा रहा है। संवेदनशील क्षेत्रों में बढ़ी चुनौती जियावन थाना सीमावर्ती एवं संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है, जबकि यातायात थाना पूरे जिले की ट्रैफिक व्यवस्था का संचालन करता है। वहीं जयंत पुलिस चौकी औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण कानून-व्यवस्था की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे में नियमित प्रभारी की अनुपस्थिति पुलिस व्यवस्था के लिए चुनौती बनती जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दुर्घटना, विवाद या अन्य गंभीर घटनाओं के दौरान निरीक्षक स्तर के अधिकारी की मौजूदगी कई बार त्वरित निर्णय और प्रभावी कार्रवाई के लिए आवश्यक होती है। ऐसे में स्थायी प्रभारी नहीं होने से कार्य प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है। पुलिस लाइन में निरीक्षक उपलब्ध, फिर भी पद खाली सूत्रों के अनुसार पुलिस लाइन में कुछ निरीक्षक वर्तमान में पदस्थ हैं, जिन्हें आवश्यकता अनुसार रिक्त थानों में नियुक्त किया जा सकता है। हाल ही में जिले से कई निरीक्षकों एवं उप निरीक्षकों के स्थानांतरण के बाद उन्हें कार्यमुक्त भी कर दिया गया, जबकि स्थानांतरण सूची के माध्यम से कुछ अधिकारियों की जिले में पदस्थापना भी हुई है। इसके बावजूद जियावन थाना, यातायात थाना और जयंत चौकी में नियमित प्रभारियों की नियुक्ति नहीं हो सकी है। तैनाती को लेकर चचाओं का बाजार गर्म पुलिस महकमे में इन रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर विभिन्न स्तरों पर चचाएं भी चल रही हैं। सूत्रों का कहना है कि कुछ महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति को लेकर कई अधिकारी दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि इस संबंध में पुलिस विभाग की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

कई महीनों से एनएच-39 पर खड़ी परित्यक्त बस, प्रशासन की चुप्पी पर उठे सवाल

आज की जनधारा

सिंगरौली । सिंगरौली राष्ट्रीय राजमार्ग-39 (एनएच-39) पर जियावन थाना क्षेत्र के खोभा स्थित सरस्वती विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार से करीब 200 मीटर की दूरी पर एक बस पिछले कई महीनों से सड़क किनारे खड़ी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से एक ही स्थान पर खड़ा यह वाहन अब दुर्घटना की आशंका बढ़ा रहा है, लेकिन संबंधित विभाग की ओर से इसे हटाने की दिशा में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। क्षेत्रवासियों के अनुसार यह मार्ग दिनभर व्यस्त रहता है। विद्यालय होने के कारण सुबह और दोपहर के समय बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं, अभिभावक और अन्य वाहन इस मार्ग से गुजरते हैं। ऐसे में सड़क किनारे लंबे समय से खड़ी बस दुर्घटना का कारण बन सकती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार इस संबंध में मौखिक रूप से शिकायत भी की गई, लेकिन अब तक स्थिति जस की तस बनी हुई है। उनका सवाल है कि क्या प्रशासन किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है, या फिर समय रहते इस संभावित खतरे को दूर किया जाएगा। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन, पुलिस और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से मांग की है कि सड़क किनारे खड़ी इस परित्यक्त बस को तत्काल हटाया जाए, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके।

बैढ़न जिला चिकित्सालय में जल्द स्थापित होगा ब्लड बैंक, मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत

आज की जनधारा

सिंगरौली । सिंगरौली जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल शुरू हुई है। जिला चिकित्सालय बैढ़न में जल्द ही नवीन ब्लड बैंक की स्थापना की जाएगी। सीधी संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉ. राजेश मिश्रा के प्रयासों के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। ब्लड बैंक की स्थापना से जिले के मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराने में सुविधा होगी तथा आपातकालीन परिस्थितियों में उपचार व्यवस्था और अधिक प्रभावी बन सकेगी। सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने गत माह मध्यप्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला से भोपाल में मुलाकात कर जिला चिकित्सालय बैढ़न में ब्लड बैंक स्थापित किए जाने का अनुरोध किया था। उन्होंने सिंगरौली जैसे औद्योगिक और तेजी से विकसित हो रहे जिले में बढ़ती आबादी तथा दुर्घटनाओं एवं गंभीर मरीजों की संख्या को देखते हुए ब्लड बैंक की आवश्यकता से अवगत कराया था। सांसद के अनुरोध पर स्वास्थ्य विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए ब्लड बैंक की स्थापना संबंधी आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। उम्मीद जताई जा रही है कि सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद जिला चिकित्सालय में आधुनिक सुविधाओं से युक्त ब्लड बैंक स्थापित कर दिया जाएगा। गंभीर मरीजों को मिलेगा सीधा लाभ ब्लड बैंक शुरू होने से सड़क दुर्घटनाओं, प्रसूति संबंधी जटिल मामलों, ऑपरेशन, थैलेसीमिया, एनीमिया सहित विभिन्न गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराया जा सकेगा। वर्तमान में कई बार मरीजों के परिजनों को रक्त की व्यवस्था के लिए अन्य जिलों का रुख करना पड़ता है या निजी स्तर पर प्रयास करने पड़ते हैं। नई सुविधा शुरू होने के बाद ऐसी परिस्थितियों में काफी राहत मिलने की संभावना है। स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर जोर सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने कहा कि सिंगरौली सहित पूरे संसदीय क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि आमजन को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और भविष्य में भी स्वास्थ्य अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए आवश्यक पहल जारी रहेगी। उन्होंने इस महत्वपूर्ण पहल के लिए उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके सहयोग से जिले को यह महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुविधा मिलने जा रही है।

'नन्हा-सा-दिल-एनसीएल' पहल के तहत छह दिवसीय क्रिटिकल केयर प्रशिक्षण शुरू

आज की जनधारा

सिंगरौली । सिंगरौली नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल ₹नन्हा-सा-दिल-एनसीएल₹ के अंतर्गत सोमवार को नेहरू शताब्दी चिकित्सालय (एनएससी) में छह दिवसीय नर्सिंग क्रिटिकल केयर एवं इकोकार्डियोग्राफी प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। यह प्रशिक्षण 13 से 18 जुलाई 2026 तक आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य चिकित्सकों एवं स्वास्थ्यकर्मियों के कौशल को उन्नत कर गंभीर मरीजों के उपचार की गुणवत्ता में सुधार लाना है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत सत्य साईं संजीवनी हॉस्पिटल के विशेषज्ञ एनसीएल के चिकित्सकों को 2-डी इकोकार्डियोग्राफी का प्रशिक्षण दे रहे हैं। वहीं, मेट्रन, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल स्टाफ को क्रिटिकल केयर, रोगी की मूलभूत देखभाल, पोषण प्रबंधन, हृदय मॉनिटरिंग, चिकित्सा उपकरणों के सुरक्षित संचालन, वेंटिलेशन केयर, ऑक्सीजन फ्लो मीटर एवं इन्फ्यूजन पंप के संचालन, सीपीआर (कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन) तथा बेसिक लाइफ सपोर्ट (बीएलएस) जैसी महत्वपूर्ण आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर निदेशक (मानव संसाधन) मनीष कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि एनसीएल सिंगरौली क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम नेहरू शताब्दी चिकित्सालय की क्रिटिकल केयर क्षमताओं को और अधिक मजबूत करेगा, जिससे न केवल एनसीएल कर्मियों बल्कि आसपास के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लोगों को भी बेहतर चिकित्सा सुविधाओं का लाभ मिलेगा। उन्होंने चिकित्सा सेवाओं से जुड़े सभी अधिकारियों, चिकित्सकों एवं स्वास्थ्यकर्मियों के सेवा-भाव और समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि आधुनिक चिकित्सा तकनीकों का प्रशिक्षण मरीजों को समय पर बेहतर उपचार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा सेवाएं (एनएससी) डॉ. विवेक खरे, सीएमएस (प्रभारी) डॉ. मंजरी मेहता, महाप्रबंधक (सीएसआर) राजीव रंजन, विभागाध्यक्ष (नेत्र विभाग) डॉ. श्री देवी दास सहित एनसीएल के वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। वहीं सत्य साईं संजीवनी हॉस्पिटल की ओर से सौम्या जंध्याला, डॉ. यामिनी बाथम, गिरिजा शंकर सातम, सरोजिनी मंजूनाथ, नंद उदय कुलकर्णी एवं गौरव दत्त ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहभागिता की।

प्रिंट रेट से महंगी बिक रहीं स्कूल की किताबें? निजी स्कूलों और बुक सेंटरों पर उठे सवाल

आज की जनधारा

सिंगरौली । सिंगरौली जिले में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होते ही निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों ने किताबों की खरीद-फरोख्त को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। आरोप है कि कुछ निजी विद्यालयों द्वारा छात्रों को चुनिंदा बुक सेंटरों से ही पुस्तकें खरीदने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से बाध्य किया जा रहा है। इतना ही नहीं, कई अभिभावकों का दावा है कि इन बुक सेंटरों पर पुस्तकों की बिक्री प्रिंट रेट (एमआरपी) से अधिक कीमत पर की जा रही है, जिससे उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। अभिभावकों के अनुसार शहर के एक निजी बुक सेंटर पर कक्षा पांचवीं के विद्यार्थियों की पुस्तकों का पूरा सेट लगभग 4 हजार रुपये में बेचा जा रहा है। उनका आरोप है कि कई पुस्तकों पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से अधिक राशि वसूली गई। साथ ही खरीदारी के बाद अधिकांश ग्राहकों को न तो विधिवत जीएसटी बिल दिया गया और न ही पक्की रसीद। कई मामलों में केवल साधारण पर्ची पर राशि लिखकर दे दी गई।

केवल तय दुकान से खरीदने का दबाव– अभिभावकों का कहना है कि संबंधित निजी विद्यालयों द्वारा पुस्तकों की खरीद के लिए कुछ निश्चित बुक सेंटर तय किए गए हैं। यदि कोई अभिभावक दूसरी दुकान से किताबें खरीदना चाहता है तो वहां पूरा सेट उपलब्ध नहीं कराया जाता। इससे अभिभावकों के सामने निर्धारित दुकान से ही खरीदारी करने की मजबूरी पैदा हो जाती है। अभिभावकों का आरोप है कि इस व्यवस्था के कारण प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाती है और मनमाने दाम वसूले जाते हैं।

प्रशासन के निदेशों पर उठे सवाल

गौरतलब है कि जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग पूर्व में निजी विद्यालयों को स्पष्ट निर्देश जारी कर चुके हैं कि किसी भी अभिभावक को किसी एक विशेष दुकान से किताबें खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। साथ ही विद्यालयों में उपयोग होने वाली पुस्तकें विभिन्न दुकानों पर उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए थे, ताकि अभिभावकों को विकल्प मिल सके और उचित मूल्य पर पुस्तकें उपलब्ध हों। इसके बावजूद यदि अभिभावकों के आरोप सही हैं तो यह प्रशासनिक निदेशों के पालन पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

बढ़ता जा रहा शिक्षा का खर्च

अभिभावकों का कहना है कि निजी स्कूलों की फीस, यूनिफॉर्म, परिवहन और अन्य शुल्क पहले ही उनकी आर्थिक क्षमता पर भारी पड़ रहे हैं। ऐसे में किताबों के नाम पर अधिक कीमत वसूले जाने से मध्यमवर्गीय परिवारों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। उनका कहना है कि शिक्षा को व्यवसाय का माध्यम नहीं बनाया जाना चाहिए।

निष्पक्ष जांच की मांग

अभिभावकों ने जिला प्रशासन, जिला शिक्षा अधिकारी और संबंधित विभागों से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यह जांच की जानी चाहिए कि क्या किताबें वास्तव में एमआरपी से अधिक कीमत पर बेची जा रही हैं, क्या विद्यालय किसी विशेष बुक सेंटर से खरीदारी के लिए दबाव बना रहे हैं तथा क्या बिक्री के दौरान बिल और कर संबंधी नियमों का पालन किया जा रहा है। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े जानकारों का भी मानना है कि यदि किसी विद्यालय और बुक सेंटर के बीच ऐसी कोई व्यवस्था है।

मैहर में 14 जुलाई को पूर्ण होगी सांसद बंटी विवेक साहू की पदयात्रा, माँ शारदा के दर्शन कर करेंगे पूजा-अर्चना

आज की जनधारा

भोपाल/मैहर। 1 जुलाई से आस्था, श्रद्धा और जनसेवा के संकल्प के साथ प्रारंभ हुई सांसद बंटी विवेक साहू की मैहर पदयात्रा 14 जुलाई को अपने अंतिम पड़ाव पर पहुँचेगी। इस अवसर पर प्रातः 11 बजे माँ शारदा धाम, मैहर में माँ शारदा के पावन दर्शन एवं विधिवत पूजा-अर्चना की जाएगी। सांसद बंटी विवेक साहू ने बताया कि पूजा-अर्चना के दौरान अपने संसदीय क्षेत्र, प्रदेश तथा समस्त देशवासियों की सुख-समृद्धि, शांति और खुशहाली की मंगलकामना की जाएगी। उन्होंने इसे आस्था, जनसेवा और लोककल्याण के संकल्प से जुड़ी आध्यात्मिक यात्रा बताया। सांसद ने सभी श्रद्धालुओं, माताओं-बहनों, युवा साथियों एवं क्षेत्रवासियों से इस पावन अवसर पर अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर माँ शारदा का आशीर्वाद प्राप्त करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह अवसर श्रद्धा, भक्ति और जनसहभागिता का प्रतीक होगा। पदयात्रा के समापन अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं एवं समर्थकों के शामिल होने की संभावना है।

जाली प्रमाण-पत्रों से सरकारी नौकरी का खेल खत्म, राजगढ़ में 9 शिक्षक सेवा से बर्खास्त

हरीश भारतीय

राजगढ़ । जिले में फर्जी शैक्षणिक दस्तावेजों के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल करने वालों के खिलाफ शिक्षा विभाग ने अब तक की सबसे बड़ी विभागीय कार्रवाई करते हुए 9 प्राथमिक शिक्षकों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी हैं। कई स्तरों पर हुई जांच, शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों के आधिकारिक सत्यापन और व्यक्तिगत सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह सख्त निर्णय लिया गया। विभाग ने पूरे प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत आपराधिक कार्रवाई की अनुशंसा करते हुए विस्तृत प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक राजगढ़ को भी भेज दिया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा के निर्देशन में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्राप्त शिकायतों की गंभीरता से जांच कराई गई। नियुक्ति एवं संविलियन के समय संबंधित शिक्षकों द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों का सत्यापन माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी (केएसओयू), मैसूर से कराया गया। जांच एजेंसियों से प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर गठित समिति ने नियुक्ति अभिलेख, सेवा रिकॉर्ड तथा अन्य दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण कर अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। विभाग ने कार्रवाई से पहले सभी संबंधित शिक्षकों को व्यक्तिगत सुनवाई का पूरा अवसर दिया। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजों एवं पक्ष का परीक्षण किया गया, लेकिन संबंधित परीक्षा प्राधिकारियों से प्राप्त सत्यापन रिपोर्टों का कोई संतोषजनक खंडन प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इसके बाद जांच समिति की अनुशंसा और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सभी 9 शिक्षकों की सेवाएं तत्काल समाप्त करने के आदेश जारी कर दिए गए। कार्रवाई की जद में आए शिक्षकों में विकासखंड ब्यावरा के विभिन्न शासकीय विद्यालयों में पदस्थ रमेशचंद्र यादव, पवन शर्मा, सुनील कुमार प्रजापति, हेमंत शर्मा, सावित्री दांगी, बने सिंह लववंशी, भारत सिंह यादव, हरिप्रसाद लववंशी तथा विकासखंड नरसिंहगढ़ के शासकीय प्राथमिक विद्यालय छापरीकलां में पदस्थ हिम्मत सिंह मीना शामिल हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने स्पष्ट किया कि शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले शैक्षणिक दस्तावेजों की सत्यता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। फर्जी, कूटरचित अथवा भ्रामक दस्तावेजों के आधार पर सरकारी नौकरी प्राप्त करने वालों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ आपराधिक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप पारदर्शी, निष्पक्ष और विश्वसनीय नियुक्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भविष्य में भी ऐसे मामलों पर लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

- 9 प्राथमिक शिक्षकों की सेवाएं तत्काल समाप्त।
- शिकायतों के बाद हुई विस्तृत जांच। माध्यमिक शिक्षा मंडल और केएसओय से कराया गया दस्तावेजों का सत्यापन।
- व्यक्तिगत सुनवाई के बाद लिया गया अंतिम निर्णय।
- पुलिस अधीक्षक को आपराधिक कार्रवाई के लिए भेजा गया प्रतिवेदन।
- फर्जी दस्तावेजों पर शासन की जीरो टॉलरेंस नीति लागू।

16 एवं 17 जुलाई को जिला कोषालय खरगोन में लगेगा IFMIS CARES CAMP

डीडीओ की तकनीकी समस्याओं का होगा त्वरित समाधान

खरगोन । जिले के समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) की आईएफएमआईएस से संबंधित तकनीकी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिला कोषालय खरगोन में 16 एवं 17 जुलाई को दो दिवसीय उअफएर आयोजित किया जाएगा। यह विशेष पहल नवागत आयुक्त कोष एवं लेखा, भोपाल श्री अमन बैस के मार्गदर्शन में स्थानीय स्तर पर की जा रही है, जिससे अधिकारियों की समस्याओं का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित हो सके। इस संबंध में प्रभारी कलेक्टर श्रीमती रेखा राठौर ने समय-सीमा बैठक के दौरान जिले के सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को कैंप में अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर पंजीयन कराने के निर्देश दिए हैं। वरिष्ठ जिला कोषालय अधिकारी श्रीमती हेमलता शर्मा ने बताया कि कैंप के दौरान डीडीओ को जिला कोषालय में उपस्थित होकर अपना पंजीयन कराना होगा। इसके पश्चात आईएफएमआईएस पोर्टल से जुड़ी पूर्व से लंबित एवं नवीन तकनीकी समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाएगा।

चावल घोटाले की आंच मध्य प्रदेश तक, एफसीआई में हड़कंप; पांच अधिकारी निलंबित, बालाघाट में 20 ट्रक जब्त

नार्थ-ईस्ट राज्यों के लिए रखे गए चावल की बिक्री में गड़बड़ी का मामला

- बालाघाट में पीडीएस चावल की हेराफेरी की जांच तेज, 13 आरोपी नामजद

श्रीकांत त्रिवेदी

भोपाल/बालाघाट। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) और केंद्र सरकार की खाद्यान्न वितरण व्यवस्था से जुड़े बहुचर्चित चावल घोटाले की जांच अब तेज होती जा रही है। नार्थ-ईस्ट राज्यों के लिए सुरक्षित रखे गए चावल की बिक्री में अनियमितता सामने आने के बाद भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) में हड़कंप मच गया है। मामले में एफसीआई के पांच अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क की पड़ताल कर रही हैं। सूत्रों के अनुसार, दिल्ली से शुरू हुई कार्रवाई का असर अब मध्य प्रदेश तक पहुंच सकता है। जांच एजेंसियां उन अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका भी खंगाल रही हैं, जिनकी जिम्मेदारी भंडारण, परिवहन और वितरण व्यवस्था से जुड़ी थी। ऐसे में भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों के अधिकारी-कर्मचारी भी कार्रवाई की जद में आ सकते हैं। इधर, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में ओपन मार्केट सेल स्कीम (ओएमएसएस) के तहत चावल वितरण में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। जांच में पाया गया कि सरकारी योजना के तहत वितरित किए जाने वाले चावल के परिवहन और बिक्री में बड़े स्तर पर गड़बड़ी की गई। मामले में अब तक चार आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि दो आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं। प्रकरण में कुल 13 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। जांच के दौरान प्रशासन और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 20 ट्रकों को जब्त किया है, जिनका उपयोग कथित रूप से चावल के अवैध परिवहन में किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किया गया है, जो पूरे नेटवर्क, परिवहन श्रृंखला और अधिकारियों की भूमिका की जांच कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ेगी, वैसे-वैसे कई नए नाम सामने आ सकते हैं। खाद्यान्न वितरण प्रणाली में हुई इस कथित गड़बड़ी को लेकर केंद्र और राज्य स्तर पर भी रिपोर्ट तलब की गई है। यदि जांच में लापरवाही या मिलीभगत प्रमाणित होती है तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि गरीबों और जरूरतमंदों के लिए निर्धारित खाद्यान्न में किसी भी प्रकार की हेराफेरी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े करती है। ऐसे में इस मामले की निष्पक्ष और व्यापक जांच पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

बैंक अधिकारियों के वेतन समझौते की मांग समिति में रवि कुमार बने सह-अध्यक्ष

अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ ने दी जिम्मेदारी, दो दिवसीय भोपाल प्रवास के दौरान करेंगे अधिकारियों से संवाद

आज की जनधारा

भोपाल। कैनरा बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन (सीबीओए) के उपाध्यक्ष के. के. त्रिपाठी ने जानकारी दी कि अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ (एआईबीओसी) ने आगामी नवंबर 2027 के वेतन समझौते के लिए तैयार किए जा रहे मांग-पत्र को भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु गठित समिति में सीबीओए के महासचिव के. रवि कुमार को सह-अध्यक्ष नियुक्त किया है। उन्होंने बताया कि श्री रवि कुमार 12 और 13 जुलाई को दो दिवसीय भोपाल प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे संगठनात्मक बैठकों में भाग लेने के साथ बैंक अधिकारियों से संवाद करेंगे तथा आगामी वेतन समझौते से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। श्री त्रिपाठी ने कहा कि यह नियुक्ति पूरे बैंकिंग अधिकारी वर्ग के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि श्री रवि कुमार के नेतृत्व में बैंक अधिकारियों के हितों की प्रभावी पैरवी होगी और आगामी वेतन समझौते में कर्मचारियों की अपेक्षाओं को मजबूती से रखा जाएगा।

युवा एथलीट्स को बढ़ावा देने के लिए भोपाल में लॉन्च किया एनर्जाइज इंडिया कैंपेन

आज की जनधारा

भोपाल। डाबर की ओर से इंस्टेन्ट एनर्जी ड्रिंक डाबर ग्लुकोज ने युवाओं में खेल प्रतिभा को बढ़ावा देने तथा देश भर की स्पोर्ट्स एकेडमियों के युवा एथलीट्स को एनर्जी एवं स्टैमिना के महत्व पर जागरुक बनाने के लिए एक कैंपेन ह्यएनर्जाइज इंडियाह्न का लॉन्च किया है। इस कैंपेन के तहत डाबर ग्लुकोज ने आज आर डी स्पोर्ट्स अकादमी, भोपाल. में एनर्जी एवं स्टैमिना मैनेजमेन्ट पर एक विशेष जागरुकता सत्र का आयोजन किया। सत्र के दौरान एथलीट्स को बताया गया कि किस तरह से वे खेल के दौरान अपने परफोर्मेन्स को बेहतर बना सकते हैं और अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। डाबर ने इस एकेडमी के टॉप एथलीट्स को सम्मानित भी किया। हमें खुशी है कि युवा एथलीट्स को एनर्जी एवं स्टैमिना के महत्व पर जागरुक बनाने के लिए हम ह्यएनर्जाइज इंडियाह्न कैंपेन लेकर आए हैं। यह कैंपेन उन्हें अपने खेल में एनर्जी के साथ बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए प्रेरित करेगा। डाबर एथलीट्स, खेल प्रशंसकों और एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाने वाले लोगों के लिए एक परफेक्ट ब्रांड है। डाबर ग्लुकोज इंस्टेंट एनर्जी देता है, ऐसे में यह विशेष रूप से उन एथलीट्स के लिए उपयुक्त है जो नियमित रूप से फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं। भोपाल स्थित संस्कार भारती विद्यापीठ हायर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान डाबर इंडिया लिमिटेड के मार्केटिंग हेड - हेल्थ सप्लीमेंट्स, श्री बिनीत कुमार ने यह बात कही। श्री ब्यास आनंद, हेड झ्र सीएसआर एवं कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस, डाबर इंडिया लिमिटेड ने कहा ह्यडाबर ग्लुकोज हमेशा से युवाओं को स्वस्थ एवं सक्रिय जीवनशैली जीने के लिए प्रेरित करता रहा है। युवा एथलीट्स के साथ यह साझेदारी इसी लक्ष्य की दिशा में एक और कदम है। अपने ताजगी से भरे स्वाद और इंस्टेन्ट एनर्जी के साथ डाबर ग्लुकोज युवा एथलीट्स की एनर्जी बनाए रखने के लिए बेहतरीन विकल्प है, जिसे अपनाकर वे अपना सर्वश्रेष्ठ परफोर्मेन्स दे सकते हैं। ऋषि रघुवंशी, आर डी स्पोर्ट्स अकादमी, भोपाल ने कहा - ने एनर्जी सैशन के दौरान युवा एथलीट्स को बताया गया कि खेल में अच्छा परफोर्मेन्स देने के लिए पोषण और हाइड्रेशन बहुत जरूरी है।

एलएनसीटी वर्ल्ड स्कूल में छात्र परिषद का शपथ ग्रहण समारोह

आज की जनधारा

भोपाल। एलएनसीटी वर्ल्ड स्कूल, में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए छात्र परिषद के गठन हेतु एक गरिमामयी 'शपथ ग्रहण समारोह' (इन्वेस्टिचर सेरेमनी) का आयोजन किया गया। यह आयोजन छात्र नेतृत्व और जिम्मेदारी के एक नए अध्याय की शुरूआत का प्रतीक रहा। समारोह के मुख्य अतिथि *जेएनसीटी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के डॉ. गोविंद भार्गव स्कूल मैनेजर शोभा चौकसे प्राचार्य चैतन्य सक्सेना के द्वारा नवनिर्वाचित छात्र पदाधिकारियों को बैज और सैश प्रदान कर सम्मानित किया। इसके बाद मुख्य अतिथि ने सभी युवा पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि और प्रबंधन के वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अनुशासन, सत्यनिष्ठा, नेतृत्व, सेवा और जिम्मेदारी के मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। इस गरिमामयी समारोह में स्कूल प्रबंधन के सदस्य, शिक्षक, अभिभावक और बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम ने युवा नेताओं में आत्मविश्वास, टीम वर्क और प्रतिबद्धता की एक नई ऊर्जा का संचार किया।

आचार्य सुबल सागर महाराज के शिष्यों द्वारा पाठशाला के बच्चो को सात्विक जीवन शैली की शिक्षा

भोपाल। आचार्य सुबल सागर महाराज के शिष्य मुनि अभेद सागर महाराज मुनि अगर्भ सागर महाराज के सानिध्य में शंकराचार्य नगर जैन मंदिर में भारतीय संस्कृति संस्कारों की रक्षा जीवन को सही दिशा ओर दशा तय करने के लिए उचित मार्गदर्शन दिया गया, पाठशाला के बच्चो ने भगवान पार्श्वनाथ का अभिषेक पूजा अर्चना की, सभी के मंगल मय जीवन की मंगल कामना के लिए नवकार महामंत्र भक्तामर का वाचन किया, मंदिर समिति अध्यक्ष सुनील अरिहंत ने बताया जिनालय में बच्चों को संस्कार प्रदान करने के लिए विशेष कक्षा लगती है, मुनि श्री ने कहा जीवन तो सभी जीते हैं, जीवन वही सार्थक है जो अपने साथ दूसरों के लिए मन में सम भाव रखे, इस अवसर पर श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर शंकराचार्य नगर ,अध्यक्ष सुनील जैन अरिहंत, सुरेश जैन समरधा महामंत्री रितेश जैन नवकार ,कोषाध्यक्ष प्रेम कुमार जैन, मंत्री नितिन जैन उप मंत्री जितेंद्र जैन बाहुबली, उपाध्यक्ष राजकुमार जैन, दीपक जैन गुजरात रोडलाइन,सुभाष जैन दिनेश जैन,अशोक जैन, प्रफुल्ल जैन, पवन जैन राजेश जैन महिला मंडल अध्यक्ष नीता जैन, नीतू जैन,रीना जैन बालिका मंडल सुबलसागर बालक के सदस्य मौजूद थे आचार्य सुबल सागर चातुर्मास स्थापना में अनेक भक्त लखनऊ जाएंगे* सन्मति सुबल जैन श्रुत सेवा संघ के अध्यक्ष अभिषेक जैन ने बताया आचार्य सुबल सागर महाराज के चतुर्मास स्थापना में अनेक भक्त 29 जुलाई को लखनऊ जाएंगे, विदित हे भोपाल के अनेक भक्त आचार्य सुबल सागर महाराज के आशीर्वाद से भोपाल में सामाजिक सहयोग जीव दया के कार्य कर रहे हे।

सेफ क्लिक हैकाथॉन 2.0 में एसजीएसयू के विद्यार्थियों का शानदार प्रदर्शन

साइबर सुरक्षा नवाचार प्रतियोगिता में टीम ऑब्सीडियन ने जीता द्वितीय रनर-अप पुरस्कार

आज की जनधारा

भोपाल। स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी (एसजीएसयू) के विद्यार्थियों ने एक बार फिर नवाचार, तकनीकी दक्षता और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ाया है। मध्यप्रदेश पुलिस (रायसेन पुलिस) द्वारा सेफ क्लिक के अंतर्गत रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय (आरएनटीयू), भोपाल के सहयोग से आयोजित सेफ क्लिक हैकाथॉन 2.0 में एसजीएसयू के विद्यार्थियों ने साइबर सुरक्षा से जुड़ी वास्तविक चुनौतियों के अभिनव समाधान प्रस्तुत किए। प्रतियोगिता में एसजीएसयू की टीम ऑब्सीडियन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए द्वितीय रनर-अप का स्थान प्राप्त किया। टीम में प्रियांशु कुशवाहा (बीसीए झ्र साइबर सिक्योरिटी), ईशान चौधरी (बीसीए झ्र फुल स्टैक) एवं यश प्रताप कुशवाहा (बीसीए झ्र फुल स्टैक) शामिल थे। टीम ने अपनी तकनीकी समझ, नवाचारपूर्ण सोच और उत्कृष्ट प्रस्तुति से निर्णायकों को प्रभावित किया। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय की दूसरी टीम ने भी प्रतियोगिता में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। इस टीम में लक्ष्य श्रीवास्तव (बी.टेक. सीएसई, तृतीय वर्ष), कार्तिक नायर, मुस्कान लाड़े (बीसीए साइबर सिक्योरिटी, द्वितीय वर्ष), श्रद्धा आंजने (बीसीए साइबर सिक्योरिटी, द्वितीय वर्ष) एवं तुलसी बरपेटिया (बीसीए एआई एवं मशीन लर्निंग, प्रथम वर्ष) शामिल रहे। विद्यार्थियों ने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में नवीन विचारों और व्यावहारिक समाधानों के माध्यम से अपनी तकनीकी क्षमता का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। इस अवसर पर स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति डॉ. सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा, आज साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे उभरते क्षेत्रों में व्यावहारिक अनुभव और नवाचार की सोच अत्यंत महत्वपूर्ण है। हैकाथॉन जैसे मंच विद्यार्थियों को वास्तविक समस्याओं पर कार्य करने, टीमवर्क विकसित करने और उद्योग की अपेक्षाओं के अनुरूप कौशल अर्जित करने का अवसर प्रदान करते हैं। हमें गर्व है कि हमारे विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा और तकनीकी दक्षता से विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया है। कुलगुरु डॉ. विजय सिंह ने कहा, ₹स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी उद्योग-उन्मुख और कौशल-आधारित शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार कर रही है। इस प्रकार की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों की सफलता उनके ज्ञान, मेहनत और विश्वविद्यालय की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रमाण है। कुलसचिव डॉ. सितेश कुमार सिन्हा ने कहा, ₹विश्वविद्यालय का उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल अकादमिक ज्ञान तक सीमित रखना नहीं, बल्कि उन्हें नवाचार, अनुसंधान और व्यावहारिक समस्या-समाधान की दिशा में प्रेरित करना है। ऐसी प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, तकनीकी दक्षता और नेतृत्व क्षमता का विकास करती हैं तथा उन्हें भविष्य के सफल साइबर सुरक्षा पेशेवर बनने के लिए तैयार करती हैं।

हिंदी से संवाद और संस्कृति से साक्षात्कार की अनूठी पहल

रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय में हुआ नौ दिवसीय 'राष्ट्रीय छात्र अध्ययन यात्रा' का भव्य शुभारंभ

- असम, मणिपुर, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, केरल, ओड़िशा, तमिलनाडु, आदि दस राज्यों के विद्यार्थी कर रहे हैं भागीदारी
- केंद्रीय हिंदी निदेशालय तथा विश्व रंग, आर.एन.टी.यू., एस.जी.एस.यू., बी.यू. का संयुक्त आयोजन

आज की जनधारा

भोपाल। केंद्रीय हिंदी निदेशालय, शिक्षा मंत्रालय (उच्च शिक्षा विभाग), भारत सरकार नई दिल्ली, विश्व रंग फाउंडेशन, रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, स्कोप ग्लोबल स्किल्स विश्वविद्यालय एवं सतत शिक्षा विभाग, बरकत उल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल के संयुक्त तत्वावधान में नौ दिवसीय राष्ट्रीय छात्र अध्ययन यात्रा का आयोजन 13झ्र21 जुलाई 2026 तक किया जा रहा है। इसमें असम, मणिपुर, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, केरल, ओड़िशा, तमिलनाडु, आदि दस हिंदीतरभाषी राज्यों के पचास विद्यार्थी रचनात्मक रूप से भागीदारी कर रहे हैं। छात्र अध्ययन यात्रा का मुख्य संयोजन विश्व रंग फाउंडेशन, रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा किया गया है। उद्घाटन समारोह की विशिष्ट अतिथि हिंदी निदेशालय, भारत सरकार की सहायक निदेशक सुश्री तमन्ना रानी ने अपने उद्बोधन में कहा कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय, शिक्षा मंत्रालय (उच्च शिक्षा विभाग), भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा प्रति वर्ष हिंदीतरभाषी क्षेत्रों में स्थित विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की कक्षाओं में हिंदी भाषा एवं साहित्य का अध्ययन कर रहे छात्र/छात्राओं की अध्ययन यात्राएँ आयोजित की जाती हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रत्येक छात्र अध्ययन यात्रा दल को हिंदीभाषी क्षेत्रों में स्थित विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं में अलग-अलग तीन-तीन स्थानों पर ले जाया जाता है। इन संस्थानों में आपसी सहभागिता पूर्ण रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से हिंदी के विभिन्न पक्षों से उनका परिचय कराया जाता है। हिंदी केन्द्रित इन रचनात्मक गतिविधियों में स्वयं की सहभागिता से वे हिंदी क्षेत्र में बोली जाने वाली हिंदी भाषा एवं उच्चारण का प्रत्यक्ष परिचय प्राप्त कर पाते हैं। डॉ. संगीता जौहरी, कुलसचिव, रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय ने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय ने कला, साहित्य, संस्कृति तथा हिंदी एवं भारतीय भाषाओं के संरक्षण एवं संवर्धन के वैश्विक मंच 'विश्व रंग' के माध्यम से विश्व के 70 से अधिक देशों में हिंदी और भारतीय भाषाओं के लिए महत्वपूर्ण कार्य संपादित किए हैं। हमारे विश्वविद्यालय के सभी उत्कृष्ट केंद्र कला, साहित्य, संस्कृति का कार्य हिंदी भाषा, स्थानीय बोलियों और भारतीय भाषाओं की समृद्धि के प्रति कृतसंकल्पित होकर कार्य कर रहें है।

तिरछी नज़र से

टैक्स देने वाले की आत्मकथा

एक ईमानदार करदाता की जीवन-गाथा – जो जीते जी शहीद हो गया

प्रभात दत्त झा

मेरा नाम रामावतार वर्मा है। मैं ईमानदारी से टैक्स भरता हूँ। आप यह पढ़कर हँस रहे हैं- मैं समझता हूँ। इस देश में ईमानदारी से टैक्स भरने वाला आदमी या तो बहुत बड़ा मूर्ख होता है, या बहुत बड़ा साहसी। मैं दोनों हूँ।

मेरी कहानी 1 अप्रैल से शुरू होती है - और हर वर्ष उसी दिन मुझे यह अहसास होता है कि यह तारीख यूँ ही नहीं चुनी गई। जब ITR भरने बैठता हूँ, तो लगता है जैसे किसी ने मेरे नाम पर अप्रैल फूल मनाया हो। फॉर्म खोलता हूँ-उसमें इतने कॉलम हैं जितने मेरे पड़ोसी के पाँच बेटे, तीन बेटियाँ और सात नाते-रिश्तेदार मिलकर नहीं बनाते।एक ईमानदार करदाता की पहचान यह है कि वह टैक्स भरते समय रोता है, और टैक्स न भरने वाला टीवी पर मुस्कुराता हुआ नज़र आता है।

Section 80C, 80D, 80G, 80CCC, 80CCD - यह धाराएँ हैं या किसी हाईवे के किलोमीटर? CA साहब बोलेः यहाँ बचत होती है। मैंने पूछाः कितनी? बोलेः डेढ़ लाख तक निवेश कर सकते हो। मैंने कहाः निवेश के लिए पैसे चाहिए, वो कहाँ से आएँ जब आधा वेतन ञ्जष्ठस् में गया? CA साहब ने आँखें झुकाई और बोलेः आपसे बड़ी फ़ीस नहीं लूँगा।

मेरे पड़ोसी चंदूलाल जी हैं। तीन दुकानें हैं, नकद में व्यापार है, बेटे की शादी में सोने के जेवर थे जो एक छोटी सुनार की दुकान को शर्मिंदा कर दें। उनका टैक्स? बोलेः भाई, हमारा तो घर का खर्च ही इतना है कि बचत होती नहीं। मैं सोचता हूँः घर का खर्च बीएमडब्लू कार, विदेश-यात्रा और इनवर्टर-बैटरी के नाम पर होता है, लेकिन टैक्स तब भी शून्य। यह चमत्कार है या कला? शायद दोनों।

एक बार मैंने नोटिस पाया। Income Tax विभाग ने पूछाः आपने इस वर्ष FD तोड़ी, उसका स्रोत बताइए। मैंने बतायाः यह मेरी माँ के गहने बेचकर मिले पैसे थे जो मेडिकल इमरजेंसी में काम आए। जवाब आयाः प्रमाण प्रस्तुत करें। मैं प्रमाण ढूँढने गया तो अस्पताल ने कहाः रसीद छह महीने से पुरानी है, अब नहीं मिलेगी। मैं समझ गयाः ईमानदारी एक ऐसा जुर्म है जिसकी सज़ा मिलती ज़रूर है, बस समय अलग-अलग होता है।

सरकार कहती हैः टैक्स दो, देश बनाओ। मैं टैक्स देता हूँ। सड़क टूटी है- मरम्मत नहीं। अस्पताल में दवा नहीं- ख़रीदनी पड़ती है। बच्चे के स्कूल में टीचर नहीं - ट्यूशन लगानी पड़ती है। यानी एक बार टैक्स में दिया, दूसरी बार बाज़ार में दिया। मैं बिना किसी शिकायत के देश का निर्माण कर रहा हूँ - ज़मीन पर भी, कागज़ पर भी।

एक दिन मैं मर जाऊँगा। ITR नहीं भर पाऊँगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि Income Tax विभाग उस वर्ष भी एक नोटिस भेजेगाः श्री रामावतार वर्मा, आपने इस वर्ष ITR दाखिल नहीं किया। कारण बताएँ। उस नोटिस का जवाब मेरी आत्मा देगीः महोदय, मृत्यु प्रमाण-पत्र संलग्न है। कृपया अब छोड़ें।

हाँ, मैं जानता हूँ - विभाग उस मृत्यु प्रमाण-पत्र पर भी सवाल उठाएगा कि यह मूल है या स्व-प्रमाणित? फिर मेरे बच्चों को वार्षिकी (Annuity) दिखानी पड़ेगी कि पिताजी सच में मरे थे या सिर्फ टैक्स बचाने के लिए गायब हो गए।

ईमानदार करदाता – वह प्राणी जो देश के लिए जीता है, देश के लिए टैक्स देता है, और देश उसे अकेला छोड़ देता है।

किताबी ज्ञान से आगे

कौशल आधारित शिक्षा क्यों है समय की सबसे बड़ी ज़रूरत

रविकान्त ठाकुर

आज का युवा किताबों की दुनिया में खोया रहता है, लेकिन जीवन की असली मंच पर उतरते ही अक्सर ठिठक जाता है। डिग्री हाथ में है, पर आत्मविश्वास और दक्षता का अभाव। क्या सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान भविष्य की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए काफी है? आज का युग तेज़ परिवर्तन, तकनीकी क्रांति और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का है। ऐसे में कौशल आधारित शिक्षा न केवल समय की मांग है, बल्कि युवाओं को सशक्त बनाने का सबसे प्रभावी माध्यम भी।

स्वामी विवेकानन्द जी ने कहा था- 'शिक्षा मनुष्य में निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है।' यह कथन स्पष्ट बताता है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी भरना नहीं, बल्कि व्यक्ति की छिपी हुई क्षमताओं को जागृत करना है। महात्मा गांधी की 'नई तालीम' भी शिक्षा को श्रम, कौशल और वास्तविक जीवन से जोड़ने पर आधारित थी।

पारंपरिक शिक्षा की सीमाएं

पारंपरिक व्यवस्था में लंबे समय तक रट्टा मारकर परीक्षा पास करना मुख्य लक्ष्य रहा है। नतीजा? डिग्री तो मिल जाती है, लेकिन रोजगार पाने, समस्याओं का समाधान करने, टीम में काम करने या नई परिस्थितियों में खुद को ढालने जैसे जरूरी कौशल नहीं विकसित होते। उद्योग और समाज ऐसे युवाओं की तलाश में हैं जो ज्ञान के साथ-साथ व्यावहारिक दक्षता, रचनात्मकता और आत्मविश्वास भी रखते हों।

सरकारी PLFS 2025 के अनुसार शिक्षित युवाओं (माध्यमिक और उच्चतर) में बेरोजगारी दर 6.5 प्रतिशत के आसपास है, जो यह स्पष्ट करता है कि केवल डिग्री पर्याप्त नहीं।

कौशल शिक्षा का असली रूप

कौशल आधारित शिक्षा विद्यार्थियों को परियोजना कार्य, प्रयोग, इंटर्नशिप और वास्तविक जीवन के अनुभवों के जरिए सीखने का अवसर देती है। इसमें समस्या-समाधान, आलोचनात्मक चिंतन, संचार कौशल, टीमवर्क, नेतृत्व क्षमता, डिजिटल साक्षरता और उद्यमिता जैसे गुण विकसित होते हैं। जब कोई छात्र खुद करके सीखता है, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और ज्ञान जीवन में उतरने लगता है।

डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने युवाओं को याद दिलाया था- 'सीखना रचनात्मकता देता है, रचनात्मकता सोच की ओर ले जाती है, सोच ज्ञान देती है और ज्ञान आपको महान बनाता है।' आज के डिजिटल युग में AI, कोडिंग, डिज़ाइन थिंकिंग, डेटा विश्लेषण और वित्तीय साक्षरता जैसे कौशल भविष्य की नौकरियों के लिए अनिवार्य हो गए हैं।

विश्व के सफल अनुभव

दुनिया कई देशों से सीख सकती है। जर्मनी का डुअल सिस्टम (स्कूल+कंपनी में व्यावहारिक प्रशिक्षण) इसका बेहतरीन उदाहरण है। वहां युवा सैद्धांतिक ज्ञान के साथ-साथ कार्यस्थल पर सीधे अनुभव प्राप्त करते हैं, जिससे शिक्षा और रोजगार के बीच का अंतर कम हो जाता है।

भारत में सकारात्मक बदलाव

भारत की नई शिक्षा नीति (NEP 2020) इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। यह स्कूल स्तर से ही व्यावसायिक शिक्षा, अनुभवात्मक अधिगम, स्थानीय कला-शिल्प और इंटर्नशिप को प्रोत्साहन देती है। इस नीति के तहत अब स्कूल स्तर से व्यावसायिक शिक्षा और अनुभवात्मक अधिगम को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे हजारों स्कूलों में व्यावहारिक प्रशिक्षण शुरू हो चुका है। इसका लक्ष्य ऐसे नागरिक तैयार करना है जो ज्ञान को सही जगह उपयोग कर सकें और सामाजिक उत्तरदायित्व भी निभाएं।

रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा था- 'उच्चतम शिक्षा वह है जो हमें केवल जानकारी नहीं देती, बल्कि हमारे जीवन को सम्पूर्ण अस्तित्व के साथ सामंजस्य स्थापित करना सिखाती है।' कौशल शिक्षा ठीक यही काम करती है- ज्ञान को जीवन से जोड़ती है।

कौशल शिक्षा के दूरगामी लाभ

यह शिक्षा केवल रोजगार तक सीमित नहीं। यह आत्मनिर्भरता, निरंतर सीखने की आदत, नवाचार और आत्मविश्वास पैदा करती है। ऐसा युवा न केवल खुद के लिए अवसर पैदा करता है, बल्कि परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में भी सक्रिय भूमिका निभाता है।

प्राचीन भारत में भी शिक्षा केवल किताबी नहीं थी। गुरुकुलों में व्यावहारिक ज्ञान, शिल्प और जीवन कौशल पर जोर दिया जाता था। आज हमें उसी परंपरा को आधुनिक संदर्भ में अपनाना है।

'मैंने सुना, भूल गया। मैंने देखा, याद रहा। मैंने किया, तो सीख गया।'

यही कौशल आधारित शिक्षा का मूल मंत्र है। अंत में इन पंक्तियों के साथ कहना चाहूंगाः-

'देश के शिल्पी हैं हम,
हमें मूर्तियाँ यूं गढ़ लाना है ।
करे जो तन मन पावन,
सबल वही परिवर्तन लाना है॥'

शिक्षाविद,अंतरराष्ट्रीय प्रारंभिक शिक्षा विशेषज्ञ,
प्रेरक वक्ता एवं राष्ट्रीय प्रशिक्षक

रिटायरमेंट की उम्र तय हो सकती है, सीखने की नहीं

60+ के बाद भी सीखते रहिए, क्योंकि सक्रिय दिमाग ही खुशहाल और स्वस्थ जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है ।'सरकारी नियम आपकी नौकरी की सेवानिवृत्ति तय कर सकते हैं, लेकिन आपके ज्ञान, जिज्ञासा और सपनों की कोई रिटायरमेंट नहीं होती।'

सुलक्षणा जिल्लारे

समाज में लंबे समय से यह धारणा रही है कि 58 या 60 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति का सीखने और आगे बढ़ने का समय समाप्त हो जाता है। लेकिन आज का युग इस सोच को पूरी तरह बदल रहा है। बढ़ती जीवन-प्रत्याशा, डिजिटल तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और ऑनलाइन शिक्षा ने यह साबित कर दिया है कि सीखने की कोई निश्चित उम्र नहीं होती। वास्तव में, जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, वह उम्र से पहले ही स्वयं को सीमित कर लेता है।

रिटायरमेंट केवल नौकरी का अंत है, जीवन का नहीं। यह वह समय है जब वर्षों के अनुभव के साथ नई चीज़ें सीखकर व्यक्ति अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। आज अनेक वरिष्ठ नागरिक डिजिटल उद्यमी बन रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, पुस्तकें लिख रहे हैं, नई भाषाएँ सीख रहे हैं और समाज के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका अनुभव है, और नई तकनीक उस अनुभव को नई उड़ान देती है।

दिमाग भी शरीर की तरह अभ्यास चाहता है

जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नियमित व्यायाम आवश्यक है, उसी प्रकार मस्तिष्क को सक्रिय रखने के लिए निरंतर सीखना जरूरी है। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारा मस्तिष्क जीवनभर नई जानकारी ग्रहण करने और उसके अनुसार स्वयं को ढालने की क्षमता रखता है। इस क्षमता को न्यूरोप्लास्टिसिटी (Neuroplasticity) कहा जाता है।

जब हम कोई नई भाषा सीखते हैं, संगीत का अभ्यास करते हैं, कंप्यूटर चलाना सीखते हैं, नई तकनीक समझते हैं या किसी रचनात्मक कार्य में भाग लेते हैं, तब मस्तिष्क में नए न्यूरल कनेक्शन बनते हैं। इससे स्मरण शक्ति, ध्यान, समस्या-समाधान की क्षमता और रचनात्मक सोच को बढ़ावा मिलता है।

कई वैज्ञानिक अध्ययनों से यह संकेत मिला है कि मानसिक रूप से सक्रिय जीवनशैली उम्र बढ़ने के साथ संज्ञानात्मक क्षमताओं को बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकती है। सीखना तनाव कम करने, आत्मविश्वास बढ़ाने और जीवन में उद्देश्य का भाव बनाए रखने में भी सहायक होता है।

डिजिटल युग में अनुभव सबसे बड़ी ताकत है

आज AI और नई तकनीकें तेजी से

60+ के बाद क्या सीखें?

आज विकल्पों की कोई कमी नहीं है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो हर वरिष्ठ नागरिक के लिए उपयोगी हो सकते हैं :-

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डिजिटल तकनीक की मूल बातें
- कंप्यूटर, स्मार्टफोन और इंटरनेट का बेहतर उपयोग
- ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और साइबर सुरक्षा
- नई भाषा सीखना
- लेखन, ब्लॉगिंग या पुस्तक लेखन
- चित्रकला, संगीत, फोटोग्राफी और हस्तशिल्प
- योग, ध्यान और स्वास्थ्य प्रबंधन
- वित्तीय योजना और निवेश की समझ
- सार्वजनिक वक्तृत्व, शिक्षण और मेंटरिंग
- सोशल मीडिया का सुरक्षित और सकारात्मक उपयोग

इनमें से कोई भी कौशल केवल समय बिताने का साधन नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और सामाजिक जुड़ाव का माध्यम भी बन सकता है।

दुनिया बदल रही हैं। कई लोग सोचते हैं कि यह केवल युवाओं के लिए है, जबकि सच्चाई यह है कि अनुभव और तकनीक का मेल सबसे प्रभावशाली परिणाम देता है। जिस व्यक्ति के पास जीवन का अनुभव है, यदि वह नई तकनीक भी सीख ले, तो वह परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत बन सकता है।

दादा-दादी और नाना-नानी यदि डिजिटल माध्यमों से जुड़ते हैं, तो वे अपने बच्चों और पोते-पोतियों से बेहतर संवाद स्थापित कर सकते हैं। वे ऑनलाइन शिक्षा, बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक गतिविधियों का लाभ भी अधिक सहजता से उठा सकते हैं।

सीखना केवल करियर के लिए नहीं, जीवन के लिए है

बहुत से लोग सोचते हैं कि सीखने का उद्देश्य केवल नौकरी पाना है। लेकिन वास्तविकता यह है कि सीखना जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने का माध्यम है। जब व्यक्ति नई चीज़ें सीखता है, तो उसमें जिज्ञासा बनी रहती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और हर दिन एक नया उद्देश्य मिलता है। यही उद्देश्य मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी मजबूत करता है।

आज ही शुरुआत करें

सीखने के लिए किसी बड़े संस्थान या महंगे कोर्स की आवश्यकता नहीं है। प्रतिदिन 30 मिनट पढ़ना, कोई ऑनलाइन वीडियो देखना, नई तकनीक का अभ्यास करना, पुस्तकालय जाना, किसी कार्यशाला में भाग लेना या किसी नई कला को सीखना–ये छोटे-छोटे कदम भविष्य में बड़ा बदलाव ला सकते हैं।

हर नया कौशल केवल ज्ञान नहीं बढ़ाता, बल्कि यह संदेश भी देता है कि इंसान तब तक जवान है, जब तक उसकी जिज्ञासा जीवित है।

निष्कर्ष :

रिटायरमेंट जीवन की गति को धीमा करने का नहीं, बल्कि नई दिशा देने का अवसर है। यह वह समय है जब अनुभव, समय और जिज्ञासा मिलकर एक नई पहचान बना सकते हैं।

आइए, हम उम्र की सीमाओं को नहीं, अपनी संभावनाओं को पहचानें। क्योंकि आने वाला समय उन्हीं का है, जो हर उम्र में सीखना, बदलना और आगे बढ़ना जानते हैं।

(सुलक्षणा जिल्लारे - रंगों, पत्थरों और धागों से अनोखी कृतियां तैयार करना। विशिष्ट कला प्रतिभा और बच्चों को कला का प्रशिक्षण)

प्रेरक पंक्तियाँ

'उम्र सिर्फकैलेंडर के पन्ने बदलती है, सीखना इंसान की पहचान बदल देता है।'

'रिटायरमेंट नौकरी से होता है, जिज्ञासा से नहीं।'

'जब तक सीखना जारी है, तब तक जीवन आगे बढ़ता रहता है।'

'ज्ञान वह निवेश है, जिसका लाभ जीवनभर मिलता है।'

पुस्तकालयों को फिर से आबाद करने की जरूरत

'किताबें जगाती हैं बंद अलमारी के शीशे से बड़ी हसरत से ताकतीं हैं'......मशहूर गीतकार गुलजार के गाने की यह पंक्तियां आज के बदलते हुए डिजिटल दौर में एकदम सटीक बैठती हैं आज इंटरनेट सोशल मीडिया और चंद् सेकंड की रील ने किताबों से हमारे लगाव को , एक एहसास को, पाने की खुशबू और किताबों में रखे उन छोटे-छोटे लम्हों को हमसे दूर कर दिया है। सूचनाएं अब हमारी उंगलियों पर नाचती हैं , परंतु यही विषय वस्तु मानव में धैर्य की कमी को विकसित कर रही है । ऐसे में समाज में (reading culture) पठन संस्कृति को पुनः जीवित करने के लिए ग्रंथालयों में जान भरना आवश्यक है।

हमारे छत्तीसगढ़ की न्यायधानी और शिक्षण केंद्र के रूप में पहचान बनाने वाला 'हमर बिलासपुर' में बदलाव स्पष्ट रूप से नजर आता है । बिलासपुर न केवल स्कूली और उच्च शिक्षा के लिए जाना जाता है बल्कि यहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का भी गढ बन गया है हमारे शहर के प्रमुख शिक्षण संस्थान जैसे गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, अटल बिहारी वाजपेई विश्वविद्यालय साथ ही कुछ प्राइवेट संस्थान जैसे डॉक्टर सी. वी.रमन विश्वविद्यालय और जरहाभाटा स्थित शासकीय जिला ग्रंथालय साथ ही कई शासकीय स्कूलों और प्राइवेट स्कूलो के ग्रंथालय भी उनके जीवंत उदाहरण है।

यदि हम उपरोक्त संस्थाओं एवं पुस्तकालयों की स्थिति पर एक नजर डालें तो हकीकत और ही निकलकर सामने आती है । एक अनुमान के मुताबिक बिलासपुर के इन शैक्षणिक पुस्तकालयों और शहरों के निजी स्टडी जोन में प्रतिदिन 2500 से अधिक युवा अपनी पढ़ाई के लिए पहुंचते हैं। शासकीय ग्रंथालय की बात करें तो यहां सीजीपीएससी व्यापम और बैंकिंग की तैयारी करने वाले छात्र-छात्राओं की उपस्थिति कुल पाठकों का लगभग 75 से 80त्न होती हैं।

पुस्तकालयों के डेटा बताते हैं कि जहां एक और साहित्य दर्शन इतिहास और सामान्य ज्ञान की मूल किताबों को पढ़ने के लिए ले जाने वाले पाठकों की संख्या में पिछले 5 वर्षों से 30% की गिरावट आई है वही ई जनरल्स वाई-फाई और डिजिटल लाइब्रेरी और शांत सिटिंग स्पेस की मांग में 50त्न से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है।

परीक्षा केंद्रित पढ़ाई बनाम ज्ञान का विस्तार :-

इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि आज का युवा केवल परीक्षा में पास होने के लिए ही ग्रंथालयों का उपयोग करता है। ज्ञान की विस्तार और पढ़ने की ललक धीरे-धीरे विलुप्त हो रही है ।आज की युवा पीढ़ी में पन्नों को पलटने नोट्स बनाने और मौलिक चिंतन करने की प्रवृत्ति कम हो गई है।

समाधान :- समाज और युवा पीढ़ी को बौद्धिक रूप से रचनात्मक विकास करने के लिए पढ़ने को परीक्षा में पास होने के दबाव से मुक्त करना होगा-

मोहल्ला स्तर पर वाचनालय :- शहर के विभिन्न वार्डों में नगर निगम के सहयोग से कम्युनिटी रीडिंग रूम शुरू किया जाना चाहिए जहां बच्चों और बुजुर्गों की पसंद की किताबों का संग्रह और समाचार पत्र की व्यवस्था भी हो । इस तरह एक स्थान पर युवाओं बच्चों और बुजुर्गों का संगम और आपसी वार्तालाप भी बढ़ेगा।

पुस्तकालय का जीवंत होना :- पहले पुस्तकालयों में पुस्तकों के संग्रह पर ही जोर दिया जाता था परंतु आज के दौर में इसे रोचक बनाने के लिए वैचारिक विमर्श पुस्तक समीक्षा जैसे केंद्र भी होने चाहिए ।

बचपन से आदत :- स्कूलों में लाइब्रेरी पीरियड को अनिवार्य और मनोरंजक बनाया जाना चाहिए ।उसे, होमवर्क करने या इनकंप्लीट वर्क को करने या दंड देने के तौर पर पुस्तकालय भेजने का जरिया नहीं बनना चाहिए बल्कि उन्हें नई-नई किताबों के साथ दोस्ती कैसे की जाए इस तरफविचार करते हुए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए और उन्हें किताबों के साथ रूबरू करना चाहिए।

किताबें सिर्फ ज्ञान नहीं देती वे संवेदनशील और जागरूक नागरिक बनाती हैं । जब तक हम किताबों से दोबारा नाता नहीं जोड़ते तब तक एक वैचारिक रूप से मजबूत समाज का निर्माण संभव नहीं है ।इंटरनेट के इस शोर में हमें किताबों के मोहक सुकून को पहचानने की आवश्यकता है और अपने शहर के पुस्तकालय को फिर से जीवंत करने की आवश्यकता है।

डॉ. निधि गुप्ता
एम. लिब. (न्यायिक मामलों की विशेषज्ञ आम आदमी और मध्यम वर्ग की समस्याओं का पूरी संवेदनशीलता

स्वत्वाधिकारी अभिव्यक्ति प्रकाशन प्रा.लि.के लिए प्रकाशक सुभाष मिश्रा के लिए, मुद्रक नरेश मंगतानी द्वारा श्रीबालाजी प्रिंटर्स, 21 एच, इंडस्ट्रियल एरिया, गोविंदपुरा, भोपाल म.प्र.से मुदित एवं एसआर-4-102, रुद्राक्ष पार्क फेस-1 बावड़ियां कलां, भोपाल, म.प्र.से प्रकाशित, प्रधान संपादक -सुभाष मिश्रा, सलाहकार संपादक- भालचन्द्र जोशी, स्थानीय संपादक- अंशुमन खरे आरएनआई रजि. नं.RNI.NO.MPHIN/ 25/A3544 पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार।